बांग्लादेश-पाकिस्तान सम्बन्ध

(एम.फिल. उपाधि हेतु आंशिक अनिवार्यताओं की पूर्ति के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में समर्पित लघु शोध-प्रबन्ध)

शोध-निर्देशक
डॉ. एस.आर. चक्रवर्ती

शोध-छात्र
प्रणय शर्मा

- दक्षिण, मध्य, दक्षिण-पूर्व एशियाई
और दक्षिण पश्चिम प्रशांत
अध्ययन केन्द्र,
अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली-110067

1998

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY
NEW DELHI-110067

दक्षिण, मध्य, दक्षिण स्वं पूर्व एशिया
स्वं दक्षिण पश्चिम प्रशांत अध्ययन केन्द्र,
अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान

21, जुलाई 1998

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रणय शर्मा द्वारा 'बांग्लादेश-पाकिस्तान सम्बन्ध' शीर्षक से प्रस्तुत लघु शोध-प्रबन्ध में प्रयुक्त सामग्री का इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय में इसके पूर्व किसी भी प्रदेय उपाधि के लिए उपयोग नहीं किया गया है ।

यह इनकी सर्वथा मौलिक कृति है ।

डा. स. आर. चक्रवर्ती
(शोध-निर्देशक)

प्रो. इन्द्रनाथ मुखर्जी
(अध्यक्ष)
CHAIRPERSON
Centre for South, Central South East
Asia and South West Pac
School of International Studies
Jawaharlal Nehru University
New Delhi-110067

GRAM : JAYENU TEL. : 610 7676, 616 7557 TELEX : 031-73167 JNU IN FAX : 91-011-6165886

प्राक्कथन

बांग्लादेश एवं पाकिस्तान का नाम लेते ही ग्लोब पर से केवल दो देशों की स्थिति उभर कर हमारे मानस पटल पर नहीं आती, बल्कि इन दोनों देशों की सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक परम्पराओं, साहित्यिक उन्नति एवं भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में इन क्षेत्रों की विशिष्ट पहचान हमारे समक्ष प्रकट होती है ।

'बांग्लादेश-पाकिस्तान सम्बन्ध' विषय पर यह शोध-प्रबन्ध लिखने के लिए अध्ययन करते हुए कई बार ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अपने पूर्वजों के पारिवारिक झगड़ों एवं नासमझी का अध्ययन कर रहा हूं ।

'विविधता सहित एकता' को चरितार्थ करने वाले इस महा-कुटुम्ब के सदस्यों में अपनी महत्वाकांक्षा एवं बाह्य औपनिवेशिक शक्तियों केस्वार्थ प्रेरित हस्तक्षेप से जो मनमुटाव पैदा हुए, वे इतनेबढ़ गये कि मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ की ये पंक्तियां उनका सही दिग्दर्शन कराती हैं --

'हम के ठहरे अजनबी, इतनी मुलाकातों के बाद
फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद ।'

ये पंक्तियां बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के जनमानस की आपसी शत्रुता के संदर्भ में ही कही गई थीं ।

उपमहाद्वीप के इन दो प्रमुख देशों के सम्बन्धों में इस सामाजिक बिखराव केसाथ 'धर्म' के आधार पर छलावा एवं अकिंचनता के बावजूद असहयोग की विडंबनापूर्ण स्थितियां उभर कर सामने आई हैं ।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में इन दोनों देशों के द्विपक्षीय सम्बन्धों के विविध पक्षों को कुल पाँच अध्यायों में विवेचित किया गया है । प्रारम्भ में 'सामान्य-परिचय' देते हुए विषय पर एक विहंगम दृष्टिपात किया गया है । उसके पश्चात् प्रथम अध्याय में बांग्लादेश-पाकिस्तान सम्बन्धों के निर्धारक तत्त्व, द्वितीय अध्याय में द्विपक्षीय विवादों के क्षेत्र, तृतीय अध्याय में राजनीतिक पक्ष, चतुर्थ में आर्थिक सम्बन्ध तथा पंचम अध्याय में सार-संकलन प्रस्तुत किया गया है । इसके पश्चात् एक परिशिष्ट एवं संदर्भ-ग्रंथ सूची दी गई है ।

अपने इस शोध-प्रबन्ध में मैंने जिन लेखकों एवं विचारकों के लेखों एवं पुस्तकों में दिये गये विचारों की मदद ली है, उनका मैं तहेदिल से शुक्रगुजार हूं ।

मैं डॉ. एस. आर. चक्रवर्ती का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने उदार निर्देशन एवं प्रेरणा से मेरा हौसला बढ़ाया ।

इसके अलावा दक्षिण एशिया अध्ययन विभाग के समस्त गुरुजनों प्रो. एस. डी. मुनी, प्रो. मुचकुन्द दुबे, प्रो. कलिम बहादुर, प्रो. आई. एन. मुखर्जी, डॉ. उमा सिंह, डॉ. एम पी. लामा, डॉ. के. लाभ, डॉ. नैन्सी जैटली एवं डॉ. पी. सहदेवन को भी साधुवाद देता हूं जिन्होंने समय समय पर मेरा मार्गदर्शन किया । अपने विचारों से मुझे लाभान्वित कराने तथा इस विषय पर भेंटवार्ता का अवसर देने के लिए मैं प्रो. वीरेन्द्र नारायण का आभारी हूं ।

यह सूची बहुत लम्बी है, जिसमें कई पुस्तकालयों का भी सहयोग रहा । किन्तु यह सब कुछ मेरे माता-पिता एवं अन्य परिजनों के सतत् सहयोग एवं स्नेह के बिना संभव नहीं था ।

पुष्पा
प्रणय

21.7.98

विषयानुक्रमणिका

	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन	अ - आ
सामान्य-परिचय	क - च
अध्याय - प्रथम बांग्लादेश-पाकिस्तान संबंध : निर्धारक तत्व	1 - 23
अध्याय - द्वितीय बांग्लादेश-पाकिस्तान संबंध : विवाद के क्षेत्र	24 - 44
अध्याय - तृतीय बांग्लादेश-पाकिस्तान संबंध : राजनीतिक संबंध	45 - 60
अध्याय - चतुर्थ बांग्लादेश-पाकिस्तान संबंध : आर्थिक संबंध	61 - 77
अध्याय - पंचम निष्कर्ष	78 - 82
परिशिष्ट	83 - 86
संदर्भ ग्रन्थ सूची	87 - 98

सामान्य परिचय

बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के द्विपक्षीय सम्बन्धों का दक्षिण एशिया के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थान है । दोनों देशों के सम्बन्धों के वर्तमान स्वरूप की पृष्ठभूमि में बीसवीं सदी के भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास निहित है । भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगति एवं उसके समानान्तर मुस्लिम लीग की साम्प्रदायिक राजनीति के साथ ही बंगाल एवं पंजाब की अलग पहचान बन चुकी थी । 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत 'लाहौर प्रस्ताव' जिसने पाकिस्तान की मांग की नींव रखी, पंजाबी नेता सिकंदर हयात खान द्वारा निर्मित प्रारूप पर आधारित था तथा इसे बंगाली नेता फजलुल हक ने पेश किया । इस प्रस्ताव में एकीकृत मुस्लिम राज्य के बारे में कुछ नहीं था, बल्कि भौगोलिक रूप से जुड़े हुए एवं संख्यात्मक दृष्टि से मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों, जैसे भारत के उत्तर-पश्चिमी एवं पूर्वी क्षेत्र, का समूह बना कर उन्हें 'स्वतंत्र राज्य' बनाये जाने की मांग की गई जिनकी घटक इकाइयां स्वायत्त एवं सार्वभौम हों । इस प्रस्ताव में अस्पष्टता, द्वैधता एवं दोहरे अर्थों के लिए पर्याप्त जगह थी । किन्तु 'द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त' के आधार पर मुसलमानों के लिए अलग राज्य 'पाकिस्तान' के निर्माण की मुस्लिम लीग की राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लीग की अंग्रेज सरकार से निकटता, मुसलमानों में हिन्दुओं के भावी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक वर्चस्ववाद के भयों के आरोपण एवं 1946-47 की व्यापक हिंसक घटनाओं के कारण सफल रही ।

धर्म को एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित कर जिस पाकिस्तान का निर्माण हुआ, उसकी सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं भौगोलिक विद्रूपताएं

1947 के तुरन्त बाद ही सामने आने लगीं । जिन्ना ने स्वतंत्र पाकिस्तान में दिये गये अपने प्रथम भाषण में पाकिस्तान को 'सेक्यूलर स्टेट' के रूप में निरूपित किया । पाकिस्तान के पूर्वी एवं पश्चिमी भागों में धर्म के अलावा और कोई समानता नहीं थी । धर्म को राजनीतिक मंत्र के रूप में किस तरह इस्तेमाल किया गया, यह इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि संयुक्त प्रान्त एवं बिहार से पाकिस्तान के पूर्वी एवं पश्चिमी भागों में गये पाकिस्तान की विचारधारा के समर्थक मुसलमानों को पाकिस्तान के गरिमापूर्ण नागरिकों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया तथा यह स्थिति आज तक भी बनी हुई है ।

1947 से 1970 के मध्य पूर्वी भाग पर पश्चिमी पाकिस्तान का औपनिवेशिक शासन रहा । पंजाब एवं पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त के लीगी नेताओं के प्रभुत्व के कारण ही 'सरकारी तंत्र' की स्थापना पश्चिमी पाकिस्तान में की गई, जबकि जनसंख्या पूर्वी भाग की अधिक थी । सुहरावर्दी, फजलुल हक, भासानी, मुजीबुर्रहमान आदि बंगाली नेताओं को किसी न किसी रूप में पाकिस्तान का शत्रु समझा गया ।

शुरुआती वर्षों में ही जिन्ना एवं लियाकत अली की मृत्यु के बाद पाकिस्तान में नेतृत्व का संकट उभरा जिसने राजनीतिक व्यवस्था पर सेना की पकड़ को मजबूत बनाया । पाकिस्तान में परम्परागत उदार लोकतंत्र के पश्चिमी मॉडल की अस्वीकृति के पीछे शासक अभिजन की सत्ताच्युति का भय रहा जिसके सूत्र पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित सैनिक तंत्र के हाथों में थे । इसलिए लोकतन्त्र की स्थापना, भाषा के प्रश्न एवं राष्ट्रीय राजस्व के समुचित वितरण को लेकर दोनों भागों में मतभेद तीव्र होते गये । पूर्वी पाकिस्तान में उर्दू के वर्चस्व के खिलाफ बंगाली को राजभाषा का दर्जा दिलाने हेतु 1952 में सफल भाषा-आन्दोलन चला एवं सरकार द्वारा बंगाली को राजभाषा के रूप में मान्यता दिये जाने पर ही समाप्त हुआ ।

पूर्वी बंगाल ने केवल 1905-1912 के संक्षिप्त काल में ही स्वायत्तता का अनुभव किया था । पूर्वी पाकिस्तान बनने के बाद प्रभावी प्रान्तीय सरकार के निर्माण की प्रक्रिया काफी धीमी रही । पूर्वी पाकिस्तान के तकरीबन प्रत्येक वरिष्ठ प्रशासनिक पद पर कोई गैर-बंगाली मुसलमान ही था । विकास संसाधनों में भी उन्हें उचित हिस्सा नहीं मिला । उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन आदि पर पश्चिमी पाकिस्तानियों ने अपना नियंत्रण रखा एवं पूर्वी भाग के व्यापार-आधिक्य का उपयोग पश्चिमी पाकिस्तान के औद्योगीकरण हेतु किया ।

1960 के दशक में सीमित नागरिक अधिकारों, अर्द्ध प्रतिनिधि संस्थाओं की पुनर्स्थापना एवं पूर्वी भाग की सांस्कृतिक एवं जातीय पहचान पर बार-बार आघातों ने अयूब विरोधी स्वर को बल दिया । 1965 के भारत-पाक युद्ध में अलग-थलग पड़ने के बाद बंगाली नेताओं ने शेख मुजीब के नेतृत्व में पूर्वी भाग की स्वायत्तता एवं राजत्व अधिकारों के रूप में छः-सूत्री कार्यक्रम पेश किया । सैनिक शासकों एवं जमाते-इस्लामी ने इसे साम्य-वाद एवं हिन्दू समर्थकों की प्रेरणा बता कर अस्वीकृत कर दिया । उल्लेखनीय है कि यह छः सूत्री स्वायत्ता प्रस्ताव 1940 के 'लाहौर-प्रस्ताव' की अवामी लीग की व्याख्या पर आधारित था जिसमें स्वायत्तता की बात कही गई थी ।

अयूब के सत्तावाद के विरोध में 1962 से चल रहे छात्र-आंदोलन ने 1969 तक अन्य धाराओं को अपने में समेटते हुए व्यापक एवं हिंसक आंदोलन का रूप ले लिया । अयूब खान को सत्ता याह्या खान को हस्तांतरित करनी पड़ी । 1970 के चुनावों के बाद मार्शल लॉ शासक याह्या खान द्वारा अवामी लीग को सत्ता हस्तांतरण से मना करने पर रक्तरंजित गृह युद्ध शुरू हुआ जो 'मुक्ति-युद्ध' में रूपान्तरित हो गया । उपमहाद्वीप की तत्कालीन परिस्थितियों में भारत के अनिवार्य हस्तक्षेप से 16 दिसम्बर 1971 को स्वतंत्र एवं सम्प्रभु राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश अस्तित्व में आया ।

1970-71 का यह संकट मूलत: अभिजन वर्ग में 'शक्ति के लिए संघर्ष' था जिसे डेविड ईस्टन के शब्दों में 'सत्ता के आधिकारिक वितरण' में बाधा का परिणाम कहा जा सकता है । इससे 'राष्ट्र-निर्माण' एवं 'राज्य-निर्माण' की प्रक्रियायें खंडित हो गईं । 1960 के दशक में कुछ विद्वानों जैसे - शिल्स (1962), जेनोविट्ज (1964) एवं ल्युसियन पाई (1962) ने यह संकल्पना रखी थी कि तृतीय विश्व के देशों में राजनीतिक अभिजन की अपेक्षा सैनिक अभिजन राष्ट्रीय एकीकरण की स्थापना में अधिक सक्षम हो सकते हैं किन्तु पाकिस्तान के संदर्भ में यह अवधारणा विफल साबित हुई ।

नवजात राष्ट्र बांग्लादेश की विदेश नीति स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों - समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, विश्व शांति एवं लोकतांत्रिक आन्दोलनों को समर्थन से प्रेरित थी । 1975 तक मुजीब के शासन काल में बांग्लादेश की भारत-सोवियत धुरी से निकटता स्वाभाविक थी । मुजीब-भुट्टो कटुता से इस दौर के आरंभ में बांग्लादेश-पाकिस्तान प्रत्यक्षत: नजदीक नहीं आ सके किन्तु बांग्लादेश के 'इस्लामी सम्मेलन संगठन' (ओ. आई. सी.) के सदस्य बनने एवं 22 फरवरी 1974 को पाकिस्तान द्वारा उसे मान्यता प्रदान किये जाने से तनाव में कमी के साथ ही सम्बन्धों में भावी सुधार का आधार बना । इसी क्रम में अप्रैल 1974 में भारत-पाकिस्तान-बांग्लादेश के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार बांग्लादेश ने 195 पाकिस्तानी युद्ध अपराधी सैनिक अधिकारियों पर मुकदमे का विचार त्याग कर उन्हें 'राज्य-क्षमा' प्रदान की ।

15 अगस्त 1975 को शेख मुजीब की हत्या के उपरान्त बांग्लादेश-पाकिस्तान सम्बन्धों में नये युग का सूत्रपात माना जा सकता है । पाकिस्तान ने ही सर्वप्रथम नई सरकार को मान्यता दी । इसमें दोनों ही देशों में सैनिक शासन के निहितार्थों को स्पष्टत: अनुभव किया जा सकता है ।

बांग्लादेश एवं पाकिस्तान को भारत से अपनी द्विपक्षीय समस्याओं के कारण भी निकट आने का अवसर मिलता है । यह दक्षिण एशिया में भारत की विशाल उपस्थिति एवं उपमहाद्वीप से बाहर तक रणनीतिक दृष्टि के कारण स्वाभाविक भी है । किन्तु बांग्लादेश एवं पाकिस्तान दोनों ही भारत की उपेक्षा करने की स्थिति में नहीं आ सकते ।

दोनों देशों के बीच 1971 से ही चली आ रही बांग्लादेशी 'बिहारियों' की पाकिस्तान वापसी एवं संयुक्त पाकिस्तान की परि-सम्पत्तियों एवं देयताओं के बंटवारे' की समस्याएं अभी तक हल नहीं हो सकी हैं । इसमें पाकिस्तान की घरेलू राजनीति का गणित एवं आर्थिक वित्तीय समस्याएं प्रमुख बाधाएं रही हैं । परन्तु ये विवाद कभी भी दोनों देशों के वृहद् हितों में बाधक नहीं बने एवं इनके बावजूद दोनों पक्ष 1975 से ही विभिन्न क्षेत्रों में निकटता एवं पारस्परिक लाभ पर आधारित सम्बन्धों हेतु प्रयासरत रहे हैं । दोनों देशों ने क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य हित के मुद्दों पर समन्वित नीतियां अपनाईं । अफगानिस्तान संकट, बोस्निया, पश्चिम एशिया की समस्याएं एवं ओ. आई. सी. की बैठकें इसका उदाहरण हैं ।

विभिन्न सरकारों के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र में सहयोग हेतु कई समझौते सम्पन्न हुए जिसमें द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि, निवेश संवर्द्धन, एवं कृषि तकनीक के क्षेत्र में आदान-प्रदान प्रमुख हैं । सार्क के अंतर्गत वरीयता व्यापार व्यवस्था (साप्टा) ने दोनों देशों को व्यापार में प्रभावी वृद्धि का अवसर उपलब्ध करवाया है । जनवरी 1998 के मध्य में ढाका में आयोजित भारत-पाकिस्तान-बांग्ला देश के त्रिपक्षीय आर्थिक शिखर सम्मेलन से इस पक्ष का महत्व उजागर हुआ है ।

1990 के बाद बांग्लादेश एवं पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनी जड़ें जमाने की कोशिश में है । बांग्लादेश में 1996 के चुनावों

के बाद अवामी लीग पुन: सत्ता में आया तथा शेख हसीना के अब तक के शासन में ऐसे कोई पाकिस्तान-विरोधी स्वर मुखरित नहीं हुए जिनकी आशंकाएं व्यक्त की जा रही थीं । यह उल्लेखनीय है कि मई 1998 में भारत एवं पाकिस्तान द्वारा परमाणु विस्फोट किये जाने के बाद बांग्लादेशी सरकार ने संयत रुख अपनाया एवं अन्य पश्चिमी देशों के विपरीत 'दक्षिण एशिया की शांति एवं स्थिरता' के लिए इन दोनों देशों के बीच वार्ता पर बल दिया । इसी क्रम में शेख हसीना ने जून माह में भारत एवं पाकिस्तान की यात्राएं कीं । निश्चय ही जहां एक ओर पाकिस्तान के नवीन नेतृत्व ने 1971 की दु:खद घटनाओं के प्रति परिवर्तित एवं लचीला रुख अपनाया है, वहीं बांग्लादेश दक्षिण एशिया में अपनी सक्रिय भूमिका की आत्मस्वीकृति कर रहा है जो दोनों देशों को भविष्य में और नजदीक ला सकते हैं ।

-

प्रथम अध्याय

बांग्लादेश-पाकिस्तान सम्बन्ध : निर्धारक तत्व

दो देशों के मध्य सम्बन्धों के समग्र परिवृत्यों को द्विपक्षवाद के नाम से जाना जाता है । द्विपक्षवाद दो देशों के पारस्परिक सम्बन्धों को प्रभावित करने वाले मुद्दों एवं विषयों का समाधान समानता एवंआपसी लाभ के आधार पर, किसी तृतीय पक्ष के हस्तक्षेप के बिना या उन्हें अन्तर्राष्ट्रीयकृत कर जटिल बनाये बिना, किये जाने पर बल देता है । सामान्य हितों की पूर्ति एवं विद्यमान विवादों के निस्तारण हेतु फेन्विक ने 'समझौता-वार्ता' के महत्व को रेखांकित किया है । यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप से तृतीय पक्ष की महत्ता से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की एक प्रसिद्ध उक्ति है कि राज्यों के बीच सम्बन्धों में मित्रता या शत्रुता स्थायी नहीं होती, बल्कि राष्ट्रीय हित ही स्थायी होते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं घरेलू परिदृश्य के सापेक्ष प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षार्थ समुचित रण-नीति एवं दावपेंचों का चयन करता है । मॉरगेन्थो के अनुसार घरेलू राज-नीति की तरह ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का तात्कालिक उद्देश्य चाहे कुछ भी हो 'शक्ति' हमेशा अन्तिम ध्येय होता है । इसी आधार पर अधिकाधिक शक्ति का संग्रहण प्रत्येक देश की विदेश नीति को प्रभावित करता है एवं द्विपक्षीय सम्बन्ध भी इससे निर्धारित होते हैं ।

इन सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक अवधारणाओं की दृष्टि से देखा जाये तो दक्षिण एशियाई देशों में द्विपक्षीय मुद्दों को अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की प्रवृत्ति रही है तथा यह बात बांग्लादेश एवं पाकिस्तान पर भी लागू होती है । बांग्लादेश एवं पाकिस्तान दोनों ही बड़ी शक्तियां नहीं हैं, इसलिए वैश्विक स्तर पर उनके द्विपक्षीय सम्बन्धों का महत्व सीमित है, किन्तु दक्षिण एशिया क्षेत्र की राजनीति में इनका महत्व बढ़ जाता है । द्विपक्षवाद एवं दक्षिण एशिया की राजनीतिक परि-स्थितियों के आधार पर बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के सम्बन्धों के निर्धारक कारकों पर विचार किया जा सकता है ।

इस आधार पर दोनों देशों की ऐतिहासिक विरासतें तथा उन का सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव, भौगोलिक अवस्थिति में दूरियों की भूमिका, सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों एवं प्रतिमानों के साथ-साथ दोनों देशों के इस्लामी स्वरूप के फलितार्थ एवं तद्जन्य सहयोग के अवसर, प्रकट-अप्रकट रूप में तृतीय पक्ष (भारत, चीन या अन्य) की भूमिका, सहयोग एवं संघर्ष के मुद्दों के अलावा दीर्घकालीन स्थायित्व की दृष्टि से एक-दूसरे की आंतरिक बाध्यताओं का यथार्थबोध, आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा एवं परिपूरकताओं के क्षेत्रों, नेतृत्व एवं राजनीतिक दलों की विचारधारा, निहित स्वार्थ एवं दूसरे देश के प्रति दृष्टिकोण आदि कारकों का समावेश इनके द्विपक्षीय सम्बन्धों के निर्धारकों में किया जा सकता है ।

भौगोलिक-आर्थिक कारक

भूगोल एवं अर्थशास्त्र किसी भी देश की विदेश नीति के मूल आधारों का निर्धारण करते हैं । ये किसी भी देश के दीर्घकालीन हितों से संबंधित हैं । इसके अंतर्गत संबंधित देशों के आकार, अवस्थिति, जनसंख्या के स्वरूप, भू-राजनैतिक महत्व, आर्थिक संसाधनों की स्थिति एवं बाह्य निर्भरता की मात्रा आदि को सम्मिलित किया जा सकता है ।

(अ) अवस्थिति एवं आकार

बांग्लादेश एवं पाकिस्तान दोनों ही मध्यम या छोटे आकार के देश हैं जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 148393 वर्ग किलोमीटर एवं 803943 वर्ग किलोमीटर है ।[1] दोनों के बीच भारत की विशाल उपस्थिति उन्हें

---

1. दि स्टेट्समैन ईयरबुक, 134 वां संस्करण, 1997-98, पृ० 187

एक-दूसरे से बहुत दूर (लगभग 1600 किलोमीटर) कर देती है । इतनी दूरी के कारण 1971 से पूर्व भी बांग्लादेश पाकिस्तान के पूर्वी भाग के रूप में उपेक्षित तथा तीन ओर से भारतीय भू-प्रदेश (2583 कि.मी. - सीमारेखा) से घिरे होने के कारण अपनी सुरक्षा के प्रति आशंकित रहा। चीन-तिब्बत सीमा से निकटता, दक्षिण पूर्व में म्यांमार से साझा सीमा (233 कि.मी.) तथा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के कारण भू-राजनीतिक दृष्टि से बांग्लादेश की अवस्थिति महत्वपूर्ण है किन्तु पाकिस्तान से अत्यधिक दूरी के कारण द्विपक्षीय सम्बन्धों में इसकी सकारात्मक भूमिका नहीं के बराबर है । इसलिए दोनों के बीच कोई भौगोलिक विवाद भी नहीं है । पूर्वी पाकिस्तान के भारत से नदी जल या सीमा विवाद अब भारत-बांग्लादेश विवादों में रूपान्तरित हो गये । कौटिल्य के पर-राष्ट्र नीति विषयक मण्डल सिद्धान्त को लागू करते हुए कहा जा सकता है कि भारत से उनके द्विपक्षीय विवाद उन्हें मित्रता का अवसर प्रदान करते हैं । भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर कौटिल्य का मत है कि पड़ोसी राष्ट्र शत्रु एवं पड़ोसी का पड़ोसी मित्र (शत्रु का शत्रु होने के कारण) होता है ।

पाकिस्तान ने पश्चिमी एवं दक्षिण-पश्चिमी एशिया के मुस्लिम देशों से अपनी सम्बद्धता स्थापित करने की कोशिश की है, वहीं बांग्लादेश पूर्वी एवं उत्तर-पूर्वी भारत का ही एक घटक प्रतीत होता है । बांग्लादेश के पास गहरे जल के बंदरगाह की सुविधा होने के कारण वह पाकिस्तान से कराची बंदरगाह के जरिए समुद्री मार्ग से व्यापार करने की स्थिति में है तथा पाकिस्तान के जरिये मध्य एशिया तक बांग्ला देश की पहुंच बन सकती है ।[2] परन्तु अत्यधिक भौगोलिक दूरी के कारण परिवहन व्यय अधिक होता है जो बांग्लादेश-पाकिस्तान के मध्य व्यापार वृद्धि में प्रमुख बाधा है ।

---

1. प्रो. वीरेन्द्र नारायण से भेंटवार्ता पर आधारित । देखें - परिशिष्ट, पृ 84

(ब) जनांकिकीय स्वरूप

दक्षिण एशिया के सभी देश जनाधिक्य की समस्या से ग्रस्त हैं। बांग्लादेश में जन घनत्व 1991 की जनगणना के अनुसार 740 व्यक्ति प्रति वर्ग कि. मी. है जो कि विश्व में सर्वाधिक सघनता वाले क्षेत्रों में से है। जनसंख्या वृद्धि दर 2.4 प्रतिशत है।[3] वर्तमान में पाकिस्तान की कुल अनुमानित जनसंख्या 13 करोड़ से अधिक हो गई है। दोनों ही देशों में साक्षरता के न्यून स्तर, गरीबी, पिछड़ापन तथा कुपोषण उन्हें अपने संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के साथ ही इन क्षेत्रों में प्रगति हेतु द्विपक्षीय सहयोग को बाध्य करते हैं। सार्क के अंतर्गत भी विभिन्न समितियों के माध्यम से दोनों देश एक-दूसरे के अनुभवों से लाभ उठाने की स्थिति में हैं।

(स) आर्थिक कारक

सामाजिक-आर्थिक पुनर्निर्माण में घरेलू आर्थिक संसाधनों के साथ ही अन्य देशों से आर्थिक सम्बन्धों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बांग्लादेश एवं पाकिस्तान दोनों ही विकासशील औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था वाले, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर एवं संरचनात्मक सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत उदारीकरण की राह पर चल रहे देश हैं।

बांग्लादेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन केवल जुट एवं प्राकृतिक गैस हैं। खनिजों में लिग्नाइट, चूना-पत्थर एवं चाइना क्ले पाया जाता है। वहीं खनिज-तेल, कोयला एवं लोहे के लिए अन्य देशों पर निर्भर है। बाढ़, समुद्री तूफान एवं अकाल अक्सर प्राकृतिक संसाधनों का क्षय करते हैं। स्वाभाविक रूप से बांग्लादेश के आर्थिक सम्बन्ध भारत के साथ अधिक

---

3. दि स्टेट्समैन ईयरबुक, 134 वां संस्करण, 1997-98, पृ0 187

व्यापक है किन्तु वह पाकिस्तान को जूट, चाय, खालें, न्यूजप्रिंट आदि के निर्यात की स्थिति में है । दूसरी ओर पाकिस्तान जिसके भारत से आर्थिक सम्बन्ध नगण्य हैं, बांग्लादेश को कपास, गेहूं, सीमेंट, मशीनरी आदि निर्यात करने की स्थिति में है ।[4]

उल्लेखनीय है कि 1971 से पूर्व पाकिस्तानी शासकों की शोषक नीतियों के कारण पूर्वी भाग की आर्थिक प्रगति सम्भव नहीं थी । शेख मुजीब ने भी अपने 6-सूत्री कार्यक्रम में आर्थिक स्वायत्तता को महत्व दिया था । 1971 के बाद बांग्लादेश निर्माण से जहां पाकिस्तान के लिए प्राकृतिक संसाधनों का एक प्रमुख स्रोत हाथ से निकल गया, वहीं बांग्लादेश भी जर्जर अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण हेतु पाकिस्तान से सम्बन्धों में सुधार को प्रेरित हुआ । वर्तमान में दोनों ही देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं । बांग्ला देशी सरकार ने टका का कई बार अवमूल्यन किया है । वहीं मई 1998 के परमाणु विस्फोटों के बाद लगे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबन्धों के कारण पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है । ये सभी कारक इन दोनों देशों को व्यापार एवं निवेश में अधिक सहयोग के लिए अनुकूल अवसर प्रदान कर रहे हैं । दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा), जो सन् 2001 ईस्वी तक लागू किया जाना प्रस्तावित है, की दिशा में भी ये परिस्थितियां अपना योगदान कर सकती हैं क्योंकि भारत पर भी परमाणु विस्फोटों के कारण आर्थिक प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ।

---

4. अबु ताहिर सलाउद्दीन अहमद, 'बांग्लादेश-पाकिस्तान रिलेशन्स : एन इवोल्यूशन,' उद्धृत, इफ्तेखारुज्जमन एण्ड इम्तियाज अहमद (संपा.) 'बांग्लादेश एण्ड सार्क', ढाका, पृ0 195-197

ऐतिहासिक कारक

द्विपक्षीय संबंधों के निर्धारण में इतिहास का महत्व बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के संबंधों में विशेष रूप से है । नीतियां राष्ट्रीय नेतृत्व के वर्षों के अनुभव से विकसित विश्व दृष्टि का परिणाम होती हैं । बांग्लादेश एवं पाकिस्तान का साझा इतिहास है । पाकिस्तान के प्रति बांग्लादेश की नीति की जड़ें भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन तक जाती हैं । 1947 से 1956 में संविधान लागू होने तक इसे पूर्वी बंगाल के रूप में जाना गया ।

बंगाल एवं पंजाब की औपनिवेशिकरण के खिलाफ संघर्ष की लंबी परम्परा है एवं राष्ट्रीय आन्दोलन भी महाराष्ट्र के अलावा इन्हीं दो प्रान्तों में मुखर था । दोनों भागों की मुस्लिम जनता ने पाकिस्तान के लिए संघर्ष किया । 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी ढाका में हुई तथा उसमें ढाका के नवाब की महत्वपूर्ण भूमिका थी । ब्रिटिश साम्राज्य-वाद के विरुद्ध संघर्ष के कारण दोनों देश साम्राज्यवाद के दुष्परिणामों से परिचित रहे हैं ।

किन्तु बंगाली नेताओं के प्रति जिन्ना एवं तदन्तर पश्चिमी पाकिस्तान के दुराग्रह एवं पाकिस्तान के एक अंग के बावजूद पूर्वी भाग के शोषण ने जो विरासतें छोड़ीं, वे कड़वाहट भरी थीं । इसका प्रभाव अब भी दोनों देशों के सम्बन्धों पर नजर आता है । पूर्वी बंगाल के नेताओं ने यू. एस. ए. के नेतृत्व में सीएटो, सेन्टो आदि सैनिक गुटों में पाकिस्तान के शामिल होने का विरोध किया था ।[5] उनके मतानुसार यू. एस. ए. आदि की साम्राज्यवादी ताकतों के संरक्षण में ही पाकिस्तानी सैनिक तानाशाही संरक्षित थी ।

---

5. कमाल, हुसैन, 'बांग्लादेश सॉवेन्टी एण्ड इंडिपेंडेंट नॉन एलाइन्ड फॉरेन पॉलिसी', ऑस्ट्रेलियन आउटलुक, वॉ0 7, नं0 4 दिसम्बर, 1988, पृ0 69

1962 में पूर्वी पाक में उग्र छात्र-आन्दोलन शुरू हुआ (अयूब खान के सैनिक शासन के खिलाफ)। 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण अलग-थलग पड़ गया। राजनैतिक नौकरशाही एवं सैनिक नियन्त्रण पूर्णरूपेण पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में केन्द्रित हो गया। इस दौरान भारी असुरक्षा एवं रक्षा-विहीनता के बोध ने बंगाली नेताओं एवं युवाओं को पूर्वी बंगाल के राजनैतिक भविष्य को भिन्न दृष्टि से देखने को प्रेरित किया।

शैख मुजीब ने पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्तता एवं राजत्व अधिकारों के रूप में 6 सूत्री कार्यक्रम सहित एक वृहद मांग-सूची प्रस्तुत की। इसमें अन्य के अलावा अलग मुद्रा, स्वतन्त्र व्यापार नीति एवं पूर्वी पाकिस्तान के लिए स्वतन्त्र सैनिक बल के गठन की मांगें शामिल थीं। राजनैतिक आन्दोलन के समानान्तर ही छात्रों एवं उग्र समूहों के गुप्त आन्दोलन चले, जिनका उद्देश्य पूर्वी बंगाल की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। इन सब में अन्तर्संबंध थे। शैख मुजीब को षड्यन्त्र केस में फंसाने के प्रयासों ने इन्हें और उग्र बनाया।[6]

अयूब 6-सूत्री मांगों के राजनीतिक समाधान के वायदे से मुकर गये। 30 मार्च 1970 को जनरल याह्या खां ने 'विधिक रूपरेखा आदेश' लागू किया, जिसने राष्ट्रव्यापी चुनावों एवं नये संविधान निर्माण के आधार पर का काम किया। अक्टुबर-नवंबर 1970 में पूर्वी बंगाल के दक्षिणी भागों में समुद्री चक्रवातों से भारी तबाही मची। किंतु सरकार सहायता उपलब्ध कराने में विफल रही। इसे बंगालियों ने सैनिक शाही के अमानवीय व्यवहार के रूप में लिया। 1969 के आन्दोलन ने

---

6. जिल्लुर्रहमान, 'बांगलादेश एक्सपेरिमेंट विद् पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी', एशियन सर्वे, वॉ0 37, नं0 6, जून 1997, पृ0 575

भी मतदान व्यवहार को प्रभावित किया तथा अवामी लीग तथा उसके 6-सूत्री कार्यक्रम को अपूर्व एवं स्पष्ट विजय प्राप्त हुई । मुजीब एवं उनके दल को पूर्वी पाकिस्तान की 169 सीटों में से 167 सीटें प्राप्त हुईं (राष्ट्रीय एसेंब्ली में) जबकि जुल्फिकार अली भुट्टो की पी.पी.पी. को पश्चिमी पाकिस्तान की 144 में से 88 सीटें मिलीं ।

भुट्टो समर्थक सेना द्वारा 1 मार्च 1971 को प्रस्तावित नव-निर्वाचित संसद के उद्घाटन अधिवेशन को स्थगित कर दिया गया । 2 मार्च 1971 को शेख मुजीब की सहमति से छात्र नेताओं के एक गठबन्धन ने बांग्लादेश के रूप में पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी की घोषणा कर दी, जिसका नया राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गीत था ।

सरकारी अत्याचारों में सरकार विरोधी आन्दोलनों में भाग लेते सैंकड़ों छात्र मारे गये । अपनी लोकप्रियता के मद्देनजर शेख मुजीब ने व्यापक स्तर पर असहयोग एवं नागरिक अवज्ञा आन्दोलन शुरू किया एवं सैनिक शाही के कानूनों का उल्लंघन किया । निस्सन्देह इसे छात्रों, मजदूरों, व्यवसायियों के समूहों एवं सामान्य जनता का व्यापक समर्थन मिला ।

1971 के आरंभ में यह आन्दोलन 'मुक्ति-युद्ध' में रूपान्तरित हो गया । पूर्वी बंगाल के गवर्नर श्री याकूब खां ने सैनिक कार्यवाही से असहमति जताते हुए जनरल याह्या खान को कड़वे नतीजों की चेतावनी दी । किन्तु उन्हें पद से हटा कर जनरल टिक्का खान को नया गवर्नर नियुक्त किया गया । जनरल टिक्का खान के अधीन किये गये सैनिक अत्याचारों को लेफ्. ज. ए.ए. के नियाजी ने चंगेज खान एवं हलाकू के अत्याचारों से भी वीभत्स बताया । निरीह नागरिकों की नृशंस हत्या, व्यापक युद्ध अपराध, आजादी की पूर्व संध्या पर जानबूझ कर बुद्धिजीवियों की हत्या आदि घटनाओं ने बांग्लादेशी जनता के मानस में पाकिस्तान की शत्रुतापूर्ण छवि निरूपित कर दी ।

1971 के बाद भी 21 फरवरी को शहीद दिवस (भाषा-आंदोलन 1952 के शहीदों की याद में), 16 दिसम्बर को बांग्लादेश स्वतन्त्रता दिवस, शहीद बुद्धिजीवी दिवस (14 दिसम्बर) आदि अवसरों पर पाकिस्तान विरोधी भावनाएं मुखरित होती रहती हैं। 1971 में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के लिए बांग्लादेश की पाकिस्तान से क्षमायाचना की मांग के बाद इतिहास पुनः उभर कर सामने आ गया है। व्यापक रूप में देखने से बांग्लादेश-पाकिस्तान सम्बन्धों में घनिष्ठता के मार्ग में ऐतिहासिक विरासतें ही सबसे बड़ी बाधा हैं।[7]

इस्लामी कारक

धर्म ने कई बार राज्यों की राजनीति पर आधिपत्य रखा है तो कई बार उसका राज्यों द्वारा उपकरण के रूप में प्रयोग भी हुआ है। दोनों ही स्थितियों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के निर्धारण में धर्म ने अपनी भूमिका अदा की है।

बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के सम्बन्धों में इसका विशेष महत्व है क्योंकि धर्म को राष्ट्रीयता का आधार मानकर ही 1947 में उप-महाद्वीप का विभाजन हुआ। 1947 से पूर्व भी बंगाल में मुस्लिम प्रभाव था एवं पूर्वी भाग इस्लामी गणराज्य के निर्माण में पाकिस्तान का सहभागी था। पाकिस्तानी सरकार की इस्लामीकरण की नीति के प्रभाव भी इस पर पड़े। 1971 में बांग्लादेश निर्माण से यह सिद्धान्त निर्मूल सिद्ध हो गया कि धर्म राष्ट्रीयता का आधार हो सकता है। धर्म ने बांग्लादेश की राजनीति को दो तरह से प्रभावित किया --

सकारात्मक - व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म को महत्व एवं इस्लामी देशों से भ्रातृत्व।

---

7. प्रो. वीरेन्द्र नारायण से भेंटवार्ता पर आधारित, देखें - परिशिष्ट, पृ. 86

नकारात्मक - 'मुस्लिम-पाकिस्तान' एवं 'हिंदू-भारत' में
अन्तर पर बल देना ।

साथ ही बांग्लादेशी मुसलमानों की दोहरी पहचान रही है - बंगाली एवं मुस्लिम । जब बंगाली पहचान पर संकट हो तो हिंदू बंगालियों से नजदीकी बढ़ जाती है, जैसा कि बांग्लादेशी मुक्तियुद्ध के दौरान हुआ । मुस्लिम-पहचान पर संकट की स्थिति में पात्र के शेष मुसलमानों एवं मुस्लिम विश्व से समीपता बढ़ती है । मुजीब के शासन के अंतिम वर्षों एवं जियाउर्रहमान तथा जन. इरशाद के शासन काल में ऐसा ही हुआ । यहां तक कि 1990 के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भी मुस्लिम-विश्व से निकट सम्बन्धों को महत्व दिया । स्पष्ट है कि इससे पाकिस्तान से बांग्लादेश के सम्बन्धों में सुधार हुआ है ।

उल्लेखनीय है कि आवामी लीग का रुख शुरू से ही कट्टरवाद विरोधी रहा है । 1956 के संविधान में पाकिस्तान को इस्लामी गणराज्य घोषित किये जाने एवं कुरान की शिक्षाओं पर बल तथा 1962 के अयूब निर्मित संविधान में इस्लामी आदर्शों एवं मूल्यों के संवर्द्धन का समावेश किया गया । अवामी लीग ने 'इस्लाम खतरे में है' के नारे को राजनैतिक स्टंट बताया एवं धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता जतायी ।[8]

21 से 24 जनवरी 1951 के दौरान कराची में इस्लामी दर्शन के सभी संप्रदायों की बैठक में तय एक सिद्धान्त यह था कि सभी नागरिक कानून की सीमा में जीवन, सम्पत्ति, सम्मान, धर्म की आजादी एवं अवसर की समता प्राप्त करेंगे किन्तु व्यवहार में यह बात पाकिस्तानी समाज में लागू नहीं हो सकी एवं विशेष तौर से बंगालियों पर अमानवीय अत्याचार किये गये ।

---

8. सैयद सिराजुल इस्लाम, 'इस्लाम इन बांग्लादेश', दि इस्लामिक क्वार्टरली, वॉ. XLI, नं0 3, 1997

1971 के बाद बांग्लादेश ने अपने देश की मुस्लिम देशों से मान्यता एवं विकास कार्यों के लिए पेट्रो डालर जुटाने हेतु 'इस्लामी-कार्ड' का इस्तेमाल किया । शेख मुजीब लाहौर में आयोजित 'इस्लामिक देशों के संगठन' के सम्मेलन में भाग लेने गये एवं 1975 में 14 वें इस्लामी विदेश मन्त्री सम्मेलन का आयोजन ढाका में किया गया । शम्सुल बारी के अनुसार बांग्लादेश एवं पाकिस्तान ने एक-दूसरे को इस्लामी देशों के शिखर सम्मेलन के संदर्भ में मान्यता दी, जिस पर बांग्लादेश में खुशी व्यक्त की गई । ढाई वर्ष पहले की स्थिति को याद करने पर यह खुशी असंगत लग सकती है किन्तु भारत की क्षेत्रीय योजना के प्रति प्रचलित भय तथा इस्लामी भ्रातृत्व के प्रति बढ़ते लोकप्रिय समर्थन की दृष्टि से यह असंगत नहीं लगता ।[9]

अगस्त 1975 के विद्रोह के बाद बांग्लादेश में दक्षिणपंथी सरकार की स्थापना से इस्लाम की भूमिका में वृद्धि हुई । जियाउर्रहमान ने संविधान में संशोधन करके... 'सर्वशक्तिमान अल्लाह के नाम पर...' शब्दावली का समावेश कर दिया । समाजवाद की इस्लामी न्याय के संदर्भ में पुनर्व्याख्या ी तथा इस्लामी एकजुटता के आधार पर सम्बन्धों का निर्धारण किया ।

1975 में नई सरकार स्थापित होते ही पाकिस्तान ने 'मुस्लिम-बंगाल' की सहायतार्थ आगे आने में देर नहीं की एवं जहाजों में भर कर सहायता-सामग्री भेजी । दूसरी ओर सामन्ती देश सऊदी अरब ने शेख मुजीब की हत्या के बाद 'दूसरे सबसे बड़े मुस्लिम देश' बांग्लादेश की

---

9. ए.एफ.एम. शम्सुल बारी, 'इमेज एण्ड रिएलिटीज ऑफ बांग्लादेश - इंडिया रिलेशन्स', जर्नल ऑफ दि बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एण्ड इंटरनेशनल अफेयर्स, वॉ. 1, नं0 1, जनवरी 1975, ढाका, पृ0 45

स्वतन्त्रता एवं सम्प्रभुता की रक्षार्थ पूर्ण समर्थन देने में तुरन्त पहल की । जैसे कि बांग्लादेश ने 1975 में अचानक मुस्लिम स्वरूप ग्रहण किया हो ।

जियाउर्रहमान एवं इरशाद दोनों ही सैनिक शासकों ने बांग्लादेश में तथा उसी समय जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान में अपनी सत्ता की वैधता स्थापित करने हेतु धर्म का सहारा लिया एवं 'इस्लामीकरण कार्यक्रम' चलाये । इरशाद ने संविधान में 8 वाँ संशोधन कर इस्लाम को राजधर्म बनाया ।

6 दिसम्बर 1992 को भारत में बाबरी-मस्जिद का ढाँचा ढहाये जाने पर इन दोनों देशों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई । इनकी राष्ट्रीय एसेंबलियों द्वारा इसकी आलोचना की गई । इन देशों में रह रहे हिन्दू परिवारों पर अत्याचार किये गये । अत: भारत को घेरने हेतु भी इस्लाम का इस्तेमाल किया जाता है ।

इस प्रकार इस्लामी देशों के संगठन (ओ.आई.सी.) तथा धर्म पर आधारित राजनीति करने वाली आंतरिक ताकतों ने दोनों देशों को निकट आने का अवसर दिया किन्तु धार्मिक कारक के पीछे राजनैतिक उद्देश्य या राजनीतिक यथार्थ हमेशा प्रमुख प्रेरक शक्ति रहे जिसका विवेचन इसी शोध प्रबन्ध में अगले अध्यायों में किया गया है ।

आन्तरिक राजनीतिक बाध्यताओं का यथार्थ-बोध

किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप, नेतृत्व, राजनीतिक दलों की विचारधाराओं, कार्यक्रमों, विपक्ष की भूमिका, जनमत, निहित स्वार्थों का दूसरे देशों के प्रति दृष्टिकोण आदि की किसी दूसरे देश के साथ सम्बन्धों के निर्धारण में महती भूमिका है ।

स्वतन्त्रता के बाद बांग्लादेश में कई प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं आ चुकी हैं । कार्यपालिका के हाथों में शक्ति का असीम

केन्द्रीकरण, राज्य का स्कात्मक स्वरूप, कमजोर एवं अप्रासंगिक निर्वाचित प्रतिनिधि सभाएं, सशस्त्र बलों द्वारा चुनावों में धोखाधड़ी, दबाव समूहों का हिंसा एवं अवैधानिक कार्यवाहियों में लिप्त होना, प्रेस एवं मीडिया पर सरकारी नियन्त्रण तथा अप्रभावी न्यायपालिका वहां की राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं रही हैं।[10] न्यूनाधिक रूप में यही लक्षण पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में भी विद्यमान रहे हैं।

बांग्लादेश की राजनीतिक व्यवस्था पर पाकिस्तान के साथ संक्षिप्त किन्तु गहन अनुभवों का भी प्रभाव है जिसके विकास के चार प्रमुख चरण हैं। इसने दोनों देशों के सम्बन्धों को प्रभावित किया है।

प्रथम है शेख मुजीब का शासन काल, जिसकी तुलना 1947-1958 के बीच पाकिस्तानी शासन व्यवस्था से की जा सकती है। इसमें ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के अनुरूप शासन व्यवस्था स्थापित करने के प्रयास सफल नहीं हो सके एवं इसका स्वरूप व्यक्ति केन्द्रित एवं दमनात्मक होता गया। अवामी लीग राजनीतिक-आर्थिक संकटों से निपटने में असफल हो गई तथा जनवरी 1975 में संविधान संशोधन कर मुजीब ने इसे सत्तावादी, अध्यक्षात्मक एवं एकदलीय राज्य बना दिया।

द्वितीय चरण 1975 में शेख मुजीब की हत्या के बाद से शुरू हुआ। जियाउर्रहमान ने पाकिस्तान के अयूब मॉडल के आधार पर नौकरशाह-सैनिक-राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की। आर्थिक विकास के लिए भी जिया के आर्थिक प्रबन्धकों ने उपर्युक्त मॉडल को ही अपनाया। अवामी लीग के समाजवाद के स्थान पर तीव्र आर्थिक वृद्धि दर तथा नियंत्रित

---

10. स्टेनली ए. कोचेनेक, 'पेट्रन - क्लाइन्ट रिलेशन्स एण्ड बिज़नेस इन बांग्लादेश', न्यू देहली, सेज पब्लिकेशन्स, 1993, पृ0 51

निजी क्षेत्र युक्त मिश्रित-अर्थव्यवस्था अपनायी गयी । जिया ने सशस्त्र सेनाओं का तीव्र पुर्निर्माण एवं विस्तार किया । मुस्लिम लीग, नेशनल अवामी पार्टी, जमाइटेड पीपुल्स पार्टी एवं कई अन्य इस्लामोन्मुखी दलों को भी अपने पुनर्निर्माण का अवसर मिला । इससे प्रशासन एवं सेना में ऐसे तत्वों का भारी मात्रा में समावेश हुआ जो भारत विरोधी थे एवं जिनकी सहानुभूति पाकिस्तान के साथ थी । जियाउर्रहमान की सेना में कई उच्चाधिकारियों पर 15 अगस्त 1975 के सैनिक विद्रोह एवं शेख मुजीब की हत्या में लिप्त होने का आरोप था । आशंका व्यक्त की जाती है कि यह विद्रोह वाशिंगटन के आशीर्वाद से इस्लामाबाद एवं ढाका में रचे गये षड़यन्त्र का परिणाम था । अगस्त 1975 के दूसरे सप्ताह में जिस पाकिस्तानी 'व्यापार-प्रतिनिधि मंडल' ने ढाका की यात्रा की, उसमें सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारी भी थे । इन्होंने खाण्डेकर मुश्ताक अहमद तथा मेजर जनरल (से.नि.) एम. आई. करीम से भेंट की जिसके बारे में माना जाता है कि 14-15 अगस्त की रात्रि की घटनाओं को 'अंतिम-रूप' दिया गया ।

जियाउर्रहमान ने 1972 के संविधान में संशोधन कर राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की तथा वैधता प्राप्त करने के उद्देश्य से अवामी लीग विरोधी गुटों को मिला कर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का गठन किया ।

मई 1981 में जिया की हत्या के बाद बांग्लादेशी राजनीति में तृतीय चरण की शुरुआत हुई । 1982 से 1990 तक जनरल एच. एम. इरशाद के नेतृत्व में सैनिक वर्चस्व वाली सरकार रही जो पाकिस्तान में जनरल जिया उल हक के शासन से साम्य रखती थी ।[11] इरशाद ने धर्म

---

11. स्टेनली ए. कोचेनेक, 'पैट्रन-क्लाइण्ट रिलेशन्स एण्ड बिजनेस इन बांग्लादेश', न्यू देहली, सेज पब्लिकेशन्स, 1993, पृ० 53

को 'राज्य-नीति' का आधार बनाए रखने की घोषणा की । बांग्लादेश एवं पाकिस्तान दोनों ही देशों में सैनिक शासन तंत्र होने से शासक अभिजन के स्वार्थ एवं कार्य प्रणाली में समानताओं ने उन्हें नजदीक आने का अवसर दिया । इसे अफगानिस्तान, पश्चिमी एशिया, भारत एवं सार्क सम्बन्धी इन देशों की नीतियों में साम्यता के आधार पर समझा जा सकता है । पाकिस्तान की राजनीति में आर्मी, अमेरिका एवं अल्लाह (तीन - अ) की निर्णायक भूमिका मानी जाती है । सैनिक शासन के दौरान इस्लामीकरण कार्यक्रम भी दोनों ही देशों में चले ।

1990 के बाद के दशक में दोनों ही देशों की राजनीतिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक चरण की शुरुआत हुई । किन्तु राजनीतिक व्यवस्था के भावी स्वरूप पर सहमति के अभाव, प्रशासनिक अनुभव की कमी, एवं सैनिक प्रतिष्ठान के हस्तक्षेप की आशंकाएं बनी रहने से दोनों देशों के बीच सम्बद्धतापूर्ण द्विपक्षीय रिश्तों के निर्माण में प्रगति नहीं हो सकी है ।

नेतृत्व एवं राजनीतिक दलों की विचारधारा एवं सामाजीकरण का विदेश नीति में निर्णायक महत्व है । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के निर्णय-निर्माण सिद्धान्त (सेपिन, स्नाइडर एवं ब्रुक द्वारा प्रतिपादित) की मान्यताओं के अनुसार किसी भी देश के विदेश नीति सम्बन्धी निर्णयों की सही परिप्रेक्ष्य में व्याख्या के लिए निर्णयकर्ता नेतृत्व के मूल्यों तथा उस पर्यावरण को समझना अनिवार्य है जो उसे प्रभावित करते हैं । इनमें आंतरिक पर्यावरण (राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक) तथा अन्तर्राष्ट्रीय दबावों को शामिल किया जाता है ।

करिश्माई नेतृत्व को इन दबावों का कम सामना करना पड़ता है । बांग्लादेश में मुजीब एवं कुछ हद तक जियाउर्रहमान तथा पाकिस्तान में जिन्ना के बाद भुट्टो एवं जनरल जियाउल हक ने इस छवि का लाभ उठाया । किन्तु करिश्माई छवि भी निरन्तर बनी नहीं रह सकती ।

मुजीब एवं जुल्फिकार अली भुट्टो के व्यक्तिगत टकरावों के कारण प्रारंभ में पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों में सुधार नहीं हो सका । भुट्टो 1971 में अमेरिका की भूमिका से असंतुष्ट थे तथा उन्होंने अपने शासन काल में पश्चिमी देशों की आलोचना की तथा इस्लामी देशों से निकटता बढ़ायी । बांग्लादेश में जियाउर्रहमान के द्वारा 'इस्लामीकरण' तथा पश्चिमोन्मुख नीति के कारण पाकिस्तान से सम्बन्धों में घनिष्ठता आई । 1977 में जियाउर्रहमान की इस्लामाबाद यात्रा से दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग के विचार की शुरुआत हुई ।[12] नवें दशक में जन. इरशाद एवं जन. जियाउल हक के सैनिक नेतृत्व में जहां दोनों देशों की इस्लामी देशों एवं चीन सैनिकटता बनी रही, वहीं सार्क की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ ।

नेतृत्व का राजनीतिक दलों से घनिष्ठ सम्बन्ध है । दोनों ही देशों में उपमहाद्वीप के अन्य देशों की तरह व्यक्ति आधारित राजनीतिक दलों का प्रभाव है । 1949 में स्थापित अवामी लीग का झुकाव धार्मिक उदारता, भारत से निकट सम्बन्ध एवं लोकतन्त्र की ओर रहा है । इसीलिए 1971 से 1975 एवं 1996 के उपरान्त बांग्लादेशी शासक अभिजन का रुख भारत विरोधी नहीं रहा । बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एवं जन. इरशाद की जातीय पार्टी इस्लामी देशों एवं पाकिस्तान से निकट सम्बन्धों की समर्थक है । ये पार्टियाँ वर्तमान अवामी लीग सरकार पर भारत के साथ किये गये समझौतों के संदर्भ में बांग्लादेशी हितों को गिरवी रखने का आरोप लगाती रही है । बांग्लादेश की जनता में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों बी.एन.पी. एवं अवामी लीग

---

12. चक्रवर्ती, एस. आर., 'बांग्लादेश अंडर मुजीब, जिया एंड इरशाद', न्यू देहली, हर आनन्द पब्लिकेशन्स, 1995, पृ० 10

का लगभग बराबर प्रभाव है । 27 फरवरी 1991 को हुए जातीय संसद के चुनावों में दोनों दलों को मिले मतों का प्रतिशत लगभग समान था किन्तु जमाते इस्लामी एवं जातीय पार्टी की मदद से बी.एन.पी. नेता खालिदा जिया सरकार बनाने में सफल रहीं । बी.एन.पी. की विचारधारा 'अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली' की समर्थक रही है किन्तु इरशाद विरोधी आन्दोलन के दौरान इसमें परिवर्तन हुआ एवं संसदीय व्यवस्था के पक्ष में लोकप्रिय जनमत होने के कारण इसे अपना रुख बदलना पड़ा । अगस्त 1991 को पारित एक संविधान संशोधन विधेयक द्वारा 16 साल पुरानी अध्यक्षीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई । सितम्बर 1991 में हुए राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह में इसकी पुष्टि होने के बाद यह प्रावधान लागू हो गया ।

यह महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक दलों की सहमति ने इसमें निर्णायक भूमिका अदा की । पाकिस्तान में 1997 के चुनावों में नवाज़शरीफ़ की सरकार भारी बहुमत से बनी । 8 वें संविधान संशोधन के संसदीय व्यवस्था विरोधी तत्वों को खारिज करने के लिए लाये गये 13 वें संविधान संशोधन के प्रति पी.पी.पी. ने अपनी सहमति जतायी । तात्पर्य यह है कि दोनों ही देशों में राजनीतिक दलों ने एक ओर अपनी प्रत्यक्ष नीतियों द्वारा एवं दूसरी ओर राजनीतिक व्यवस्था में रूपान्तरण के माध्यम से बांग्लादेश-पाकिस्तान के द्विपक्षीय सम्बन्धों के निर्धारण में योगदान किया है । वर्तमान में दोनों देशों में सत्ताधारी दलों (बांग्लादेश में अवामी लीग एवं पाकिस्तान में मुस्लिम लीग - नवाज़) को लोकप्रिय समर्थन प्राप्त होनेसे वे द्विपक्षीय सम्बन्धों में सुधार की दिशा में साहसिक कदम उठाने को प्रेरित हुए हैं । उदाहरण के लिए नवाज़ शरीफ़ ने 1971 के घटनाक्रम को तत्कालीन पाकिस्तानी शासकों की गलती के रूप में स्वीकार किया जो किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की प्रथम स्वीकारोक्ति है । दूसरी ओर शेख हसीना ने जनवरी 1998 में भारत सहित पाकिस्तान एवं बांग्लादेश का

त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित कर दक्षिण एशिया मेंबांग्लादेश की बढ़ती सक्रियता का परिचय दिया ।

जनमत विदेश नीति के व्यापक सरकारों के साथ ही छोटे-छोटे मुद्दों पर भी सरकारों पर दबाव डालता है । प्रेस एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रसार के बाद किन्हीं मुद्दों पर बहुत शीघ्र जनमत तैयार होता है । द्विपक्षीय सम्बन्धों में दोनों देशों की जनता का एक-दूसरे के प्रति दृष्टिकोण एवं राजनीतिक प्रक्रिया में उसका प्रकटीकरण महत्व-पूर्ण भूमिका निभाता है ।[13] बांग्लादेश की जनता में जहाँ पाकिस्तान के अत्याचार सहन कर चुकी पीढ़ी के मन में पाकिस्तान से निकट सम्बन्धों के प्रति वितृष्णा है, वहीं इस्लाम से सहानुभूति रखने वाला जनमत पाकिस्तान से समीपता चाहता है । 1992 में भारत में बाबरी-मस्जिद ढांचा गिराये जाने पर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश की तीव्र प्रतिक्रिया इसी उग्र इस्लामी जनमत का परिणाम ही ।

स्वतन्त्रता के पश्चात् भी बांग्लादेश में व्यापक स्वतन्त्रता-आंदोलन का प्रभाव रहा जिसने सरकारों को परम्परागत नीतियों की पूर्ण उपेक्षा नहीं करने दी । 16 वर्ष तक सैनिक शासन के बावजूद लोगों में बची हुई जागरूक चेतना ने लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया ।

---

13. वीरेन्द्र नारायण, 'फॉरेन पॉलिसी ऑफ बांग्लादेश, इवोल्यूशन एण्ड प्रोस्पेक्ट्स', उद्धृत - चक्रवर्ती, एस. आर., 'फॉरेन पॉलिसी ऑफ बांग्लादेश', न्यू देहली, हर आनन्द पब्लिकेशन्स, 1994, पृ0 39

तृतीय पक्षों की भूमिका

द्विपक्षीय सम्बन्धों के सार तत्व को तृतीय-पक्ष अर्थात् अन्य देशों की प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भूमिका सदैव प्रभावित करती है । बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के सम्बन्धों के निर्धारण में भारत की निकट उपस्थिति एवं नीतियों का महत्वपूर्ण स्थान है । इसके अलावा चीन, रूस एवं यू. एस. ए. जैसी क्षेत्र बाह्य शक्तियां भी इन दोनों देशों के सम्बन्धों की प्रकृति पर अपनी नीतियों एवं हितों के अनुरूप प्रभाव डालती हैं ।

दक्षिण एशिया 'भारत-केन्द्रित' क्षेत्र है, जिसमें सार्क के सदस्य देशों की भौगोलिक सीमाएं केवल भारत से मिलती हैं । भारतीय शासक वर्ग भारत की उसके आकार, भू-राजनीतिक अवस्थिति, ऐतिहासिक अनुभव, विशाल अर्थव्यवस्था एवं शक्ति संभाव्यता के अनुरूप वैश्विक भूमिका के संदर्भ में प्रयास करता रहा है ।[14] इसे पड़ौसी देश 'वास्तविक' या 'कल्पित' भय के रूप में निरूपित करते हैं ।

पाकिस्तान अपने जन्म से ही 'पहचान के संकट' से ग्रस्त है तथा उसके अस्तित्व का औचित्य ही 'भारत विरोध' के आधार पर सिद्ध होता है । 1947 के बाद से लोकतांत्रिक या सैनिक जो भी नेतृत्व रहा, अपनी समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने एवं वोट बैंक की राजनीति के लिए भारत विरोध का सहारा लिया । पाकिस्तान की नीति इस संदर्भ में भारत के अन्य पड़ोसियों से द्विपक्षीय विवादों का लाभ उठाकर उन्हें भारत के विरुद्ध लामबंद करने की रही है ।

---

14. इफतेखारुज्जमन, 'डिआर्मामेंट इन साउथ एशिया : इश्यूज एण्ड इम्पेडिमेंट्स', उद्धृत - एमाजुद्दीन अहमद एण्ड अबुल कलाम (सम्पा.), 'बांग्लादेश, साउथ एशिया एण्ड दि वर्ल्ड', ढाका, ऐकेडमिक पब्लिशर्स, 1992, पृ0 274-275

जहां तक बांग्लादेश का प्रश्न है, भारत की मदद के बिना उसकी आजादी संभव नहीं थी, यद्यपि इसमें निहित भारतीय हितों को भी नकारा नहीं जा सकता । किन्तु विजय का उल्लास थमते ही बांग्लादेशियों को भारत की `क्षेत्रीय संरचना योजना` का अहसास हुआ जिसमें बांग्लादेश भारत पर निर्भर ही रह सकता था । बांग्लादेश में कई दबाव गुटों ने भारत से 10 कि.मी. सीमा तक मुक्त व्यापार समझौते को थोपा हुआ कहना शुरू कर दिया ।

1972 में हस्ताक्षरित `शांति एवं मैत्री संधि` ने बांग्लादेशी मनस् में भय के तत्वों का बीजारोपण किया । इसके विदेश नीति, रक्षा, अर्थव्यवस्था सम्बन्धी प्रावधानों ने इस नये राज्य के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत की पहुंच सुनिश्चित कर दी एवं बांग्लादेश की स्वतन्त्र निर्णय-क्षमता को सीमित कर दिया । इसी प्रकार 1974 में भारत द्वारा परमाणु-विस्फोट, सिक्किम का भारत में विलय, फरक्का-विवाद, न्यू मूर द्वीप विवाद, विवादित अन्तःक्षेत्र (तीन बीघा), सीमा पर बाड़ लगाने, चकमा शरणार्थियों की समस्या आदि के चलते शांतिपूर्ण सीमा के आश्वासन को सतही माना गया जिसका दावा मित्रता सन्धि में था ।[15] यद्यपि इन मुद्दों पर प्रेस एवं मीडिया का भारत-विरोधी रुख खुले रूप में था, किन्तु आधिकारिक प्रतिक्रियाएं `गंभीर` परन्तु सचेत सरोकार लिए हुए थीं ।[16]

TH-7436

---

15. मौदूद अहमद, `एरा ऑफ शेख मुजीबुर्रहमान`, ढाका, युनिवर्सिटी प्रेस लिमिटेड, 1983, पृ0 186
16. शेल्टन कोडीकारा, `स्ट्रेटेजिक फेक्टर्स इन इन्टरस्टेट रिलेशन्स इन साउथ एशिया`, कैनबरा पेपर्स ऑन स्ट्रेटेजी एण्ड डिफेंस, नं0 19, कैनबरा, 1979, पृ0 34

DISS
V,44XV;1944X^N9
152N8

भारत से समस्याओं के कारण बांग्लादेश एवं पाकिस्तान की समान प्रवृत्ति एवं मनोवृत्ति कई बार दृष्टिगोचर हुई है । शेख मुजीब की हत्या के उपरान्त भारत के प्रभाव को कम करने के लिए पाकिस्तान से निकट सम्बन्ध ही बांग्लादेशी शासकों को उचित विकल्प लगा । इसे एक 'ऐतिहासिक-चक्र' का पूरा होना कह सकते हैं कि जिस भारत ने पाकिस्तान के औपनिवेशिक शिकंजे से बांग्लादेश को मुक्त कराया, वही भारत से भय के कारण पाकिस्तान से निकटता को बाध्य हुआ ।

बांग्लादेश में बाढ़, सूखा या तूफान के लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है । दूसरी ओर 1996 के चुनावों के समय भी भारत को एक मुद्दा बनाया गया । बेगम जिया ने 25 वर्ष पुरानी भारत बांग्लादेश मैत्री संधि को समाप्त करने का वादा किया । (इस सन्धि की अवधि 1997 में समाप्त हो गई)

बांग्लादेशी एवं पाकिस्तानी सैनिक शासकों का सत्ता में आने का प्रमुख आधार ही जहाँ भारत विरोध था, वहीं चीन एवं यू.एस.ए. से निकट सम्बन्धों पर बल दिया गया । चीन ने पाकिस्तान से निकट सम्बन्धों से जुड़ी बाध्यता के कारण 'कथित भारतीय विस्तारवाद' एवं 'सोवियत समाजवादी साम्राज्यवाद' के विरुद्ध 'साम्राज्यवादी अमेरिका' से हाथ मिलाया ।[17] 1975 के बाद शीत युद्ध का दक्षिण एशिया में जो प्रभाव पड़ा, उसमें पाकिस्तान एवं बांग्लादेश का पश्चिम की ओर झुकाव स्पष्ट नजर आता है । चीन का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश को भारत-विरोधी खेमे में लाना था तथा तत्कालीन बांग्लादेशी शासकों की प्रवृत्ति इसके अनुकूल थी । चीन से सैनिक सहायता एवं हथियारों की आपूर्ति, आर्थिक संपदाओं

---

17. वीरेन्द्र नारायण, 'फॉरेन पॉलिसी ऑफ बांग्लादेश', जयपुर, आलेख पब्लिशर्स, 1987, पृ0 115

के निर्माण एवं तकनीकी क्षेत्र में सहायता मिली । वर्तमान में भी चीन `भारत को घेरने` की नीति के तहत `युआन कूटनीति` का इस्तेमाल कर रहा है तथा बांग्लादेश एवं पाकिस्तान को आर्थिक-सैनिक सहायता जारी रखे हुए है । जुलाई 1998 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की चीन यात्रा के दौरान दक्षिण एशिया में शांति एवं स्थिरता के लिए चीन की भूमिका स्वीकार किये जाने से चीन के इरादों को और बल मिल सकता है ।

किन्तु बांग्लादेश एवं पाकिस्तान मिलकर भी भारत को प्रति-संतुलित करने की स्थिति में नहीं आ सकते तथा बांग्लादेश के नये नेतृत्व (अवामी लीग) को इस बात का बेहतर अहसास है । भारत से घिरे होने एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के कारण भारत से तनावपूर्ण सम्बन्ध कभी भी बांग्लादेश के हित में नहीं हो सकते ।[18] पाकिस्तान को अपनी अर्थ-व्यवस्था के उत्थान के लिए भी भारत से व्यापार बढ़ाना ही पड़ेगा ।

---

18. प्रो. वीरेन्द्र नारायण से भेंटवार्ता पर आधारित, देखें - परिशिष्ट, पृ. 83

अध्याय : द्वितीय

बांग्लादेश-पाकिस्तान सम्बन्ध : विवाद के क्षेत्र

बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के द्विपक्षीय सम्बन्धों के निर्धारक कारकों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि समग्र रूप में दोनों के मध्य सम्बन्धों में बड़े तनावों की अनुपस्थिति रही है एवं पारस्परिक हितों को अधिक महत्व देने का प्रयास किया गया है । किन्तु बांग्लादेश के उद्भव के समय से ही दो मुद्दों ने उनके निकट सम्बन्धों में बाधा पहुंचाई है । ये मुद्दे हैं : 'उर्दू भाषी बिहारी मुसलमानों (बेसहारा पाकिस्तानियों) की बांग्लादेश से स्वदेशवापसी' तथा 'परिसम्पत्तियों एवं आर्थिक देयताओं का बँटवारा' । साथ ही 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना द्वारा बांग्लादेशी अवाम पर किये गये अत्याचारों के लिए 'क्षमा-याचना' की बांग्लादेश की मांग का मुद्दा भी सुर्खियों में रहा है ।

बांग्लादेश में 'बेसहारा पाकिस्तानी'

1947 में भारत के विभाजन के समय पूर्वी पाकिस्तान जाने वालों में उर्दू भाषी बिहारी मुसलमान बड़ी संख्या में थे । इन्हें 'गैर-बंगाली', 'गैर स्थानीय', 'बिहारी' आदि नामों से जाना गया ।[1] 23 साल के पाकिस्तानी शासन के दौरान भी ये समाज की मुख्यधारा में शामिल नहीं हुए । 1971 के मुक्ति-युद्ध में भी पाकिस्तान के विभाजन के विरोधी होने के कारण इनकी सहानुभूति पाकिस्तानी सेना के साथ रही । इनमें से कुछ, जिन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों के रूप में आत्मसमर्पण किया, पाकिस्तान जाने में सफल रहे ।

16 दिसम्बर 1971 को बांग्लादेश की आजादी के समय वहाँ कुल लगभग 10 लाख बिहारी थे । युद्ध समाप्ति पर आदान-प्रदान में

---

1. दिलारा चौधरी, 'बांग्लादेश एण्ड दि साउथ एशियन इंटरनेशनल सिस्टम', ढाका ऐकेडमिक पब्लिशर्स, 1992, पृ0 296

171,000 बंगालियों के बदले 170,000 बिहारी पाकिस्तान लौटे तथा लगभग 18000 अपने बूते पर अनिश्चित भविष्य के साथ पाकिस्तान गये । शेष को बांग्लादेश में रहने का विकल्प दिया गया जिसके तहत आधे से अधिक बिहारियों ने बांग्लादेश की नागरिकता स्वीकार कर ली । कुल 500,000 लोगों ने पाकिस्तान जाने का विकल्प चुनते हुए रेडक्रॉस की अन्तर्राष्ट्रीय समिति (आई.सी.आर.सी.) में अपना पंजीकरण करवाया । इस विशेष समूह को ही 'बेसहारा पाकिस्तानी' कहा जाता है तथा इसी के अनुरूप 'बेसहारा पाकिस्तानी पुनर्वापसी महासमिति' का गठन किया गया ।

प्रारंभिक वर्षों में पाकिस्तानी सरकार एवं प्रेस ने गैर-बंगालियों से सहानुभूति व्यक्त करते हुए बांग्लादेश सरकार पर पाशविकता का आरोप लगाया तथा बिहारियों की दुर्दशा को 'प्रथम व्यवस्था का नरसंहार' के रूप में दुष्प्रचारित किया । इसके बावजूद इस काल में पाकिस्तान उन्हें स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था । जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत सहित किसी अन्य देश में बसाने का सुझाव दिया । शुरुआत में ही बिहारियों का अनिश्चित भविष्य पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी के इस वक्तव्य से स्पष्ट हो गया कि 'हमें उनसे क्या लेना-देना है ? हमारी अपनी समस्याएं हैं और वैसे भी वे भारतीय शरणार्थी हैं ।'[2] पाकिस्तान की यह रणनीति उपमहाद्वीप की इस यथार्थ राजनीति के अनुरूप ही थी जिसमें लाखों लोगों का प्यादों के रूप में इस्तेमाल किया गया ।[3]

पाकिस्तान से सम्बन्धों के सामान्यीकरण की पूर्व शर्त के रूप में इस विवाद के समाधान पर बांग्लादेश के दबाव के फलस्वरूप दो समझौते हुए :

---

2. न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क, फरवरी 13, 1972
3. फार ईस्टर्न इकानामिक रिव्यू, हांगकांग, मई 28, 1973

1973 का दिल्ली समझौता (मेमोरेंडम सहित) एवं 1974 का त्रिपक्षीय समझौता ।

दिल्ली समझौते के अनुसार :

1. पाकिस्तान सरकार प्रारंभिक रूप में पर्याप्त मात्रा में गैर-बंगालियों को वापस लेने पर सहमत हुई (जिन्होंने पाकिस्तान जाने का विकल्प चुना था)
2. इसके उपरान्त पाकिस्तान जाने के इच्छुक अतिरिक्त लोगों की संख्या निर्धारित होने पर उन्हें जाने की अनुमति दी जायेगी ।

संलग्न मेमोरेंडम में उन श्रेणियों का उल्लेख किया गया जिन के अन्तर्गत पाकिस्तान गैर-बंगालियों की वापसी पर सहमत हुआ । इनमें पूर्व पश्चिमी पाकिस्तान के मूल निवासी, पाकिस्तान की पूर्व केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी एवं उनके परिवार, विभाजित परिवारों के सदस्य तथा 25,000 तंगदस्ती में रहने वाले, जो वहां अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे, सम्मिलित किये गये ।

भारत, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते में भी पाकिस्तान सरकार ने असीमित मात्रा में (उपर्युक्त श्रेणियों के अन्तर्गत) बिहारियों की वापसी पर सहमति जतायी [4] ।

इसके बावजूद वास्तविक संख्या के निर्धारण का मुद्दा लम्बा खिंचता गया । आई.सी.आर.सी. के अनुमान के अनुसार 170,000 बिहारियों की वापसी के बाद भी बांग्लादेशी शिविरों में 350,000 से 400,000 के बीच बिहारी थे । इसे पाकिस्तान ने अस्वीकार कर दिया ।

---

4. मूल दस्तावेज, बांग्लादेश-पाकिस्तान-भारत त्रिपक्षीय समझौता, नई दिल्ली, अप्रैल 9, 1974

1974 में भुट्टो-मुजीब शिखर सम्मेलन में भी यह मुद्दा उठा किन्तु अतिरिक्त संख्या के मामले पर किसी महत्वपूर्ण विचार-विमर्श के प्रति पाकिस्तान ने कोई रुचि नहीं दिखाई । यह 1973 एवं 1974 के समझौतों का पूर्णतः उल्लंघन था । दिल्ली समझौते के अन्तर्गत पाकिस्तान उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में आने वाले समस्त लोगों को वापस लेने हेतु बाध्य था । भुट्टो 400,000 में से, जो कि बांग्लादेश के अनुसार पाकिस्तानी नागरिकता के योग्य थे, 115,000 से अधिक को वापस लेने को तैयार नहीं थे ।[5]

इसी बीच 1973 में वित्तीय संसाधनों के अभाव में रेडक्रॉस सोसायटी ने अपनी पुनर्वास सम्बन्धी गतिविधियां रोक दीं । पाकिस्तान पर दबाव बनाने के उद्देश्य से ढाका ने यह मुद्दा 1974 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की तृतीय समिति एवं 1975 में जमैका में राष्ट्रमंडल नेताओं के सम्मेलन के समक्ष उठाया ।

बांग्लादेशी राष्ट्रपति जियाउर्रहमान की 1977 में पाकिस्तान यात्रा से दोनों के सम्बन्धों में एक नये अध्याय की शुरुआत हुई । इसी वर्ष अगस्त में पाकिस्तानी विदेश सचिव की ढाका यात्रा के दौरान तंगहाली में रह रहे 25000 लोगों की अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के जरिए वापसी पर सहमति हुई किन्तु 4790 लोगों की पुनर्वापसी के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक संकट के कारण यह प्रक्रिया बीच में ही बाधित हो गई । इसे पुनः पटरी पर लाने के लिए 1978 में बांग्लादेश के विदेश सचिव ने पाकिस्तान की यात्रा की परन्तु पाकिस्तान की इस मुद्दे में विशेष रुचि नहीं थी तथा 'उसने उपर्युक्त संख्या को 25000 से घटा कर 16000 कर दिया ।'[6]

----

5. न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क, जून 29, 1974

6. सैयद सिराजुल इस्लाम, 'बांग्लादेश-पाकिस्तान रिलेशन्स : फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू कॉ-आपरेशन', उद्धृत, एमाजुद्दीन अहमद(सम्पा0)'फॉरेन पॉलिसी ऑफ बांग्लादेश : ए स्मॉल स्टेट्स इम्पेरेटिव,' ढाका युनिवर्सिटी प्रेस, 1984, पृ0 55

इस दौरान बेसहारा पाकिस्तानी जिस दयनीय स्थिति में रह रहे थे, वह शोचनीय थी तथा बांग्लादेश के लिए अपने सीमित संसाधनों से इतने लोगों की देखभाल काफी कठिन कार्य था । पाकिस्तान की हिचकिचाहट के बीच ही सितम्बर 1979 में बांग्लादेशी गृहमंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान यात्रा कर वार्ता जारी रखने का मार्ग प्रशस्त किया । अक्टूबर 1980 में पाकिस्तानी विदेश सचिव की ढाका यात्रा के सिवा इस बीच और कोई प्रगति नहीं हुई । इस दौरान बांग्लादेश ने केन्द्रीय सरकार के पूर्व कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को वरीयता देते हुए वापसी प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का आग्रह किया तथा 'विभाजित परिवारों' की परिभाषा के लिए स्पष्टीकरण मांगे । बांग्लादेश ने इस्लामी एवं पौर्वात्य अवधारणा के अनुसार संयुक्त परिवार को आधार माना । गतिरोध की इस स्थिति के बीच 1983 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ढाका में 1974 के त्रिपक्षीय समझौते के आधार पर 50000 बिहारियों को और वापस लेने का आश्वासन दिया ।'[7]

इस मुद्दे पर विश्व-मीडिया का भी ध्यान आकर्षित हुआ । ये बिहारियों की दुर्दशा मूलत: एक मानवीय समस्या थी जो उपमहाद्वीप के नस्लीय संघर्षों, घृणा एवं हिंसा में उलझ कर रह गई । ब्रिटिश शरणार्थी परिषद् की एशिया समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व ब्रिटिश सांसद लार्ड डेविड एनक्स ने बेसहारा पाकिस्तानियों के पुनर्वास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय कोष स्थापित किया । दिसम्बर 1982 में जेनेवा में स्वयंसेवी संगठनों की अन्तर्राष्ट्रीय परिषद के सम्मेलन में बेसहारा पाकिस्तानियों ने इस मुद्दे का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करते हुए मुस्लिम देशों से भी हस्तक्षेप की अपील की । इस्लामी देशों

---

7. अब्दुल एम. हफीज, 'बांग्लादेश पाकिस्तान रिलेशन्स : स्टिल ह्वलपिंग ?' बी.आई.आई.एस.एस.जर्नल, 1986, पृ0 361

को विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भी यह मुद्दा उठाया गया । बांग्लादेश ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने 1982 तक केवल 1,26,941 लोगों को वापस लिया जबकि पाकिस्तान के मत में यह संख्या 169000 थी ।[8]

अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यानाकर्षण के अन्तर्गत मक्का स्थित मानवतावादी संगठन - रबीता-अल अलाम-अल-इस्लामी ने इस मानवीय समस्या के समाधान में रुचि लेना शुरू किया ।

1983 के बाद से पाकिस्तान ने किसी भी प्रकार की पुनर्वापसी के लिए पहल न करने की नीति अपना ली, यद्यपि 1985 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया-उल-हक ने अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान कहा कि पाकिस्तान किसी भी बिहारी को वापस लेने के लिए विधिक रूप से बाध्य नहीं है, किन्तु मानवीय एवं नैतिक आधारों पर हम इस मुद्दे पर ध्यान देंगे । रबीता की सहमति के बावजूद उसकी कोई अनिवार्य जिम्मेदारी नहीं है ।[9]

यह एक विचित्र स्थिति थी । पाकिस्तान की उत्पत्ति मुस्लिम गृह-राज्य के रूप में हुई तथा ये बिहारी, जो मुस्लिम भी थे तथा पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी थीं और पाकिस्तान में रहना चाहते थे, उन्हें निश्चय ही यह अधिकार था ।

पाकिस्तान वित्तीय संसाधनों के लिए रबीता संस्था, जिसका धनी तेल-सम्पदा वाले देशों से सम्पर्क था, से वार्तालाप करता रहा एवं कुछ भी उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पायी । दूसरी ओर 260,000 बिहारी शिविरों में बदहाली में जीते रहे । बेसहारा पाकिस्तानियों की वापसी के लिए अन्तर्राष्ट्रीय परिषद के जन सम्पर्क सचिव के शब्दों में, "इन वर्षों में ढाई लाख पाकिस्तानी, पुनर्वापसी का इंतजार करते हुए झुग्गियों में

---

8. फार ईस्टर्न इकोनॉमिक रिव्यू, हांगकांग, जनवरी 26, 1985.
9. डेली इत्तेफाक, ढाका, दिसम्बर 10, 1985

दैन्य, अत्यधिक गरीबी एवं पूर्ण पतन की स्थिति में रहने को मजबूर थे । ... जबकि पाकिस्तानी सरकार आर्थिक तंगी एवं सामाजिक तनावों के बहाने बना रही थी ।[10]

1987-88 के दौरान बेसहारा पाकिस्तानी पुनर्वास महासमिति के प्रमुख नसीम खान ने पाकिस्तान पर दबाव बनाये रखने हेतु प्रदर्शन एवं भूख हड़तालें आयोजित कीं । पाकिस्तान एवं रबीता के बीच 1988 में इस्लामाबाद में चिर-प्रतीक्षित समझौता हुआ जिसमें 260,000 बिहारियों की वापसी हेतु 284 मिलियन यू. एस. डालर का कोष स्थापित करने का प्रावधान किया गया । तीन वर्ष में यह कार्य पूर्ण किया जाना था ।[11] बांग्लादेश ने इसे पुनर्वापसी का प्रथम चरण कह कर स्वागत किया । किंतु पाकिस्तान की आंतरिक बाध्यताओं के चलते 400 बेसहारा पाकिस्तानियों को ले जाने वाली प्रथम उड़ान ही रद्द कर दी गई तथा हमेशा की तरह उनका भविष्य फिर अंधकारमय हो गया ।

बेनजीर भुट्टो ने 1989 में इन्हें बांग्लादेश में ही बसाने का सुझाव दिया जिसके लिए आर्थिक सहायता दी जा सकती थी । बेगम जिया की दिसम्बर 1992 में पाकिस्तान यात्रा के दौरान 3000 परिवारों को पंजाब में बसाने पर सहमति हुई । पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ इस समस्या के समाधान के प्रति अधिक गम्भीर दिखे । 1992 में उनके कार्यकाल में 321 परिवारों को पंजाब में, जो कि नवाज़ शरीफ का गृह राज्य है, रबीता ट्रस्ट द्वारा बनायी गई आवासीय इकाइयों में बसाया गया ।[12] नवाज़ शरीफ की सरकार के पतन के साथ ही यह प्रक्रिया पुनः बाधित हो गई ।

---

10. न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क, जुलाई 7, 1988
11. फार ईस्टर्न इकानामिक रिव्यू, जनवरी 26, 1989
12. एशियन रिकॉर्डर, मार्च 5 से 11, 1998, पृ0 27127

पंजाब प्रान्त के विभिन्न जिलों में 250 मि. डालर की लागत से प्रस्तावित कुल 41500 आवासीय इकाइयों में से 1994 तक मियां छन्नू नामक स्थान पर 1000 इकाइयों का निर्माण पूरा किया जा चुका था ।[13]

इस वृहद् मानवीय कार्यक्रम के लिए दो बैंक खातों में विदेशी एवं घरेलू मुद्रा में सहयोग हेतु अपील की गई जिसमें कहा गया कि 'ये पाकिस्तानी केवल अपने को पाकिस्तानी कहने के गर्व के कारण पिछले 25 सालों से बांग्लादेश में अवर्णनीय एवं दु:खद स्थितियों में जीवन गुजार रहे हैं ।'[14]

इस मुद्दे पर बांग्लादेश की भी अपनी आंतरिक राजनीतिक एवं आर्थिक बाध्यताएं हैं । अपने सीमित संसाधनों में से बांग्लादेश इन बिहारियों को खाद्य सामग्री, पेयजल, बिजली व स्वच्छता की सुविधाएं एवं अन्य राहत उपलब्ध करवाता रहा है जो वह अपने अधिकांश नागरिकों को भी उपलब्ध नहीं करवा पाता । इसके लिए लगभग 120 मि. टका प्रतिवर्ष व्यय होता है ।[15] साथ ही सामाजिक एवं नृवंशीय तनाव भी बांग्लादेशी सरकार को इनकी शीघ्र पाकिस्तान वापसी हेतु मजबूर कर रहे हैं । नवाज शरीफ के पुन: सत्ता में आने के बाद बिहारियों ने अपने आन्दोलन तेज कर दिये । 1997 में इन्होंने बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना से पाकिस्तान पर दबाव डालने का आग्रह करते हुए जुलूस निकाला । इस अवसर पर बेसहारा पाकिस्तानी पुनर्वास महासमिति के प्रमुख नसीम खान ने कहा -'हमारा जीवन जानवरों से भी बदतर है । उन तथाकथित शिविरों में अमानवीय दशाओं में रखने के बजाए हमें गोली मार दीजिए ।'[16] प्रदर्शन में शामिल

----

13. एशियन रिकॉर्डर, मार्च 5 से 11, 1998, पृ0 27127
14. वही, पृ0 27128
15. दिलारा चौधरी, 'बांग्लादेश एण्ड दि साउथ एशियन इंटरनेशनल सिस्टम, ढाका, ऐकेडमिक पब्लिशर्स, 1992, पृ0 303
16. साउथ एशिया वॉच, साउथ एशियन सेंटर फॉर स्टेटेजिक स्टडीज़, वॉ. 1, इश्यू-8, जुलाई 1997, पृ0 8

बच्चों एवं महिलाओं ने धमकी दी कि यदि उन्हें अपने 'गृहस्थान' पर नहीं बसाया गया तो वे खुद को समाप्त कर लेंगे ।

दूसरी ओर इस मुद्दे को लटकाये रखने में पाकिस्तान की अपनी घरेलू मजबूरियां एवं हित हैं । प्रारंभिक पाकिस्तानी सरकारें आर्थिक संसाधनों की कमी के बहाने इसे टालती रहीं । रबीता ट्रस्ट से समझौते एवं आर्थिक संसाधन उपलब्ध होने के बाद पाकिस्तानी प्रधान मन्त्री बेनजीर भुट्टो ने बिहारियों को पाकिस्तानी मानने से इन्कार कर दिया तथा इस मुद्दे को 'मुस्लिम उम्मा' से जोड़ा । उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पी.पी.पी.) बिहारियों की वापसी की विरोधी रही है, जो सिंध प्रान्त में बहुसंख्यक सिंधी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है । सिंधियों को आशंका है कि भारत भूमि से आये मुसलमानों की सिंध में संख्या बढ़ने से होने वाले जनांकिकीय परिवर्तनों के कारण वे अल्पसंख्यक हो जायेंगे तथा पाकिस्तान की राजनीति में उनका महत्व घट जाएगा । साथ ही इनके आने से सिंधियों के लिए आर्थिक प्रगति, रोजगार एवं व्यवसाय के अवसर सीमित हो जायेंगे जो पहले ही मोहाजिरों के आने से काफी कम हो चुके थे । पी.पी.पी. का मत है कि पंजाब सहित इन बिहारियों को देश के किसी भी भाग में बसाया जाये तो भी ये स्थानांतरण करके सिंध प्रान्त या कराची में आ जायेंगे ।[17] बेनजीर ने तो इनके शरीर में मुस्लिम-लहू होने पर भी सन्देह किया ।

सच्चाई तो यह है कि अराजकता, आतंक और जातीय हितों के सियासी टकराव के चलते पाकिस्तान का सिंध प्रान्त वर्षों से अशांत चल रहा है । सिंध के अनेक राज-दलों ने शरीफ सरकार पर आरोप लगाया कि वह विदेशी आतंकवादियों (बिहारियों, जो कि सिंध में बस चुके हैं)

---

17. प्रो. वीरेन्द्र नारायण से भेंटवार्ता पर आधारित । देखें - परिशिष्ट, पृ. 86

को हथियार मुहैया करवा रही है । ऐसे में नवाज़ शरीफ द्वारा बांग्लादेश में फंसे ढाई लाख बिहारियों को पाकिस्तान ला कर आबाद करने के आश्वासन ने आग में घी का काम किया । वर्तमान शरीफ सरकार में शामिल रही मुत्ताहीद कौमी मूवमेंट (पहले मौहाजिर कौमी मूवमेंट) भी बिहारियों की वापसी हेतु लगातार दबाव बनाये हुए है ।[18] सिंधियों ने इसे अपनी पहचान एवं अस्तित्व से जोड़ लिया है । मौहाजिरों के बढ़ते प्रभाव से वे पहले ही दु:खी हैं । पीपुल्स पार्टी को सिंध में अपना जनाधार खिसकता नजर आ रहा है । जिए सिंध आन्दोलन ने भी कराची से मौहाजिरों सहित बिहारियों के निष्कासन की मांग की है । इसी मानसिकता की झलक है कि जब 1988 के समझौते (पाकिस्तान व रबीता के बीच) के अन्तर्गत एक विमान 400 बिहारियों को ढाका से कराची लाने वाला था तो सिंध नेशनल स्लायंस(जातीय उग्र राष्ट्रवादी संगठन) के नेतृत्व में सिंधियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कराची हवाई अड्डे को घेर लिया ।

इन जातीय एवं राजनीतिक बाध्यताओं के बावजूद वित्तीय व्यवस्थाएं हो जाने से पाकिस्तान के पास इस मुद्दे को टालने के कोई तार्किक कारण नहीं हैं । मुशाहिद हुसैन के अनुसार बिहारियों सम्बन्धी इस मुद्दे पर पाकिस्तान का पक्ष नैतिक एवं कानूनी दृष्टिकोण से काफी कमजोर है । पाकिस्तान सरकार की नीति समय गुजार कर इस प्रश्न को गौण बना देने की है ।[19]

बांग्लादेश में अवामी लीग तथा पाकिस्तान में नवाज शरीफ के पुन: सत्ता में आने के बाद इस समस्या के समाधान हेतु नया वातावरण

---

18. जनसत्ता, नई दिल्ली, जून 27, 1998
19. दि नेशन, इस्लामाबाद, मार्च 24, 1998

बना है । 26 दिसम्बर 1997 को पुनर्वापसी कार्यक्रम की पुनर्संरचना के लिए पाकिस्तान के वित्त मंत्री सरताज अजीज की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय बैठक इस्लामाबाद में हुई तथा वापसी के तौर-तरीकों पर विचार किया गया । एम. क्यू. एम. के नेता अल्ताफ़ हुसैन लगातार यह मांग उठाते रहे हैं । जनवरी 1998 में त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन (भारत - पाकिस्तान - बांग्लादेश) के अवसर पर 16जनवरी को शेख हसीना से अपनी मुलाकात में नवाज़ शरीफ ने 238,000 बिहारियों (1991-92 में संयुक्त रूप से की गई जनगणना के आधार पर) की वापसी पर गंभीरता-पूर्वक कार्य करने पर सहमति जताई ।[20] यह उम्मीद की जा सकती है कि जब तक दोनों देशों में वर्तमान सरकारें हैं, इस विवाद पर सकारात्मक दिशा में प्रगति होगी । नवाज़ शरीफ स्वयं भी पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में अपना वोट बैंक बढ़ाने तथा सिंध में बेनजीर का आधार सीमित करने को प्रयासरत हैं तथा बिहारियों की वापसी इसमें मददगार है ।

परिसम्पत्तियों एवं आर्थिक देयताओं का बँटवारा

संयुक्त पाकिस्तान की सम्पदा में दोनों भागों (पूर्वी एवं पश्चिमी) के लोगों के प्रयासों एवं श्रम का योगदान था । बांग्लादेश के निर्माण के बाद संयुक्त परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों का समुचित बँटवारा न होने से दोनों देशों के सम्बन्धों पर विपरीत असर पड़ता रहा है । अप्रैल 1974 में नई दिल्ली त्रिपक्षीय सम्मेलन के दौरान भी यह मुद्दा उठाया गया । जून 1974 में प्रधानमंत्री भुट्टो की ढाका यात्रा के दौरान शेख मुजीब ने बिहारियों के मुद्दे के साथ ही 6 बिलियन डालर की परिसम्पत्तियों का

---

20 खलीज़ टाइम्स, यू.ए.ई., जनवरी 17, 1998

मुद्दा भी उठाया जो पाकिस्तान के अधिकार में थी एवं बांग्लादेश ने इस पर अपना दावा जताया । इसके साथ ही बांग्लादेश ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना द्वारा किये गये विनाश के लिए मुआवज़े की भी मांग रखी, जो कि सौदेबाजी का एक प्रयास था । मुजीबुर्रहमान ने रक्षित स्वर्ण भण्डार, विदेशों में जमाओं, प्रतिभूतियों, हवाई जहाज एवं जहाज, रक्षा भण्डार एवं उपकरण एवं दूतावासों की इमारतों के दो माह में बंटवारे की मांग की ।[21] ढाका सरकार ने भुट्टो-मुजीब वार्ताओं में सम्पत्ति के बंटवारे को सम्बन्ध सुधार की पूर्वापेक्षा के रूप में पेश किया तथा पाकिस्तान से समझौते का आग्रह किया । इस सम्बन्ध में प्रमुख समस्या सम्पत्तियों एवं देयताओं के परिमापन की थी । पाकिस्तान ने इस बात को विशेष महत्व न देते हुए भुट्टो की यात्रा को एक `खोजी` यात्रा के रूप में निरूपित किया । पाकिस्तान ने सम्पत्ति के समुचित विभाजन के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने में रुचि ज़ाहिर की, जो मूलत: और अधिक समय निकालने का बहाना मात्र था ।

पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने 3.6 बिलियन डालर की ऋण देनदारियों के विभाजन की कार्यप्रणाली निर्धारित करने का प्रयास किया । बांग्ला देश ने केवल 50 करोड़ डालर की देनदारी स्वीकार की । पाकिस्तान ने देनदारियों वाले पक्ष पर अधिक बल दिया जिसके अनुसार कुल बाह्य ऋण 6 बिलियन डालर से अधिक था । बांग्लादेश ने यह मुद्दा संयुक्त समिति के सुपुर्द करने पर सहमति जताई । संयुक्त पाकिस्तान के स्वर्ण भंडार एवं विदेशी मुद्रा भंडार के 1 करोड़ 70 लाख डालर सहित परिसम्पत्तियों में बांग्लादेश की कुल मांग 4 हजार मिलियन

---

21. न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क, जुलाई 9, 1974

डालर थी । उल्लेखनीय है कि राज्यों के उत्तराधिकार सम्बन्धी वियना अभिसमय 1983 के आधार पर बांग्लादेश जैसा भूभागग्रस्त देश पाकिस्तान से पर्याप्त मात्रा में सम्पत्ति का दावा कर सकता है ।[22] अधिकारिक अनुमानों के अनुसार बांग्लादेश का हिस्सा सेना में 15 प्रतिशत, प्रशासन में 12 प्रतिशत, विदेश सहायता में 30 प्रतिशत एवं केन्द्र सरकार के व्यय में 26 प्रतिशत था । बांग्लादेश ने 23 पाकिस्तानी विभागों एवं स्वायत्त निकायों की परिसम्पत्ति के बँटवारे का विवरण भी पेश किया । इनमें से इक्विटी सहभागिता कोष एवं गृह निर्माण वित्त निगम के प्रति बांग्लादेश ने अपनी 108.8 मिलियन टका की देनदारी स्वीकार की । पाकिस्तानकी दृष्टि में बांग्लादेश के दावे अतिशयोक्तिपूर्ण एवं निराधार थे । दावों-प्रतिदावों की इन स्थितियों के कारण यह मुद्दा भी लटका रहा ।

जियाउर्रहमान के सत्ता में आने के बाद दिसम्बर 1977 में उनकी पाकिस्तान यात्रा की समाप्ति पर जारी संयुक्त विज्ञप्ति में पाकिस्तान आधिकारिक रूप से पहली बार सम्पत्तियों के वितरण पर बांग्लादेश से वार्ता को सहमत हुआ । किन्तु इसके लिए जो संयुक्त कार्यकारी दल गठित किया गया, उसकी बैठकें ही नहीं हो सकीं ।

बांग्लादेश ने 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1992 एवं 1998 में शासनाध्यक्षों या विदेश मंत्रियों की आपसी यात्राओं के दौरान पाकिस्तान से गम्भीरतापूर्वक बातचीत का प्रयास किया किन्तु किसी

---

22. उमा सिंह, 'बांग्लादेश एण्ड पाकिस्तान : कन्वरजेन्स एण्ड डाइवरजेन्स', उद्धृत - चक्रवर्ती, (सम्पा.) 'फॉरेन पॉलिसी ऑफ बांग्लादेश', न्यू देहली, हर आनन्द पब्लिकेशन्स, 1994, पृ0 226

संतोषजनक हल तक नहीं पहुंचा जा सका । सैयद सिराजुल इस्लाम के अनुसार बांग्लादेश ने परिसम्पत्तियों के विभाजन के लिए चार सूत्र प्रस्तावित किये :

1. जनसंख्या - जहां बांग्लादेश कुल परिसम्पत्तियों में 56 प्रतिशत पर दावा कर सकता है ।
2. सम्पदा - जिसके अनुसार बराबर वितरण होगा एवं बांग्लादेश को 50 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा।
3. विदेशी मुद्रा भंडार - इसके तहत बांग्लादेश का हिस्सा 51 प्रतिशत होगा ।
4. आनुपातिक - कुल परिसम्पत्तियों का 44 प्रतिशत बांग्लादेश मांग सकता है ।

लेकिन इन सूत्रों पर भी सहमति नहीं हो सकी । एक पाकिस्तानी लेखक के अनुसार बांग्लादेश अपने बढ़ा-चढ़ा कर पेश किये गये दावों को भुना नहीं सकता तथा ये केवल कागजों पर ही रहेंगे ।[23] यह इतिहास की विडंबना है कि जिस पाकिस्तान ने 1947 में भारत-विभाजन के बाद परिसम्पत्तियों के वितरण एवं अपने अनुचित दावों की पूर्ति हेतु जोरदार हो-हल्ला किया था, वही बांग्लादेश को उसका समुचित हिस्सा देने से कतराता रहा है । जनवरी 1998 में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ ने अपनी ढाका यात्रा के दौरान परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के परीक्षण एवं निर्धारण हेतु 'संयुक्त निकाय' की स्थापना की पुरानी बात ही दोहराई ।[24]

---

23. ए. ए. अक्मत, 'राइट्स एण्ड ऑब्लिगेशन्स इन रिगार्ड टू एसेट्स लोकेटेड इन बांग्लादेश', पाकिस्तान होराइजन्स, 1973, पृ० 7

24. खलीज़ टाइम्स, यू. ए. ई., जनवरी 17, 1998

अन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं न्याय की दृष्टि से बांग्लादेश के दावे वैध हैं क्योंकि बांग्लादेश संयुक्त पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत रहा था ।

पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से उपजी कड़वाहट

जनसंवेदनाएं एवं जनमानस में बैठी यादें राष्ट्रों की नीतियों पर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं । यह बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के सम्बन्धों पर भी लागू होता है। सन् 1947 से 1971 के बीच 23 वर्षों तक पूर्वी बंगाल की जनता ने पश्चिमी पाकिस्तान के 'आंतरिक उपनिवेश' के रूप में कष्ट सहे । इसके उपरान्त 1971 में गृहयुद्ध छिड़ने पर 25 मार्च को पूर्वी बंगाल में पाकिस्तानी सैनिक कार्यवाही शुरू हुई । 16 दिसम्बर 1971 को भारत-बांग्लादेश की संयुक्त कमान के समक्ष पाकिस्तान के पूर्वी कमाण्डर जनरल नियाजी द्वारा 90000 सैनिकों सहित आत्मसमर्पण करने तक, कुल 9 माह की अवधि में पाकिस्तान सेना ने पूर्वी बंगाल की जनता पर असीमित जुल्म ढाये । यह उल्लेखनीय है कि इस दौरान लगभग 30 लाख निरीह बंगालियों की हत्या की गई एवं लगभग 3 लाख महिलाओं के साथ पाकिस्तानी फौजियों ने बलात्कार किया । बांग्लादेशियों के अनुसार जनवध, व्यापक पैमाने पर बलात्कार, आगजनी, लूटपाट एवं लगभग एक करोड़ लोगों को भारत में शरणार्थी बनने को मजबूर करने के लिए पाकिस्तानी सैनिक जिम्मेदार थे ।[25]

16 दिसम्बर 1971 को समर्पण से पूर्व पाकिस्तानी सेना द्वारा बांग्लादेशी व्यवसायियों एवं बुद्धिजीवियों की चुन-चुन कर की गई हत्याओं ने आग में घी डालने का काम किया । इसने बांग्लाजन के मनस् पर स्थायी आघात लगाया । प्रो. वीरेन्द्र नारायण के अनुसार अन्य

---

25. एशियन रिकॉर्डर, मार्च 5 से 11, 1998, पृ0 27119

विवादों के होते हुए भी पाकिस्तानी सेना के इस दुष्कृत्य से बांग्लादेशी जनता के मन में उपजी कटु यादें दोनों देशों को नजदीक लाने में बाधक रही हैं । अप्रत्यक्ष रूप से दोनों देशों के बीच ये विरासतें बड़ी खाई बनाये हुए हैं तथा अभी भी आने वाले कुछ वर्षों में दोनों देशों के सम्बन्धों को प्रभावित करती रहेंगी ।[26]

बांग्लादेशी समाज के विभिन्न वर्गों एवं सरकार ने समय-समय पर पाकिस्तानी सेना के उपर्युक्त दुष्कृत्यों के लिए पाकिस्तान द्वारा क्षमा-याचना करने की मांग की है । पिछले कुछ सालों से विश्व राजनीति में 'क्षमायाचना राजनय' चर्चित रहा है । जापान ने चीन से द्वितीय विश्व-युद्ध में किये गये अत्याचारों के लिए माफी मांगी तथा अमेरिका से 1945 में जापान पर अणुबम गिराने के लिए क्षमायाचना की मांग की । इसी प्रकार इस वर्ष ब्रिटिश महारानी की भारत यात्रा के समय भारतीय समाज के कुछ समूहों ने जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 'क्षमायाचना' हेतु आवाज उठायी । बांग्लादेश-पाकिस्तान सम्बन्धों में यह मुद्दा तब पुनः चर्चा में आया, जब पिछले दिनों जनवरी 1998 में प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ की बांग्लादेश यात्रा के दौरान उन्होंने 1971 की घटनाओं को एक 'ऐतिहासिक भूल' या त्रुटि की संज्ञा दी । 17 जनवरी, 1998 को ढाका में शेख हसीना द्वारा उनके सम्मान में आयोजित भोज के दौरान शरीफ ने स्वीकार किया कि 'यदि 1970 के चुनावों का सम्मान किया जाता तो इस उपमहाद्वीप का इतिहास आज दूसरा होता ।[27] शरीफ ने कहा कि समस्या तब हुई जब लोकतंत्र के सिद्धान्तों का सम्मान नहीं किया

---

26. प्रो. वीरेन्द्र नारायण से भेंटवार्ता पर आधारित, देखें - परिशिष्ट, पृ. 86

27. दि हिन्दू, नई दिल्ली, जनवरी 19, 1998

गया या मतपत्र की शुचिता का खण्डन किया गया । इसमें कोई शक नहीं कि पश्चिमी पाकिस्तान में सत्ता तंत्र के सूत्रों को केन्द्रित रखने के लिए जानबूझ कर पूर्वी भाग को अलग होने को मजबूर किया गया । अवामी लीग को 1970 के चुनावों में मिले जनसमर्थन का सम्मान करते हुए इसके नेता शेख मुजीब को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए था ।

उल्लेखनीय है कि किसी भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री द्वारा 1971 की 'गलती' स्वीकार करने का यह पहला अवसर है । किन्तु इस स्वीकारोक्ति के पीछे भारत विरोध एवं पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति के कई कारकों का भी योगदान है । अपने वक्तव्य में यह जोड़ कर कि "बाह्य शत्रुतापूर्ण शक्तियां जो हमारी गलतियों का फायदा उठाने की ताक में थीं, अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल रहीं । अत: अब हमें इतिहास से सीख लेनी चाहिए"[28], प्रकारान्तर से उन्होंने भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की ।

इस संदर्भ में भी बांग्लादेश एवं पाकिस्तान दोनों की आंतरिक राजनीतिक अनिवार्यताएं हैं । पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ सत्ता पर सेना की पकड़ को कमजोर करने के साथ ही बेनजीर की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को भी किनारे करना चाहते हैं । इसीलिए उन्होंने बांग्लादेश यात्रा से लौटने के बाद पाकिस्तान में एम.क्यू.एम. की रैली को संबोधित करते हुए 1971 की दुखान्तिका के लिए जिम्मेदार मार्शल लॉ शासकों एवं राजनीतिज्ञों की आलोचना करते हुए दोषी लोगों को दण्ड नहीं दिये जाने पर निराशा व्यक्त की । उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसे लोगों पर मुकदमा चलाने का आश्वासन देते हुए कहा कि 'पाकिस्तान के टुकड़े करने वाले' ही इसके सम्मानीय नागरिक बने बैठे हैं ।'[29] यद्यपि ये 'दोषी' कौन हैं,

---

28. एशियन रिकॉर्डर, फरवरी 28 से मार्च 4, 1998, पृ0 27111

29. वही

उन्होंने स्पष्ट नहीं किया किन्तु सेना एवं पीपुल्स पार्टी के कई वरिष्ठ लोगों की ओर ही उनका इशारा था ।

नवाज़ शरीफ की उपर्युक्त स्वीकारोक्तियों के उपरान्त 27 जनवरी 1998 को बांग्लादेश सरकार ने आधिकारिक रूप से 1971 की घटनाओं एवं मारकाट के लिए पाकिस्तान से `क्षमायाचना` की मांग की । बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शरीफ की स्वीकारोक्ति का स्वागत करते हुए उनसे `एक कदम और` आगे बढ़ते हुए बांग्लादेशी जनता के घावों पर मलहम लगाने हेतु यह आग्रह किया ।

पाकिस्तान में भी कुछ लोगों ने ढाका की मांग से सहानुभूति जतायी । सेवानिवृत्त एयर मार्शल एवं वर्तमान में पाकिस्तान नेशनल कान्फ्रेंस (पी.एन.सी.) के अध्यक्ष असगर खान ने, जिन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में सैनिक कार्यवाही का विरोध किया था, कहा कि पाकिस्तान द्वारा क्षमायाचना उचित एवं मर्यादायुक्त कदम होगा क्योंकि पाकिस्तान इस दुखान्तिका के 27 वर्ष बाद भी अपने को `पापमुक्त` नहीं कर पाया है ।

जनरल ए.ए.के. नियाजी, जिन्होंने अपनी सेना सहित 1971 में समर्पण किया था, ने हाल ही में प्रकाशित अपनी पुस्तक में हवाला दिया है कि पाकिस्तानी सेना द्वारा भारी मात्रा में लोगों की हत्याएं की गईं तथा जनरल टिक्का खान द्वारा की गई सैनिक कार्यवाही चंगेज खान एवं हलाकू खान द्वारा किये गये नरसंहारों से भी वीभत्स थी ।[30]

---

30. लेफ्. जन. ए.ए.के. नियाजी, `दि बिट्रेयल आफ ईस्ट पाकिस्तान`, कराची, ऑक्सफार्ड युनिवर्सिटी प्रेस, उद्धृत, एशियन रिकॉर्डर, मार्च 5-11 1998, पृ0 27128

लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने ढाका की मांग पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की । इससे ऐसे समय में पाकिस्तान की दु:खती रग पर हाथ पड़ गया जब वह कश्मीर में भारतीय सेनाओं द्वारा कथित दमन की ओर विश्व का ध्यान आकृष्ट करने में अपने समस्त प्रयास झोंके हुए है। एक वरिष्ठ पाकिस्तानी संघीय मंत्री ने पाकिस्तानी सेना द्वारा कथित 'युद्ध अपराधों' के लिए औपचारिक रूप से माफी माँगने की बांग्लादेशी सरकार की माँग की आलोचना की ।

'पूर्वी पाकिस्तान संकट' पर पाकिस्तानी प्रतिष्ठान की भूमिका पर छिड़ी इस नई बहस में सेना का बचाव करते हुए सेवानिवृत्त मेजर जनरल अब्दुल मज़ीद मलिक ने कहा कि 'कलकत्ता-योजना' के अंतर्गत 1971 में पाकिस्तान विरोधी तत्वों ने पाकिस्तान के विभाजन का षडयन्त्र रचा था तथा आंतरिक एवं बाह्य आक्रमण की स्थितियों ने 'पूर्ण-युद्ध' का रूप ले लिया । ऐसे में मातृभूमि की रक्षार्थ पाकिस्तानी सैनिकों को युद्ध लड़ना पड़ा, जिसमें जानबूझ कर किसी भी निरपराध की हत्या नहीं की गई ।[31] उन्होंने तर्क दिया कि सैनिक तो उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन कर रहे थे।लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता जैसे कि द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद न्यूरेम्बर्ग युद्ध अपराध न्यायाधिकरण ने जर्मन युद्ध अपराधियों के ऐसे ही तर्क को अस्वीकार कर दिया था ।

बांग्लादेशी जनता में 1971 की घटनाओं की कड़वाहट की मिसाल राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद द्वारा 14 दिसम्बर 1998 को 'शहीद बुद्धि-जीवी दिवस' के अवसर पर व्यक्त इन विचारों से भी मिलती है कि बांग्लादेश पाकिस्तानी सेना द्वारा एक हजार से भी अधिक बुद्धिजीवियों की चुन-चुनकर हत्या करने के 'पाशविक एवं बर्बर कृत्य' को कभी भुला नहीं सकता ।[32] बांग्लादेशियों के अनुसार व्यवसायियों एवं बुद्धिजीवियों

---

31. खलीज टाइम्स, यू. ए. ई., फरवरी 4, 1998

32. एशियन रिकॉर्डर, जनवरी 22 से 28, 1998, पृ० 27024

की जानबूझ कर हत्याओं के पीछे उद्देश्य यह था कि एक नये राष्ट्र के भावी निर्माताओं की सम्पूर्ण पीढ़ी का ही उन्मूलन कर दिया जाये ।

इसलिए 1971 की गलतियों को स्वीकार करने के बावजूद नवाज़ शरीफ पाकिस्तानी सेना के जनसंहार को भुगत चुके बांग्लादेशियों को संतुष्ट नहीं कर सके । शरीफ ने केवल 'तकनीकी गलती' की ओर इशारा किया एवं बंगालियों के प्रति पश्चिमी पाकिस्तान के औपनिवेशिक व्यवहार को भूल गये । बांग्लादेश निर्माण के 26-27 वर्ष बाद भी शरीफ ने यह महसूस नहीं किया कि बंगालियों के धर्मनिरपेक्ष-राष्ट्रवाद का पाकिस्तानी पंथ आधारित-राष्ट्रवाद से मौलिक विरोध था, जिसने दोनों भागों के मध्य विभाजन प्रक्रिया को त्वरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । इसके बावजूद यदि पाकिस्तान 1971 के अत्याचारों के लिए माफी मांगता है तो दोनों देशों के मध्य सम्बन्धों के और सुधार में मदद मिलेगी तथा अन्तर्राष्ट्रीय जगत की प्रशंसा भी ।

अध्याय - तृतीय

बांग्लादेश-पाकिस्तान : राजनीतिक सम्बन्ध

द्विपक्षीय सम्बन्धों में राजनीतिक पक्ष अन्य समस्त पक्षों का निर्णायक होता है । यद्यपि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रों के मध्य सम्बन्धों के ये विभिन्न पक्ष (आर्थिक, सांस्कृतिक, भू-राजनीतिक, रक्षात्मक आदि) अत्यधिक घुलमिल गये हैं, किन्तु राजनीति के व्यापक निहितार्थों में इनका समावेश किया जा सकता है ।

बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के सम्बन्धों में धार्मिक समानता के बावजूद राजनीतिक तत्व हमेशा प्रमुख निर्णायक रहे हैं । दोनों देशों के सम्बन्धों में राजनीतिक यथार्थ का निरूपण, अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर अपनाये गये रुख तथा तत्सम्बन्धी सामान्य हितों, क्षेत्रीय राजनीतिक समस्याओं, जैसे - परमाणु हथियार मुक्त दक्षिण एशिया, हिंदमहासागर को शांति क्षेत्र बनाने, कश्मीर, सार्क के अन्तर्गत पारस्परिक तालमेल, उपक्षेत्रीय सहयोग से उपजी आशंकाओं आदि के सम्बन्ध में दोनों की स्थिति तथा द्विपक्षीय स्तर पर सहयोग एवं राजनीतिक नेतृत्व के प्रयासों को उनके द्विपक्षीय राजनीतिक सम्बन्धों के तहत विश्लेषित किया जा सकता है ।

बांग्लादेश-पाकिस्तान राजनीतिक संबंधों का विकास

बांग्लादेश की स्वतन्त्रता के तत्काल बाद पाकिस्तान से सम्बन्धों में सुधार के प्रयास शुरू हुए किन्तु सकारात्मक परिस्थितियां 1974 में पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश को मान्यता देने पर ही बन सकीं । शुरू के लगभग दो वर्ष तक मुजीब एवं भुट्टो के व्यक्तित्वों का टकराव शिखर पर था । भुट्टो 'संयुक्त-पाकिस्तान' के मिथक को बनाये रखते हुए बांग्लादेश के लिए 'मुस्लिम बंगाल' का सम्बोधन प्रयुक्त करते रहे जबकि तब तक कई राष्ट्र बांग्लादेश को मान्यता दे चुके थे ।[1]

---

1. कौशिक, एस.एस., 'पाकिस्तान'स रिलेशन्स विद् बांग्लादेश : एन ओवरव्यू ऑफ दि परसेप्शन ऑफ दि लीडर्स ऑफ दि टू कन्ट्रीज़', उद्धृत- चक्रवर्ती, एस.आर. एण्ड नारायण वीरेन्द्र (सम्पा.), 'बांग्लादेश : ग्लोबल पॉलिटिक्स', वॉ. 3, पृ0 155

इसी कारण 1974 में बांग्लादेश को मान्यता दिये जाने के बावजूद पाकिस्तान ने राजनयिक सम्बन्ध स्थापित नहीं किये । प्रारंभ में दोनों देशों के बीच जो प्रमुख समस्याएं थीं, उनमें भारत एवं पाकिस्तान में बंदी पाकिस्तानी युद्धबंदियों की वापसी, पाकिस्तान में बंदी बंगाली सैनिकों एवं नागरिक कर्मियों की रिहाई, पाकिस्तान से उर्दू भाषी पाकिस्तान समर्थकों की वापसी तथा परिसम्पत्तियों एवं आर्थिक देनदारियों का बँटवारा प्रमुख है । इनमें से बिहारियों की वापसी एवं परिसम्पत्तियों के बँटवारे का विवाद अभी भी अनसुलझा है ।

शेख मुजीब की हत्या के बाद पाकिस्तान एवं बांग्लादेश दोनों ने घनिष्ठ सम्बन्धों हेतु प्रयास किया । इसमें फरक्का विवाद के कारण बांग्लादेश के भारत से तनावपूर्ण होते सम्बन्धों से भी मदद मिली । मुजीबोत्तर काल में भुट्टो की विदेश नीति में उपमहाद्वीप में भारत को अलग-थलग करना एक प्रमुख लक्ष्य था । इसलिए बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ वैसी ही सन्धि करने को आमंत्रित किया, जैसी बांग्लादेश ने भारत के साथ की थी । भुट्टो का उद्देश्य पाकिस्तान को 'शक्तिशाली एवं अजेय' बनाना था ताकि भारत के वर्चस्व को चुनौती देकर बांग्लादेशी शासकों को भारतीय चुनौती से निपटने की क्षमता के प्रति संतुष्ट किया जा सके ।[2] पाकिस्तान के साथ अच्छे सम्बन्धों को बांग्लादेशी सरकार उपमहाद्वीप में शान्ति, सुरक्षा एवं सहयोग की स्थापना सम्बन्धी अपनी विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों से जोड़ कर देखती रही । पाकिस्तान के साथ राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना के उपलक्ष्य में जियाउर्रहमान ने कहा कि, 'यह दोनों देशों के आपसी हितों पर आधारित सहयोग एवं मित्रता

---

2. दि डॉन, कराची, जनवरी 25, 1976

को प्रोत्साहित करेंगे ।[3]

अगस्त 1976 में गुटनिरपेक्ष देशों के कोलम्बो शिखर-सम्मेलन में बांग्लादेश के राष्ट्रपति सायेम ने भारत की कथित 'वर्चस्ववादी' भूमिका के प्रति आशंकाएं व्यक्त कीं । यह भुट्टो द्वारा अपनाये गये रुख का अनुगमन मात्र था ।[4]

5 जुलाई 1977 को पाकिस्तान में सैनिक विद्रोह एवं जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश-पाकिस्तान में एक नया अध्याय शुरू होता है । बांग्लादेशी राष्ट्रपति जियाउर्रहमान ने जनरल जिया उल हक की सैनिकशाही को पूर्ण सहयोग प्रदान किया । यद्यपि 'बिहारियों एवं परिसम्पत्तियों' सम्बन्धी मुद्दे पर कोई प्रगति नहीं हो सकी । यह महत्वपूर्ण है कि दोनों देशों की सैनिक सरकारों की आपसी समझ एवं राजनीतिक गणित के आधार पर ही बांग्लादेशी सरकार ने भुट्टो को फाँसी दिये जाने पर चुप्पी साध ली, जबकि कई विपक्षी दलों ने भुट्टो को 'राज्य-क्षमा' दिये जाने काआह्वान किया था । यह 'मुस्लिम भ्रातृत्व' पर 'राजनीतिक-यथार्थ बोध' की वरीयता का प्रमुख उदाहरण है जो बांग्लादेश-पाकिस्तान सम्बन्धों में इस्लाम की भूमिका की विडंबना को प्रदर्शित करता है ।

दोनों देशों में जियाउलहक एवं जियाउर्रहमान के काल में निम्न-लिखित प्रमुख समझौते हुए --

---

3. कौशिक, एस.एस. -'पाकिस्तान्स रिलेशन्स...', उद्धृत, चक्रवर्ती एस.आर. एण्ड नारायण वीरेन्द्र(सम्पा.) 'बांग्लादेश: ग्लोबल पॉलिटिक्स', वॉ. 3, नई दिल्ली, साउथ एशिया पब्लिशर्स, 1994, पृ0 162

4. दि टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, अगस्त 19, 1976

1. जहाजरानी समझौता - 2 अगस्त 1978, जिसे दोनों देशों के बीच सम्प्रभु समानता एवं आपसी हित पर आधारित प्रथम समझौता कहा जा सकता है ।[5]
2. उड्डयन समझौता - 4 जनवरी 1979, एवं
3. संयुक्त आर्थिक आयोग की स्थापना - 21 जुलाई 1979 ।

मई 1981 में जियाउर्रहमान की हत्या के उपरान्त बांग्लादेश की नई सरकार के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए जनरल जिया उल हक ने `इस्लामी भ्रातृत्व` का शगूफा फिर छोड़ा । जुलाई 1981 में एक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डल की बांग्लादेश यात्रा के दौरान तो यह आशंकाएं व्यक्त की जाने लगीं कि बांग्लादेश को `इस्लामी गणराज्य` घोषित किया जा सकता है एवं बांग्लादेश-पाकिस्तान का एक `परिसंघ` बनाया जा सकता है । बांग्लादेश के कई विपक्षी नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया, जिस पर तत्कालीन बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शाह अजीज़ रहमान को इसका खण्डन जारी करना पड़ा ।[6]

स्पष्ट है कि परिसंघ बनाने का यह विचार उन लोगों का था जो बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के परिसंघ में अन्य पड़ोसी देशों को भी आकर्षित करने का इरादा रखते थे ताकि उन्हें भारत के खिलाफ गोलबंद किया जा सके । जबकि भारत में लोहिया आदि जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान-बांग्लादेश के परिसंघ की मांग उठायी, वह समग्रतावादी दृष्टि से प्रेरित थे ।[7]

---

5. दि डॉन, कराची, अगस्त 3, 1978
6. दि टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, जुलाई 2, 1961
7. प्रो. वीरेन्द्र नारायण से भेंटवार्ता पर आधारित, देखें - परिशिष्ट, पृ. 84

लेफ. जन. इरशाद एवं जन. जिया उल हक की पहली मुलाकात में इरशाद ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने पर बल दिया, जिसके लिए पूर्व राष्ट्रपति जियाउर्रहमान ने प्रयास शुरू किये थे । दूसरी ओर अगस्त 1983 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री साहबजादा याकूब खान ने अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान बांग्लादेश से आह्वान किया कि वह अतीत को भूल कर पाकिस्तान के साथ सुनहरे भविष्य हेतु कार्य करें । किन्तु अतीत को भुलाने की यह मांग हास्यास्पद ही कही जा सकती है ।

1985 में तूफानी चक्रवात से बांग्लादेश में हुए विनाश के बाद जिया उल हक ने वहां की यात्रा की । `बंग-भवन` में एक संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए उन्होंने भावनात्मक अन्दाज में कहा कि, `बांग्लादेश का दु:ख पाकिस्तान का दु:ख एवं बांग्लादेश की खुशी पाकिस्तान की खुशी है ।`[8] किन्तु `बिहारियों` की वापसी एवं `परिसम्पत्तियों` के बंटवारे के मुद्दों पर जियाउल हक ने यही भावात्मक एकता नहीं दिखाई, उल्टे बांग्लादेश पर भारीमात्रा में आर्थिक देन-दारियां आरोपित कर दीं ।

1988 में विमान दुर्घटना में जिया उल हक की मृत्यु के उपरान्त पाकिस्तान में लोकतन्त्र का मार्ग प्रशस्त हुआ । बेनजीर भुट्टो के प्रधान-मंत्री बनने का राष्ट्रपति इरशाद ने स्वागत किया एवं पाकिस्तान से सम्बन्धों में और सुधार की आशा व्यक्त की । बेनजीर अपने गृह प्रान्त सिन्ध की जनता (सिन्धी) के भारी विरोध के कारण `बिहारियों` को वापस लेने की स्थिति में नहीं थी, किन्तु अक्टूबर 1989 में अपनी बांग्लादेश यात्रा के समय आर्थिक प्रबन्ध एवं सिंध प्रान्त में कानून व्यवस्था

---

8. दि न्यू नेशन, ढाका, जून 6, 1985

की स्थिति ठीक होते ही पुनर्वापसी कार्यक्रम शुरू करने का आश्वासन दिया । बेनजीर ने कहा कि, 'बांग्लादेश एवं पाकिस्तान धर्म, इतिहास एवं परम्परा के बंधन में बंधे हैं । हमने साथ-साथ मुस्लिम पहचान के लिए संघर्ष किया... किन्तु 'दो भाइयों ' के अलग-अलग घर होते हुए भी हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिसमें हमेशा एक-दूसरे के कल्याण एवं सुरक्षा का ख़याल रखा जाता है ।'[9]

उल्लेखनीय है कि यह वह दौर था जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी से बेनजीर भुट्टो की अच्छी समझ बनी थी एवं दोनों देशों के सम्बन्धों में सुधार की आशाएं थीं । किन्तु बेनजीर जिस परिवार की बात कर रही थीं, वह उनकी दृष्टि में 'मुस्लिम-परिवार' था । 'धर्म, इतिहास एवं परम्परा' के आधार पर भारत इस परिवार में 'बड़े भाई ' की भूमिका में आता है, लेकिन पाकिस्तानी शासकों की मनो-वृत्ति के अनुरूप बेनजीर केवल 'धर्म ' को ही परिवार का आधार मान रही थीं, जिसका खोखलापन 1971 तक बांग्लादेश के शोषण एवं 1971 में बांग्लादेश के उदय के रूप में सामने आ चुका था ।

1990-91 ऐसा संक्रमणकाल था, जब अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कई परिवर्तन आये । सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध की समाप्ति एवं खाड़ी संकट के साथ ही अमेरिका का एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरना। ये घटनाएं बांग्लादेश-पाकिस्तान को निकट लाने में सहायक सिद्ध हुईं । घरेलू स्तर पर बांग्लादेश में भी लोकप्रिय जनमत के दबाव में सैनिक शाही की विदाई तथा संसदीय लोकतंत्र की वापसी हुई । बेगम खालिदा जिया के नेतृत्व में बी. एन. पी. की सरकार बनना पाकिस्तान के लिए अधिक सुविधाजनक था । बेगम जिया ने भूतपूर्व राष्ट्रपति जियाउर्रहमान की नीतियों को जारी रखने का संकेत दिया । पाकिस्तानी प्रधान मंत्री नवाज़ शरीफ ने भी लचीला रुख अपनाते हुए 'बिहारियों ' की

---

9. दि पाकिस्तान टाइम्स, लाहौर, अक्टूबर 2, 1989

पाकिस्तान वापसी की प्रक्रिया शुरू की (1992) एवं 'परिसम्पत्तियों एवं आर्थिक देनदारियों' के निर्धारण हेतु शीघ्र प्रयास का आश्वासन दिया ।

सितम्बर 1993 में बांग्लादेश सरकार ने पाकिस्तान के साथ 1992 में हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समझौते तथा राजनयिक मिशनों के लिए भूमि के पट्टे सम्बन्धी समझौते की पुष्टि कर दी ।[10]

1996 के चुनावों के बाद बांग्लादेश में शेख हसीना वाजेद के नेतृत्व में अवामी लीग सत्ता में आया । अवामी लीग का झुकाव भारत की ओर अधिक माना जाता है । भारत में संयुक्त मोर्चा सरकार से बांग्लादेश के सद्भावनापूर्ण सम्बन्ध विकसित हुए तथा गंगा-जल के बंटवारे पर सन्धि हुई जो दोनों देशों के बीच 1972 से ही एक प्रमुख विवाद रहा है । किन्तु शेख हसीना ने पाकिस्तान के साथ भी मित्रतापूर्ण सम्बन्धों पर बल देते हुए 25 मार्च 1997 को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के स्वर्ण जयंती समारोहों के उपलक्ष्य में आयोजित ओ.आई.सी. की असाधारण शिखर बैठक में भाग लिया । इस यात्रा का उद्देश्य पाकिस्तान से निकट सम्बन्ध तथा संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठक शीघ्र आयोजित करवाना भी बताया गया ।[11] इससे पहले 5 मार्च 1997 को बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुस समद आजाद शरीफ के पुन: प्रधानमंत्री

---

10. कौशिक, एस.एन., 'पाकिस्तान-बांग्लादेश रिलेशन्स ड्यूरिंग बेनजीर भुट्टो एण्ड नवाज़ शरीफ रिजीम्स', उद्धृत, चक्रवर्ती, एस.आर. (सम्पा.) - 'फॉरेन पॉलिसी ऑफ बांग्लादेश', पृ0 212

11. एशियन रिकॉर्डर, अप्रैल 9-15, 1997, पृ0 26367

बनने के बाद पाकिस्तान यात्रा पर आने वाले प्रथम विदेश मंत्री थे जिन्होने द्वीपक्षीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों देशों की नीतियों में समन्वय हेतु बातचीत की ।

इस संदर्भ में जनवरी 1998 में ढाका में भारत-पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों का शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण घटना थी । यद्यपि यह वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए आयोजित किया गया किन्तु अनौपचारिक बातचीत एवं सम्मेलन के बाद नवाज़ शरीफ की औपचारिक बांग्लादेश यात्रा में राजनीतिक पक्षों पर भी विचार-विमर्श हुआ । आर्थिक सहयोग के लिए सर्वाधिक वांछित परिस्थिति आपसी विश्वास एवं `बयानबाजी` के इतिहास से मुक्ति की आवश्यकता है ।

17 जनवरी 1998 को ढाका में शैख हसीना द्वारा आयोजित भोज के अवसर पर नवाज़ शरीफ ने स्वीकार किया कि `यदि 1970 के चुनावों का सम्मान किया जाता तो इस क्षेत्र का इतिहास दूसरा होता ।`[12] शरीफ ने 1971 के घटनाक्रम को तत्कालीन पाकिस्तानी शासकों की `भारी-भूल` के रूप में निरूपित किया । वास्तव में नवाज़ शरीफ़ ने जहां एक ओर भारत को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास किया वहीं अवामी लीग की पाकिस्तान के प्रति परम्परागत विरोधपूर्ण नीति की धार को कम करना भी उनका उद्देश्य था । इसके लिए उन्होंने बिहारियों की वापसी का कार्यक्रम शीघ्र शुरू करने की घोषणा की । किन्तु 1971 की घटनाओं के लिए बांग्लादेश द्वारा पाकिस्तान से `क्षमा-याचना` करने की मांग के कारण दोनों ओर से कुछ कटु बयानबाजी भी हुई । दोनों ही देशों की सरकारें सम्बन्धों के भावी सुधार हेतु आर्थिक क्षेत्र में अधिकाधिक सहयोग करने पर सहमत हैं ।

---

12. एशियन रिकॉर्डर, फरवरी 19-25, 1998, पृ० 27101

'सुरक्षा' सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य का भी बांग्लादेश-पाकिस्तान सम्बन्धों में महत्व है । सुरक्षा के अन्तर्गत आंतरिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा तथा बाह्य आक्रमण से सुरक्षा को शामिल किया जा सकता है ।

बांग्लादेश में पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी आई. एस. आई . की विध्वंसक एवं अस्थिरताकारक गतिविधियां दोनों देशों के बीच कई बार तनाव का विषय बनी हैं । शेख मुजीब की हत्या के बाद ही आई. एस. आई . ने बांग्लादेश में अपनी जड़ें जमा लीं तथा इसके साथ ही भारत विरोधी तोड़-फोड़ के कार्यक्रम बनाने शुरू किये । नागालैण्ड, असम, त्रिपुरा एवं मिजोरम के विद्रोहियों को बांग्लादेश में प्रशिक्षण देना शुरू किया । उल्लेखनीय है कि आई. एस. आई . की ये गतिविधियां सैनिक शासकों एवं मुस्लिम कट्टरपंथियों की सरपरस्ती में पनपीं ।आई. एस. आई . ने अपनी गतिविधियों के प्रतिकूल रुख वाली शेख हसीना सरकार को अस्थिर करने के प्रयास भी शुरू किये, क्योंकि भारत से अच्छे सम्बन्धों की स्थापना के लिए शेख हसीना ने सत्ता संभालने के बाद आई. एस. आई . द्वारा संचालित भारत विरोधी आतंकवादियों के कई प्रशिक्षण शिविरों को बंद कर दिया था ।[13] ढाका, चिटगांव, सिलहट एवं खुलना में आई. एस. आई. को अपने कई कार्यालय बंद करने पड़े । उल्लेखनीय है कि आई. एस. आई. का दो वर्ष पूर्व भारत के प. बंगाल राज्य के पुरुलिया जिले में विमान से हथियार गिराये जाने की घटना में हाथ था । नेपाल के रास्ते वह आतंकवाद एवं तस्करी को बढ़ावा देती रही है ।

मादक पदार्थों एवं बांग्लादेशी नागरिकों की तस्करी भी बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के बीच सामाजिक सुरक्षा का एक प्रमुख मुद्दा है । दक्षिण

---

13. एशियन रिकॉर्डर, जनवरी 1-7, 1997, पृ0 26143

एशिया में 4.4 मिलियन लोग नशीली दवाओं का सेवन करते हैं जिनमें 2.2 मिलियन हेरोइन का नशा करते हैं । इनमें से 1.5 मिलियन अकेले पाकिस्तान में हैं । भारत में 2.5 से 5 लाख के बीच तथा शेष बांग्लादेश एवं श्रीलंका में हैं ।[14] उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान एवं बांग्लादेश क्रमश: तस्करी के लिए कुख्यात `गोल्डन क्रेसेंट` एवं `गोल्डन ट्राइएंगल` के शीर्ष भागों पर स्थित है ।

पश्चिमी मुस्लिम देशों (अरब देशों) में ऊंट दौड़ों में `जॉकी` के रूप में इस्तेमाल किये जाने के लिए बांग्लादेशी बच्चों की भारत होते हुए, पंजाब में अमृतसर के रास्ते, तस्करी की जाती है ।[15] इसके अलावा बांग्लादेशी जवान महिलाओं को पाकिस्तानी स्पेंट खरीद कर पाकिस्तानी या अरब देशों के `बाजार` में बेच देते हैं ।

उपर्युक्त दोनों ही समस्याएं मानवीय सभ्यता पर कलंक हैं तथा बांग्लादेश एवं पाकिस्तान सरकारें भारत के सहयोग से इनके प्रभावी समाधान हेतु प्रयास करने में विफल रही हैं ।

बांग्लादेश में आने वाले तूफानी चक्रवात भी उसकी आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रमुख चुनौती रहे हैं तथा पर्यावरण सुरक्षा एवं राहत के रूप में उसे अन्य देशों के साथ ही पाकिस्तान की मदद की भी जरूरत होती है । मई 1991 में पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री नवाज़ शरीफ ने अपनी ढाका यात्रा के दौरान तूफान से हुए विनाश से राहत में सहयोग देते हुए बांग्लादेश को 25000 टन चावल, 50000 मीटर कपड़ा, 2 टन दवाइयां, 5000 तम्बू आदि उपलब्ध करवाये । इसके साथ ही बांग्लादेश

---

14. दि हिन्दू, नई दिल्ली, मई 18, 1998
15. प्रो. वीरेन्द्र नारायण से भेंटवार्ता पर आधारित, देखें - परिशिष्ट, पृ: 85

को 10 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की ।[16] इसी प्रकार 1985 में तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति जिया उल हक ने बांग्लादेश की मदद मुहैया करवायी थी ।

सुरक्षा के बाह्य परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से बांग्लादेश एवं पाकिस्तान की भौगोलिक दूरी उन्हें घनिष्ठ सुरक्षा या सैनिक सम्बन्धों की अनुमति नहीं देती । दोनों ही देश भारत को अपनी सुरक्षा के लिए प्रमुख खतरा मानते हैं । इसलिए पाकिस्तान छठे दशक में सिएटो एवं सेण्टो सैनिक सन्धियों का सदस्य बना तथा चीन एवं अमेरिका से भारी मात्रा में शस्त्रास्त्र एकत्रित किये । बांग्लादेश ने भी म्यांमार के रास्ते चीन से हथियारों का आयात किया किन्तु बांग्लादेश एवं पाकिस्तान आपस में कोई वृहद् सैनिक रणनीति नहीं बना सके । वास्तव में बांग्लादेश भारत से इस तरह घिरा हुआ है कि वह इस स्थिति में हो भी नहीं सकता ।

बांग्लादेश के पास अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी के निरीक्षण में एक परमाणु रिएक्टर है तथा उसका कोई सैनिक परमाणु कार्यक्रम नहीं है । 1995 में 'परमाणु अप्रसार सन्धि' के अनिश्चितकालीन विस्तार के समय बांग्लादेश ने गैर परमाणविक देशों को सुरक्षा आश्वासन दिये जाने तथा दक्षिण एशिया में 'परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र' बनाये जाने की मांग की । स्पष्ट है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से इस सन्दर्भ में कोई खतरा नहीं है । उसका दृष्टिकोण भारत से सुरक्षा आशंकाओं से ही निर्धारित था ।

बांग्लादेश के भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों के बारे में दृष्टिकोण का उसके पाकिस्तान से सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ता है । मुजीब के काल में

बांग्ला देश का रुख भारत समर्थक था । `कश्मीर` के प्रश्न पर मुजीब ने भारतीय पक्ष का समर्थन किया । तत्कालीन बांग्लादेशी विदेश मन्त्री अब्दुस समद आजाद ने कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा जनमत संग्रह की मांग को अनाधिकारपूर्ण बताते हुए कहा कि पाकिस्तान ने पूर्वी बंगालको यही अधिकार देने से इन्कार कर दिया था । 2 जुलाई 1972 को भारत एवं पाकिस्तान के बीच `शिमला-समझौते` को `सही दिशा में सही कदम` बताया एवं इसकी प्रशंसा की ।[17] किन्तु बाद की सरकारों का रुख `कश्मीर` के बारे में बदलता रहा है । जियाउर्रहमान ने संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के कश्मीर सम्बन्धी प्रस्ताव के महत्व को स्वीकार किया । इरशाद ने कश्मीर विवाद के कारण दक्षिण एशिया में तनावों एवं अस्थिरता की आशंका जताते हुए 1989 में बेनजीर भुट्टो की बांग्ला-देश यात्रा के दौरान भारत-पाकिस्तान के बीच `परमाणु-प्रतिष्ठानों पर अनाक्रमण` सम्बन्धी समझौते का स्वागत किया । इरशाद ने दक्षिण एशिया में `परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र` की पाकिस्तानी मांग का पूर्ण समर्थन किया ।[18]

अगस्त 1992 में बेगम जिया ने कश्मीर में हिंसक घटनाओं तथा इससे भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने पर चिन्ता व्यक्त की । किन्तु बेनजीर भुट्टो के द्वितीय कार्यकाल के दौरान जब उनका भारत-विरोधी स्वर अधिक प्रखर था, बेगम जिया ने उनके सुर से सुर मिलाकर कश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुरूप हल किये जाने की मांग की ।

---

17. दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, जुलाई 16, 1972
18. दि पाकिस्तान टाइम्स, लाहौर, अक्टूबर 2, 1989

इस संदर्भ में बांग्ला देश का रुख ओ.आई.सी. की बैठकों में लिये गये निर्णयों से भी झलकता है, जिसका बांग्लादेश सदस्य है । 25 मार्च, 1997 को इस्लामाबाद में हुई इस संगठन के देशों की विशेष बैठक में कश्मीर विवाद के निपटारे हेतु `भारत के मित्र` के रूप में `संयुक्त राष्ट्र` के प्रस्तावों को लागू करने की मांग की ।[19] इसी प्रकार दिसम्बर 1997 में तेहरान में हुए ओ.आई.सी. शिखर सम्मेलन में कश्मीर समस्या पर एक सम्पर्क-दल का गठन किया गया। क्योंकि बांग्लादेश ने इन प्रस्तावों का विरोध नहीं किया, इसलिए इनमें उसकी भी मौन सहमति मानी जा सकती है । किन्तु शेख हसीना सरकार भारत से सम्बन्ध सुधारने को प्रयासरत है एवं प्रकट रूप में कश्मीर को भारत-पाकिस्तान की द्विपक्षीय समस्या मानती रही है ।

भारत एवं पाकिस्तान द्वारा मई 1998 में किये गये परमाणु विस्फोटो को बांग्लादेश दक्षिण एशिया की शान्ति एवं विकास के लिए गम्भीर खतरा मानता है । बांग्लादेश के कई बुद्धिजीवियों एवं राजनीतिक विचारकों ने भारत के परमाणु-विस्फोटों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इन्हें `बहुत-बुरा`, `क्षेत्रीय स्थिरता` के लिए खतरा, `जनकल्याण एवं विकास में बाधक` तथा `क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में परिवर्तनकारी` बताया ।[20]

सरकारी स्तर पर भारत एवं पाकिस्तान के परमाणु विस्फोटो पर संयत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दोनों देशों के बीच आपसी वार्ता का आग्रह किया गया ताकि उसके बाद उपजे तनाव को दूर किया जा सके । शेख हसीना ने जून-जुलाई 1998 में भारत एवं पाकिस्तान की यात्रा की परन्तु दोनों के बीच मध्यस्थता से इन्कार किया ।

---

19. एशियन रिकॉर्डर, अप्रैल 30 - मई 6, 1997, पृ० 26424
20. खलीज़ टाइम्स, यू. ए. ई., मई 13, 1998

पाकिस्तान का भारत-बांग्लादेश सम्बन्धों के बारे में दृष्टिकोण प्रारम्भ में काफ़ी नकारात्मक रहा था । भुट्टो ने बांग्लादेश को भारत के हाथ की कठपुतली करार दिया । मुजीब की हत्या के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत पर बांग्लादेश की सीमाओं पर सैनिक जमा करने का आरोप लगाया ताकि बांग्लादेश में अपनी `पिट्ठू` सरकार बनायी जा सके ।[21]

पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भारत के साथ द्विपक्षीय विवादों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने के लिए प्रेरित किया एवं 1976 के बाद से संयुक्त राष्ट्र में फरक्का विवाद उठाये जाने पर उसका समर्थन किया । शेख हसीना की सरकार के आगमन के बाद भारत-बांग्लादेश के बीच गंगाजल के वितरण पर हुई संधि से दोनों देशों के बीच सद्भावपूर्ण सम्बन्ध बनना पाकिस्तान के सैनिक प्रतिष्ठान के लिए असुविधाजनक है तथा वह आई. एस. आई. के माध्यम से बांग्लादेश के कट्टरवादी तत्वों को इस संधि का विरोध करने के लिए प्रेरित कर रहा है ।

सार्क के अंतर्गत बांग्लादेश-पाकिस्तान सम्बन्ध

1977 में जियाउर्रहमान ने पाकिस्तान यात्रा के दौरान ही `दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग` का विचार दिया किन्तु प्रारम्भ में भारत एवं पाकिस्तान दोनों ने इस ओर विशेष उत्सुकता नहीं दिखाई । भारत की पहल को उसके `वर्चस्ववादी` इरादों का नाम दिये जाने की

---

21. कौशिक एस. एन., `पाकिस्तान्स रिलेशन्स विद् बांग्लादेश : एन ओवरव्यू ऑफ दि परसेप्शन ऑफ दि लीडर्स ऑफ दी टू कन्ट्रीज़`, उद्धृत, चक्रवर्ती एस. आर. एण्ड नारायण वीरेन्द्र (सम्पा.), `बांग्लादेश : ग्लोबल पॉलिटिक्स`, वॉ. 3, नई दिल्ली, साउथ एशिया पब्लिशर्स, 1994, पृ0 160

आशंका से भारत का ठण्डा रुख उचित था । 1985 में ढाका में सार्क की स्थापना के समय इसके चार्टर में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया कि 'द्विपक्षीय विवादों' को इस मंच पर नहीं उठाया जायेगा । किन्तु पाकिस्तान इसके शिखर सम्मेलनों में कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है ।

भारत एवं पाकिस्तान के विवादों से सार्क की प्रगति बाधित हुई है । बांग्लादेश ने सार्क की बैठकों में दक्षिण एशिया में परमाणु हथियारों से मुक्त क्षेत्र की पाकिस्तानी मांग का समर्थन किया किन्तु सर्वसम्मति के अभाव में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका । भारत-पाकिस्तान तनाव के चलते ही बांग्लादेश आदि देश सार्क के अन्तर्गत उप-क्षेत्रीय सहयोग हेतु प्रेरित हुए हैं जिसका पाकिस्तान ने विरोध किया ।

अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, खाड़ी युद्ध एवं चीन से सम्बन्धों के संदर्भ में बांग्लादेश एवं पाकिस्तान सरकारों में सहमति रही है ।

अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप पर जियाउर्रहमान ने पाकिस्तान के रुख का बचाव किया तथा इसे दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिए खतरा बताया । इरशाद ने अपने कार्यकाल में अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी तथा अफगान लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार देने की मांग की ।

इसमें बांग्लादेश का सुरक्षात्मक भय नहीं अपितु मुस्लिम देशों की सहानुभूति बटोरने का प्रयास था । बांग्लादेश की वर्तमान सरकार का रुख अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी रुख से अलग है तथा वह अफगानी लोगों को ही उन के भविष्य निर्धारण का अधिकार दिये जाने की पक्षधर है ।

---

22. दि मुस्लिम, इस्लामाबाद, फरवरी 18, 1983

अध्याय - चतुर्थ

बांग्लादेश - पाकिस्तान : आर्थिक सम्बन्ध

द्विपक्षीय सम्बन्धों में आर्थिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है । बांग्लादेश एवंपाकिस्तान के बीच आर्थिक सहयोग व्यापार के क्षेत्र में अधिक है । 1971 के युद्ध एवं बांग्लादेश के उद्भव ने उन व्यापार संबंधों को गहरा आघात पहुंचाया जो 1947 के बाद पाकिस्तान की दोनों शाखाओं (पूर्वी एवं पश्चिमी) के बीच विकसित हुए थे । दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्थाएं चरमराने की स्थिति में पहुंच गईं क्योंकि संयुक्त पाकिस्तान का आर्थिक ढाँचा उसकी दोनों शाखाओं की परिपूरकता पर आधारित था ।[1] पाकिस्तानी सरकार की आर्थिक नीतियों ने संपूर्ण पाकिस्तान की `एकीकृत अर्थव्यवस्था` के विकास के प्रयास में इन परि-पूरकताओं को और गहन बनाया । किन्तु `परिपूरकताओं ` के आधार पर `अर्थव्यवस्था` का यह विकास `स्वस्थ` नहीं था ।

पश्चिमी भाग की औपनिवेशिक नीतियों के कारण पूर्वी भाग का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो गया । व्यापार, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, बीमा एवं बैंकिंग क्षेत्र आदि पर पश्चिमी पाकिस्तान के पूंजीपतियों का स्वामित्व था । 1947 से ही पूर्वी बंगाल से किये गये निर्यात पाकिस्तान के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्ति के एकमात्र स्रोत होने के बावजूद बंगालियों को उनका समुचित हिस्सा नहीं मिला । संयुक्त पाकिस्तान में जिस तरह की आर्थिक परिपूरकताएं विकसित हुईं, उसके स्वरूप को साम्राज्यवादी एवं औपनिवेशिक कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी । पूर्वी भाग कच्चे माल की आपूर्ति करता था एवं पश्चिमी भाग के उद्योगों से निर्मित माल तैयार कर पुन: पूर्वी भाग में बेच दिया जाता था । महत्वपूर्ण है कि पूर्वी भाग के व्यापार-अधिशेष का इस्तेमाल भी पश्चिमी भाग के औ-द्योगीकरण हेतु किया गया । इसलिए शेख मुजीब ने अपने छ:-सूत्री कार्यक्रम

---

1. दिलारा चौधरी, `बांग्लादेश एण्ड दिसाउथ एशियन...`, ढाका, एकेडमिक पब्लिशर्स, 1992, पृ0 291

में आर्थिक स्वायत्तता पर जोर दिया । 1971 में बांग्लादेश के उद्भव के बाद पाकिस्तान के साथ आर्थिक सम्बन्धों के विकास को तीन चरणों में समझा जा सकता है --

1. प्रारम्भिक चरण

शेख मुजीब के शासन काल को इसके अंतर्गत रखा जा सकता है, जब बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के बीच आर्थिक सहयोग नगण्य रहा । यद्यपि बांग्लादेश की मुक्ति के निकट पूर्व तक दोनों भागों में पर्याप्त व्यापार जारी था । 1969-70 में पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान को लगभग 167 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया, जबकि पूर्वी भाग से 173 करोड़ रुपए का आयात किया । यह व्यापार 1971 में घट कर क्रमश: 47.40 करोड़ रुपए एवं 38 करोड़ रुपए रह गया । इस दौरान पश्चिमी भाग से पूर्वीभाग को निर्मित वस्त्र, चावल, मशीनें, चीनी, रसायन, दवाइयां, कपास आदि की आपूर्ति होती थी जबकि पूर्वी भाग से कच्चा जूट, चाय, टाट एवं इमारती लकड़ी आदि मंगवाया जाता था ।[2]

1971 के बाद पाकिस्तान की दोनों पूर्व शाखाओं के लिए व्यापार सम्बन्धों के समायोजन की अनिवार्यता के बावजूद राजनीतिक शत्रुता के कारण यह बहुत कठिन था । भारतीय वस्तुओं द्वारा पाकिस्तान से आयातों की क्षतिपूर्ति का बांग्लादेश का प्रयास पूर्णत: सफल नहीं हुआ वहीं पाकिस्तान को अपने उत्पादों के लिए बाजार नहीं मिल पा रहा था ।

---

1. कौशिक एस. एस., 'पाकिस्तान्स रिलेशन्स विद् बांग्लादेश...', उद्धृत, चक्रवर्ती, एस आर एण्ड नारायण, वीरेन्द्र, 'बांग्लादेश : ग्लोबल पॉलिटिक्स', नई दिल्ली, साउथ एशिया पब्लिशर्स, 1988, पृ० 161

1974 तक दोनों देशों ने आपसी व्यापार एवं आर्थिक सम्बन्धों का महत्व पुन: समझा एवं पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश को मान्यता देने में इस पक्ष का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा । यद्यपि सामूहिक परि-सम्पत्तियों के बंटवारे का मुद्दा अभी भी था, किन्तु सरकारी एवं निजी क्षेत्र में व्यापार सम्पर्क पुन: स्थापित हुए ।

2. द्वितीय चरण

शेख मुजीब की हत्या (अगस्त, 1975) के उपरान्त से 1990 तक बांग्लादेश में सैनिक शासन रहा । दोनों देशों के सैनिक शासकों ने कई क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया ।

अप्रैल 1976 में व्यापार समझौते के पहले ही 1974 से व्यापार में वृद्धि की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी किन्तु इसमें किसी तीसरे देश को माध्यम बनाना पड़ा । उपर्युक्त व्यापार समझौता प्रारम्भ में तीन वर्ष के लिए किया गया जिसमें उतनी ही अवधि के लिए स्वत: पुनर्नवीकरण की व्यवस्था थी । इसमें सर्वाधिक वरीयता वाले राष्ट्र का दर्जा देने, दोनों देशों में व्यापार के भावी विस्तार एवं वैविध्य की निगरानी के लिए संयुक्त समिति बनाने तथा मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में वस्तुओं के विनिमय के प्रावधान किये गये ।

दिसम्बर 1977 में राष्ट्रपति जियाउर्रहमान की पाकिस्तान यात्रा के समय दोनों सरकारें सहमत हुईं कि 1971 के पहले जैसी व्यापार-व्यवस्था की स्थापना से दोनों देशों को लाभ होगा । 1977-78 में पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश को निर्यातों का मूल्य 26 करोड़ रुपए था जबकि आयात 49 करोड़ रुपए का किया गया जो बढ़ कर 1980-81 में क्रमश: 64.6 करोड़ रुपए एवं 71.1 करोड़ रुपए हो गया ।[3]

---

3. दि डॉन, कराची, जुलाई 28, 1986

1979 में दो महत्वपूर्ण समझौते हुए । प्रथम - 'संयुक्त आर्थिक आयोग' की स्थापना से संबंधित था जिस पर जुलाई में बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री सैफुर रहमान की पाकिस्तान यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किये गये तथा द्वितीय - दोहरे कराधान से बचने हेतु सहमति (अक्टूबर 1979) हुई । जुलाई 1979 में ही 'संयुक्त आर्थिक आयोग' की प्रथम बैठक में द्विपक्षीय व्यापार की समीक्षा के साथ ही जहाजरानी, संयुक्त उद्यम, तकनीकी सहयोग, संयंत्रों एवं फैक्ट्रियों के निर्यात, उड्डयन आदि क्षेत्रों की सहयोग हेतु पहचान की गई ।

फरवरी 1982 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को अफगान शरणार्थियों के लिए द्विपक्षीय समझौते के आधार पर 2.2 मिलियन पाउण्ड चाय निर्यात की ।[4] यद्यपि इसी वर्ष बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 10 लाख टन चावल का आयात किया क्योंकि वहां आकस्मिक रूप से खाद्यान्न उत्पादन कम हो गया था ।

दोनों देशों के वाणिज्यिक प्रतिनिधिमण्डलों के बीच भी सम्पर्क बढ़ा एवं जून 1984 में एक संयुक्त 'चैम्बर आफ कामर्स' की स्थापना की गई । 27 जुलाई 1986 को बांग्लादेश व्यापार निगम (टी.सी.बी.) एवं पाकिस्तान व्यापार निगम (टी.सी.पी.) ने दो वर्ष के लिए 'विशिष्ट व्यापार समझौता' (स.टी.ए.) सम्पन्न किया जिसमें लगभग 4 करोड़ डॉलर मूल्यों की वस्तुओं के प्रतिवर्ष विनिमय का प्रावधान था। व्यापार क्षेत्रों के विस्तारण के लिए बांग्लादेश एवं पाकिस्तान 'एशियाई निष्पादन संघ' (ए.सी.यू.), जिसमें ईरान, भारत, नेपाल, श्रीलंका एवं बर्मा भी थे, के सदस्य बन गये ।

---

4. दि पाकिस्तान टाइम्स, लाहौर, फरवरी 7, 1982

1976 से 1986 के दशक में दोनों देशों के बीच व्यापार का आकार तिगुना हो गया । 1976 में यह 33.41 मिलियन यू.एस. डॉलर था, जबकि 1986 में 110 मि. डॉलर ।[5] 1985 में केवल निजी क्षेत्र के व्यापार का मूल्य ही 40 मिलियन डॉलर था तथा इसे 100 मि. डॉलर तक बढ़ाने की संभावना व्यक्त की गई ।[6]

पाकिस्तान 1983-84 एवं 1984-85 में बांग्लादेशी वस्तुओं का चौथा सबसे बड़ा आयातक देश था जबकि 1985-86 में तीसरा । इस दौरान उसने बांग्लादेश के कुल विश्व व्यापार का क्रमश: 8.1 प्रतिशत, 5.7 प्रतिशत एवं 7.10 प्रतिशत आयात किया । किन्तु 1986-87 से बांग्लादेश से चाय निर्यात कम होने के कारण यह प्रतिशत कम होता गया । दूसरी ओर बांग्लादेश के कुल आयातों में पाकिस्तान से किये जाने वाले आयातों का प्रतिशत 1983-84 में 1.43 प्रतिशत, 1984-85 में 1.15 प्रतिशत, 1985-86 में 2.24 प्रतिशत एवं 1986-87 में 0.77 प्रतिशत था ।

इस दौरान जहां पाकिस्तान बांग्लादेश के कच्चे जूट एवं चाय का सबसे बड़ा आयात कर्ता रहा वहीं बांग्लादेश को निर्यातों में कपास एवं वस्त्र सर्वप्रमुख रहे ।

जुलाई 1988 में पाकिस्तान के वित्त मंत्री डॉ. महबूबुल हक ने बांग्लादेश यात्रा के दौरान अपने बांग्लादेशी समकक्षसे व्यापार में और

---

5. अबु ताहिर सलाउद्दीन अहमद, 'बांग्लादेश-पाकिस्तान रिलेशन्स ....', उद्धृत, इफतेखारुज्जमन एण्ड इम्तियाज़ अहमद (सम्पा.) 'बांग्लादेश एण्ड सार्क...', ढाका, एकेडमिक पब्लिशर्स, 1992, पृ0 195

6. मॉर्निंग न्यूज, कराची, दिसम्बर 10, 1985

वृद्धि के अर्थोपायों पर चर्चा की । डॉ. हक ने बांग्लादेश को मशीनें एवं उपकरण खरीदने, जिनमें रेल के डिब्बे, बसें, रोड़ रोलर आदि शामिल हैं, के लिए 5 करोड़ अमेरिकी डालर का ऋण उदार शर्तों पर देने का प्रस्ताव किया ।[7] बांग्लादेश के आग्रह पर पाकिस्तान ने एक लाख टन सीमेंट एवं तीस हजार टन चीनी की आपूर्ति पर भी सहमति व्यक्त की । बांग्लादेश में विदेशी मुद्रा की कमी की समस्या का ध्यान रखते हुए पाकिस्तान ने 4 करोड़ डालर तक आयातों का भुगतान टका में करने की छूट दी जो कि बांग्लादेश की अपनी मुद्रा है । डॉ. हक ने कहा कि पाकिस्तान ने चीन से औद्योगिकरण सम्बन्धी तकनीकें हासिल की हैं एवं वह अपने अनुभव बांग्लादेश से बाँटने का इच्छुक है ।[8]

जुलाई 1989 में ढाका में संयुक्त आर्थिक आयोग की तृतीय बैठक के अवसर पर पाकिस्तानी वित्त राज्य मंत्री ई. एच. पिराचा ने संयुक्त उद्यमों की स्थापना का प्रस्ताव किया । पाकिस्तान इसके लिए तकनीकी जानकारी , कच्चे माल एवं मशीनों की आपूर्ति को तैयार था जबकि वित्त की व्यवस्था पूंजी निर्यातक देशों या अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को करनी थी ।

3. तृतीय चरण

1990-91 के दौरान वैश्विक पटल पर राजनीति के साथ-साथ आर्थिक परिदृश्य में भी परिवर्तन शुरू हुआ । दक्षिण एशिया के देशों में भी अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया के चलते श्री लंका में 1988-89 में पाकिस्तान में 1990-91 भारत में 1991-92 एवं बांग्लादेश में 1992 में ढांचागत समायोजन कार्यक्रम लागू किये गये ।

---

7. दि डॉन, कराची, जुलाई 23, 1988
8. दि मुस्लिम, ढाका, जुलाई 28, 1988

बेगम ख़ालिदा जिया द्वारा आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत से बांग्लादेश की विदेश नीति में व्यापार का महत्व बढ़ा । भारत से बांग्लादेश का व्यापार 1990 में 192 मिलियन यू.एस. डॉलर से बढ़ कर 1994 में 512 मिलियन डॉलर हो गया । पाकिस्तान से भी व्यापार में वृद्धि हुई किन्तु यह भारत की तुलना में धीमी रही । 1990 में दोनों देशों के बीच 93 मिलियन डॉलर का व्यापार 1994 में 150 मिलियन डॉलर तक ही पहुंच पाया । इसमें से बांग्लादेश के पाकिस्तान को निर्यात 19 मि. डॉलर एवं पाकिस्तान से आयात 131 मि. डॉलर रहे जो पाकिस्तान के पक्ष में भारी व्यापार संतुलन को दर्शाता है ।[9]

पाकिस्तान को बांग्लादेशी निर्यातों में कमी का प्रमुख कारण चाय निर्यात में कमी रही । व्यापार वृद्धि के उद्देश्य से फरवरी 1992 में दोनों देश व्यवसायियों की संयुक्त समिति (जे.बी.सी.) बनाने पर सहमत हुए ।[10] 14 मार्च 1992 को ढाका में दोनों देशों के बीच बांग्लादेश में पाकिस्तान के सहयोग से 16600 टन चीनी उत्पादन क्षमता वाली मिल स्थापित करने का समझौता हुआ ।

जुलाई 1992 में पाकिस्तानी वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ (कराची) के एक प्रतिनिधि मंडल ने अपनी पांच दिवसीय बांग्लादेश यात्रा के दौरान नवीन क्षेत्रों में व्यापार संवर्द्धन तथा निजी क्षेत्र में संयुक्त उद्यम लगाने पर वार्ताएं कीं । पाकिस्तानी प्रतिनिधि मण्डल के नेता मियां हबीबुल्लाह ने बांग्लादेशी वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ के सदस्यों को सम्बोधित करते हुए सीमेंट, चीनी, आटोमैटिक मशीनों, कपड़ा, अन्य मशीनी उपकरणों

---

9. सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज : इन्फॉरमेशन हैण्डबुक, 1996-97

10. दि पाकिस्तान टाइम्स, लाहौर, फरवरी 15, 1992

एवं इंजीनियरिंग उत्पादों के क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों की स्थापना हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की । निजी क्षेत्र के लाभ हेतु पांच वर्षीय आर्थिक-वाणिज्यिक सहयोग समझौता सम्पन्न हुआ । उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के बीच व्यापार में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है ।[11]

संयुक्त आर्थिक आयोग की 1997 तक सात बैठकें हो चुकी हैं । इनमें व्यापार के वैविध्य के साथ ही गहनता पर बल दिया गया । बांग्लादेश-पाकिस्तान के बीच व्यापार की प्रमुख मदें इस प्रकार रही हैं :

बांग्लादेश से पाकिस्तान को निर्यात : कच्चा जूट एवं जूट निर्मित वस्त्र, चाय, ताम्बूल-पत्र, बाँस, हेम्प, नारियल-जटा, मछली, दवाइयां एवं अन्य रसायन, मसाले, इमली, इमारती लकड़ी, कागज एवं गत्ता, न्यूजप्रिंट, मशीनें, चमड़ा, हड्डियां एवं खालें, फल, लुग्दी, कच्चा रबर आदि ।

पाकिस्तान से बांग्लादेश को निर्यात : कपड़ा एवं सिले-सिलाये वस्त्र, कपास, चावल, सीमेंट, चीनी, पिसे हुए पत्थर, फल-सब्जियां, काफी, तिलहन, रंग, दवाइयां, धात्विक खनिज, इलेक्ट्रानिक मशीनें, परिवहन उपकरण, कोयला आदि ।

1980 के बाद से 1996 तक बांग्लादेश-पाकिस्तान व्यापार का आकार अग्रांकित सारणी नं0 1 में प्रदर्शित है तथा सारणी नं0 2 में सार्क एवं भारत से व्यापार के संदर्भ में तुलना की गई है ।

---

11. दि बांग्लादेश ऑब्जर्वर, ढाका, जुलाई 23, 1992

सारणी नं0 1

बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के बीच व्यापारिक सम्बन्ध
1980 से 1996 (यू. एस. मिलियन डालर में)

वर्ष	निर्यात	आयात	संतुलन
1980	55.3	34.90	+ 20.40
1985	41.5	35.28	+ 06.22
1990	23.0	70.00	- 47.00
1991	39.0	57.00	- 18.00
1992	30.0	88.00	- 48.00
1993	26.0	90.00	- 54.00
1994	19.0	131.00	- 112.00
1995	26.0	138.00	- 112.00
1996	35.0	87.00	- 52.00

स्रोत : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष : डाईरेक्शन आफ ट्रेड ईयर बुक
(विविध प्रकाशन)

सारणी नं0 - 2

बांग्लादेश का पाकिस्तान भारत एवं सार्क से कुल व्यापार
(तुलनात्मक प्रस्तुति : यू.एस. मिलि. डॉलर में)

वर्ष	पाकिस्तान	भारत	सार्क
1980	90.00	72.00	176
1985	77.00	92.00	182
1990	93.00	192.00	317
1991	96.00	212.00	335
1992	118.00	288.00	427
1993	116.00	393.00	535
1994	150.00	512.00	691

टिप्पणी : आंकड़े नजदीकी पूर्ण संख्या में हैं ।

स्रोत : सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज : इन्फॉरमेशन हैण्डबुक, 1996-97

सार्क देशों के अन्तर्गत 1990 से पूर्व पाकिस्तान बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापार साझीदार रहा है । बांग्लादेश का कुल व्यापार (सार्क के अन्तर्गत) भारत के साथ अधिक है किन्तु पाकिस्तान को उसके निर्यातों का अधिकांश हिस्सा जाता है । सारणी नं0 1 के अनुसार 1985 तक व्यापार संतुलन बांग्लादेश के पक्ष में रहा किन्तु इसके बाद यह पाकिस्तान के पक्ष में रहा । 1994 एवं 1995 के वर्षों के दौरान यह सर्वाधिक-112 मिलियन डॉलर प्रतिवर्ष रहा ।

सार्क देशों से बांग्लादेश का कुल व्यापार, 1994 में 691 मि. डॉलर था, जिसमें भारत के साथ 73.3% एवं पाकिस्तान के साथ 21.6 प्रतिशत था । शेष 5 प्रतिशत में अन्य देश थे । भारत हमेशा बांग्लादेश को पाकिस्तान की तुलना में सस्ती कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध कराने की स्थिति में है क्योंकि मालभाड़े के संदर्भ में भौगोलिक निकटता का बहुत महत्व है ।[12] इसलिए बांग्लादेश के लिए 'संभाव्य आयात लाभों' की तुलना के आधार पर भारत से व्यापार अधिक लाभप्रद है ।

बांग्लादेश-पाकिस्तान के बीच आर्थिक सहयोग की संभाव्यता

बांग्लादेश एवं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्थाओं की वर्तमान संरचना, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के अन्तर्गत द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग, उपक्षेत्रीय सहयोग की नवीन संकल्पना एवं त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन (ढाका) की परिघटनाओं ने दोनों देशों के आर्थिक सम्बन्धों को नवीन परिप्रेक्ष्य प्रदान किया है ।

---

12. अधिकारी, पी.सी. एवं बिस्वास एस., 'पॉटेंशियल गेन्स टू बांग्लादेशफॉर इम्पोर्ट ऑफ सलेक्टेड कॉमोडिटिज फ्रॉम इंडिया एण्ड पाकिस्तान', इंडिया क्वार्टरली 47 (4) अक्टू.-दिस. 1991, पृ0 66

बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में जी.डी.पी. की लगभग 5 प्रतिशत वृद्धि दर बनी हुई है । 1995-96 में प्रति व्यक्ति आय 265 यू.एस. डॉलर, औद्योगिक वृद्धि - 6 प्रतिशत, बेरोजगारी की दर (1991 की जनसंख्या के आधार पर) 18.5 प्रतिशत तथा बाजार मूल्य पर जी.डी. पी. का कुल आकार 32 मिलियन डॉलर था ।[13] 1995 में ऊर्जा उत्पादन की कुल संस्थापित क्षमता 2908 मेगावाट थी ।

बांग्लादेशी सरकार उद्योग क्षेत्र में नये निवेशों में वृद्धि के लिए नियमों का सरलीकरण तथा 100 प्रतिशत स्वामित्व सहित विदेशी उद्योगों की स्थापना की स्वीकृति दे रही है ।

बांग्लादेश में प्राकृतिक गैस के विशाल भण्डार पाये जाने से वह इसके निर्यात की स्थिति में आ गया है । लगभग 17 गैस क्षेत्रों में कुल 10 ट्रिलियन क्यूबिक फुट गैस भंडारों का पता चल चुका है तथा यह भंडार 80 से 100 ट्रिलियन क्यूबिक फुट तक हो सकता है ।[14]

किन्तु पिछले दो वर्षों से बांग्लादेशी मुद्रा टका का कई बार अवमूल्यन किया गया है । फरवरी 1998 के प्रारम्भ में ही यू.एस. डॉलर के मुकाबले 1.87 प्रतिशत अवमूल्यन किया गया तथा इसके बाद भी दो बार अवमूल्यन किया जा चुका है जिसका उद्देश्य निर्यात एवं विदेशी मुद्रा में वृद्धि करना है ।[15]

दूसरी ओर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का स्वरूप विदेशी सहायता

---

13 सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज : इन्फॉरमेशन हैंडबुक, 1996-97

14. खलीज टाइम्स, यू.ए.ई. फरवरी 13, 1998

15. राजस्थान पत्रिका, जयपुर, फरवरी 3, 1998

पर अधिक आधारित है । रक्षा मद पर बजट के 30 प्रतिशत से अधिक (जी.डी.पी. का लगभग 7 प्रतिशत) एवं ऋणों का व्याज चुकाने में 25 प्रतिशत व्यय हो जाता है । पाकिस्तान का कुल जी.डी.पी. लगभग 50 बिलियन डालर है जिसमें 36 अरब डालर ऋण है जो कि जी.डी.पी. का 72 प्रतिशत है ।

28 एवं 30 मई 1998 को चगाई में परमाणु विस्फोटो के बाद पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंस गई है । दोनों ही देशों की अर्थ व्यवस्थाएं कमजोर हैं, इसलिए पारस्परिक सहयोग की व्यापक संभावनाओं का दोहन अनिवार्य सा हो गया है ।

सार्क के अन्तर्गत द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग : 1985 से ही दोनों देशों को इसका अवसर मिलता रहा है । लोगों के जीवन स्तर में उन्नयन एवं विकास के मूल उद्देश्य को लेकर स्थापित किया गया सार्क सन् 2001 तक दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) की ओर बढ़ रहा है । दक्षिण एशिया वरीता व्यापार व्यवस्था (साप्टा) 8 दिसम्बर 1996 के बाद अस्तित्व में आयी तथा इसके बाद साप्ता तृतीय पर वार्तायें सम्पन्न हो चुकी हैं । साप्टा द्वितीय के अन्तर्गत बांग्लादेश ने कुल 272 वस्तुओं पर प्रशुल्कों में छूट की पेशकश की है जिन में पाकिस्तान को 13 वस्तुओं पर छूट शामिल है । इस छूट की मात्रा 10 प्रतिशत होगी । पाकिस्तान ने 386 वस्तुओं पर प्रशुल्कों में छूट दी है जिसमें बांग्लादेश को 26 वस्तुओं पर छूट दी गई है । ये ऐसी वस्तुएं हैं जो न्यूनतम विकसित देशों के लिए हैं ।

किन्तु साप्टा प्रथम एवं द्वितीय के अंतर्गत प्रस्तावित छूटें ऐसे उत्पादों पर दी गई है जिनका दक्षिण एशिया के व्यापार में अधिक महत्व नहीं है । बांग्लादेश एवं पाकिस्तान दोनों ही एक दूसरे की वस्तुओं पर, जिनका द्विपक्षीय व्यापार में महत्व है, शून्य-प्रशुल्क व्यवस्था कर के

व्यापार का आकार बढ़ा सकते हैं । पाकिस्तान से अपने व्यापार घाटे की पूर्ति के लिए शेख हसीना ने 17 जनवरी 1998 को ढाका में नवाज़ शरीफ से वार्ता के दौरान पाकिस्तान से `शून्य - प्रशुल्क व्यवस्था` की मांग की ।[16]

उपक्षेत्रीय सहयोग

1996 में सत्ता में आने के बाद बांग्लादेशी प्रधान मंत्री शेख हसीना एवं भारत की तत्कालीन संयुक्त मोर्चा सरकार के बीच समझ विकसित होने से `उपक्षेत्रीय सहयोग` की संकल्पना ने जोर पकड़ा । भारत पाकिस्तान के बीच तनाव एवं अन्य कारणों से सार्क के अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाने तथा साप्टा एवं साफ्टा की ओर धीमी प्रगति आदि कारकों ने सार्क के अन्तर्गत ही भौगोलिक दृष्टि से समीपस्थ देशों के बीच उपक्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता प्रतिपादित की । इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों, जिनमें मुख्यत: जलविद्युत परियोजनाएं स्थापित करने की व्यापक संभावनाएं शामिल हैं, का संयुक्त रूप से अनुकूलतम उपयोग करने एवं व्यापार के मार्ग में बाधाओं की समाप्ति की कार्ययोजना रखी गई है ।

मुख्य प्रगति भारत के उत्तरी-पूर्वी राज्यों एवं प. बंगाल, बांग्लादेश, भूटान एवं नेपाल के बीच जलविद्युत परियोजनाओं के विकास एवं संयुक्त उद्योगों की स्थापना हेतु उपक्षेत्रीय सहयोग व्यवस्था निर्धारित करने पर हुई है । इसे `दक्षिण एशिया विकास चतुर्भुज` का नाम भी दिया गया है । भारत, श्रीलंका एवं मालदीव के बीच भी ऐसी ही व्यवस्था स्थापित हो सकती है।

पाकिस्तान ने उपक्षेत्रीय सहयोग की अवधारणा को भारतद्वारा सार्क के अन्तर्गत पाकिस्तान को अलग-थलग करने की नीति बताते हुए

---

16. दि हिन्दू, नई दिल्ली, जनवरी 19, 1998

इसका विरोध किया । पाकिस्तान का तर्क है कि यह सार्क-चार्टर के विरुद्ध है तथा इससे भारतीय वर्चस्ववाद की झलक मिलती है । बांग्लादेश में विपक्ष की नेता बेगम खालिदा जिया ने इसका विरोध करते हुए इसे 'सार्क' के विघटन एवं भारतीय विस्तारवाद की स्थापना' से प्रेरित बताया ।'[17]

पाकिस्तान ने ऐसे तत्वों को हवा दी तथा बांग्लादेश से भी इस मुद्दे पर असहमति प्रकट की । कुछ मतों के अनुसार बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान के बाजार भारत की वृहद् अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत उसकी वस्तुओं से पट जायेंगे तथा इन देशों में औद्योगीकरण को बढ़ावा नहीं मिलेगा ।

उल्लेखनीय है कि 'उपक्षेत्रीय सहयोग' की प्रगति से बांग्ला देश के पाकिस्तान के साथ आर्थिक सम्बन्धों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है ।[18] किन्तु इन आशंकाओं को झुठलाते हुए शेख हसीना ने जनवरी 1998 में ढाका में भारत-पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के त्रिपक्षीय वाणिज्यिक शिखर सम्मेलन में सहयोग के 'उपक्षेत्रीय आधार' का महत्व प्रतिपादित किया ।[19]

15-16 जनवरी 1948 में ढाका में आयोजित त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में पहली बार तीनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने सहयोग, संयुक्त उद्यमों, व्यापार में वृद्धि आदि पर बातचीत की तथा राजनीतिक विषयों को अलग रखा गया । इसमें 170 से अधिक उद्योगपतियों एवं व्यवसायियों ने भी भाग लिया तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने पर वार्ताएँ कीं ।

---

17. दि बांग्लादेश ऑब्जर्वर, ढाका, जनवरी 8, 1997
18. जगलुल हैदर, 'साउथ एशिया सब्रीजनल ग्रुपिंग : ए थ्रेट टू दि सिक्योरिटी ऑफ बांग्लादेश', रीजनल स्टडीज़, इस्लामाबाद, वॉ. 15, नं० 3, समर, 1997, पृ० 36
19. दि हिन्दू, नई दिल्ली, जनवरी 19, 1998

तीनों देशों के शासनाध्यक्षों ने व्यापार एवं पारगमन की बाधाओं के निराकरण के उद्देश्य से `एशियन हाइवे ` के निर्माण किये जाने तथा किसी देश विशेष के ऊर्जा-आधिक्य को दूसरे देश में प्रयोग हेतु उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से `साउथ एशियनपावर ग्रिड` की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया । इन प्रस्तावों पर प्रगति होने एवं इनके कार्यरूप में आने की स्थिति में बांग्लादेश को पाकिस्तान से भारत की भूमि के रास्ते व्यापार करने एवं पाइप लाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस आपूर्ति का अवसर मिल सकता है ।

सम्मेलन के अंत में 15 सूत्री घोषणा में तीव्र वृद्धि दर द्वारा गरीबी उन्मूलन पर बल दिया गया । निवेशसंवर्द्धन एवं संरक्षण, दोहरे कराधान से बचाव, वाणिज्यिक विवादों के निस्तारण हेतु प्रक्रियाओं के निर्धारण तथा सन् 2001 तक मुक्त व्यापार व्यवस्था लाने पर सहमति हुई । इस हेतु तटकरों में क्रमिक कमी, मात्रात्मक प्रतिबन्धों एवं गैर तटकर बाधाओं को हटाने पर बल दिया गया । न्यूनतम विकसित देशों को, बिना प्रतिदाय के, उनकी विकास प्रक्रिया में मदद एवं विशिष्ट व्यापार रियायतें देने पर भी सहमति हुई ।[20] इन उपायों की सफलता के लिए पारस्परिक विश्वास की स्थापना जरूरी है ।

---

20. एशियन रिकॉर्डर, फ़रवरी 19-25, 1998, पृ0 27101

अध्याय : पंचम

बांग्लादेश - पाकिस्तान सम्बन्ध : निष्कर्ष

भारतीय उपमहाद्वीप की विशिष्ट परिस्थितियों में बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के द्विपक्षीय सम्बन्धों का ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक दृष्टि से किया गया विवेचन कुछ प्रचलित प्रस्थापनाओं का खण्डन एवं उनके द्विपक्षीय सम्बन्धों की भावी दिशा को इंगित करता है ।

इस्लाम आधारित विचारधारा एवं भ्रातृत्व पर दोनों के वृहद् राष्ट्रीय हितों एवं राजनीतिक यथार्थ ने हमेशा वरीयता प्राप्त की । पाकिस्तान के निर्माण, संयुक्त पाकिस्तान में बंगाली आन्दोलन एवं बांग्लादेश के निर्माण, बांग्लादेश द्वारा इस्लामी देशों एवं पाकिस्तान से निकट सम्बन्धों की स्थापना हेतु प्रयास, 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दिये जाने पर बांग्लादेशी सैनिक सरकार की चुप्पी आदि समस्त परिघटनायें सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की धर्म पर वरीयता का सूचक है ।

दोनों देशों ने `मुस्लिम-उम्मा` का समर्थन किया है क्योंकि वहां उनके द्विपक्षीय सम्बन्धों में टकराव नहीं है किन्तु मुस्लिम भ्रातृत्व की यह भावना `बिहारियों` की पुनर्वापसी के प्रश्न पर दिखाई नहीं देती क्योंकि वहां पाकिस्तानी अभिजन के लिए आंतरिक राजनीतिक बाध्यताएं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं एवं किसी भी देश में शासक वर्ग इन बाध्यताओं का उल्लंघन करने की स्थिति में नहीं होता । यहां तक कि इस्लामी अरब देशों के शेखों ने भी लोकतंत्र एवं धर्म निरपेक्षता पर आधारित बांग्लादेश की विदेश नीति का समर्थन नहीं किया क्योंकि इससे उनके `बंद समाजों एवं सामन्ती व्यवस्था` के प्रति असंतोष के स्वर उठने की आशंका थी ।

बांग्लादेश एवं पाकिस्तान का भारत विरोध भी धार्मिक एकता के आधार पर न होकर भारत से द्विपक्षीय विवादों से उपजे तनाव से प्रेरित रहा है ताकि भारत से `राजनीतिक सौदेबाजी` की जा सके । बांग्लादेश एवं पाकिस्तान दोनों ऐसी उप-व्यवस्था के भाग हैं

जिसकी केन्द्रीय शक्ति भारत है । एक विशाल देश के छोटे-छोटे पड़ोसियों को असुरक्षा बोध होना स्वाभाविक है, चाहे वह `वास्तविक` हो या `कल्पित` । ऐसी स्थिति में भारत से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वह वर्चस्ववादी प्रवृत्ति के संकेत न दे ।

उत्तर-मुजीब काल में बांग्लादेश की विदेश नीति का एक प्रमुख लक्ष्य भारत पर अत्यधिक निर्भरता को समाप्त करना था जिससे उसका झुकाव पाकिस्तान-चीन एवं अमेरिका की ओर अधिक हुआ । पाकिस्तान एवं चीन भी `भारत के घेराव` की नीति के तहत म्यांमार एवं बांग्लादेश से घनिष्ठ सम्बन्ध बनाने को प्रयासरत हैं तथा इसी के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में आई. एस. आई . की भारत विरोधी गतिविधियां सक्रिय रही हैं । किन्तु लोकतंत्र की स्थापना और विशेष रूप से 1996 में अवामी लीग सरकार के सत्ता में आने से पुन: संतुलन की स्थिति आ गई । खालिदा जिया द्वारा गंगा-जल-बंटवारे की सन्धि को `भारत के समक्ष समर्पण ` कहना आंतरिक राजनीति से प्रेरित है क्योंकि अपने कार्यकाल के दौरान वे स्वयं भारत के साथ मोटे तौर पर इसी प्रकार की सन्धि करने को प्रयासरत थीं ।

बांग्लादेश एवं पाकिस्तान आर्थिक क्षेत्र में अधिकाधिक सहयोग कर सकें, इसकेलिए भारत की सकारात्मक भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है ।

आपसी विवादों के चलते दक्षिण एशियाई देशों के बीच `असहयोग की कीमतें ` बहुत अधिक होती जा रही हैं । अक्षत प्राकृतिक संसाधनों, विशाल मानव संसाधन एवं वृहद् बाजार के महत्व की पहचान तथा उसके अनुकूलतम उपयोग हेतु समन्वित प्रयासों की जरूरत है ताकि इस क्षेत्र को समृद्ध बनाया जा सके ।

शेख हसीना द्वारा दक्षिण एशियाई देशों के भविष्य को आर्थिक विषय सूची की वास्तविकताओं के साथ जोड़ना (त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन

के अवसर पर) इसी यथार्थ बोध को संकेतित करता है । व्यापार, उद्योग, आधारभूत ढाँचे एवं ऊर्जा के क्षेत्र में शीघ्र एवं गहन सहयोग की आवश्यकता है । यह उद्देश्य 'सार्क' के अन्तर्गत मुक्त व्यापार क्षेत्र कायम करके तथा उपक्षेपीय एवं द्विपक्षीय सहयोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देकर ही हासिल किया जा सकता है । साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि आकार, विकास के स्तर एवं सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं की विविधता के कारण ऐसे साधनों एवं रक्षोपायों की व्यवस्था की जाये, जिससे सब के सामान्य हितों की संवृद्धि हो ।

विशेष रूप से बांग्ला देश एवं पाकिस्तान के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि इनकी अर्थ व्यवस्थाओं का आकार छोटा है एवं दक्षिण एशिया के समन्वित विकास में इन दोनों का हित निहित है ।

पाकिस्तान एवं भारत के बीच आर्थिक सम्बन्ध सीमित होने के कारण बांग्लादेश का महत्व और बढ़ जाता है । पाकिस्तान रक्षा पर बजट का भारी हिस्सा व्यय करता है जो 1947 के बाद से 30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत के बीच रहा । दूसरी ओर बांग्लादेश विकासोन्मुख कार्यों में निवेश को बढ़ा रहा है ।

चगाई में परमाणु विस्फोट करने के बाद पाकिस्तान पर लगे आर्थिक प्रतिबन्धों से वह 'दिवालिया' होने के कगार पर है । यहां तक कि निजीकरण आयोग को प्रधान मंत्री सचिवालय को बेचने के लिए निविदायें जारी करनी पड़ी हैं । विदेशी कर्ज पर अत्यधिक निर्भरता की स्थिति में कर्जों की स्वीकृति रुकते ही विदेशी मुद्रा का संकट पैदा हो गया है । आर्थिक आपातकाल लगाये जाने तथा बैंक खातों से विदेशी मुद्रा की निकासी रोकने से भी विदेशी मुद्रा की आवक रुक गई है । अर्थव्यवस्था को विनाश के गर्त में जाने से रोकने के लिए पाकिस्तान को दक्षिण एशियाई देशों के सहयोग की आवश्यकता है और भारत से

मौजूदा तनावों के चलते, बांग्लादेश ही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ।

परमाणु विस्फोटों के बाद लगे कठोर प्रतिबन्धों ने प्रतिपादित किया है कि शक्तिशाली राष्ट्रों की नीतियां अपने दूरगामी राजनीतिक हितों से निर्धारित होती हैं तथा प्रतिबन्ध हटाने में भी इन्हीं हितों की केन्द्रीय भूमिका होगी । सहायता एवं रियायतों के पीछे यही राजनीतिक गणित रहता है । भारत भी ऐसे ही आर्थिक प्रतिबन्धों का सामना कर रहा है, इसलिए 'साफ्टा' को तेजी से कार्य रूप में लाने के प्रयासों की उम्मीद है । इसी संदर्भ में बांग्लादेशी प्रधान मंत्री हसीना ने 'सक्रियतावादी' रुख का परिचय देते हुए भारत एवं पाकिस्तान की यात्रा की ।

बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के समक्ष अन्य महत्वपूर्ण सामान्य उद्देश्य भी हैं जो उन को नजदीक लाते हैं । इनमें राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिरता में बाधक जातीय संघर्षों का समाधान, स्वपोषित विकास, सैनिक तंत्र के वर्चस्व का न्यूनीकरण आदि शामिल हैं । इन सम्बन्धों में 'एक का लाभ दूसरे की हानि' की स्थिति नहीं आती ।

नवाज़ शरीफ़ एवं शेख हसीना की वर्तमान सरकारों का दृष्टिकोण सकारात्मक है जिसमें एक दूसरे की आंतरिक राजनीतिक बाध्यताओं की समझ तथा राजनीति को आर्थिक सहयोग में बाधक नहीं बनने देने हेतु सहमति है । दोनों सरकारें अपने व्यापक जनसमर्थन का लाभ उठाकर इस हेतु द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर साहसिक कदम उठा सकती हैं ।

बांग्लादेश-पाकिस्तान एवं भारत तीनों विकासशील देश हैं एवं पारस्परिक अन्तर्निर्भरता तथा सांस्कृतिक निकटता का लाभ उठा कर अपने संयुक्त प्रयासों से दक्षिण एशिया क्षेत्र के समग्र विकास को नई दिशा दे सकते हैं ।

परिशिष्ट

(प्रो. वीरेन्द्र नारायण से 8 मार्च 1998 को जयपुर में की गई भेंटवार्ता का संकलन । सेवा- निवृत्ति से पूर्व प्रो. वीरेन्द्र नारायण दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र, राजस्थान विश्व-विद्यालय, जयपुर (राजस्थान) में बांग्लादेश मामलों के विशेषज्ञ रहे हैं ।)

बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के द्विपक्षीय सम्बन्धों के स्वरूप के बारे में आपके क्या विचार हैं ?

- बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के द्विपक्षीय सम्बन्धों का दक्षिण एशिया के संदर्भ में काफी महत्व है । यद्यपि आकार एवं प्रभाव की सीमाओं के कारण विश्व मामलों में इनके सम्बन्धों का महत्व सीमित है ।

ऐसा कोई बड़ा विवाद नहीं है जो द्विपक्षीय हितों के संवर्द्धन में बाधक बना रहे, किन्तु एक-दूसरे से 1600 कि. मी. दूर स्थित होने एवं भारतीय भू-भाग से बांग्लादेश के तीन ओर से घिरे होने के कारण `इंडिया फेक्टर` अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है ।

बांग्लादेश में अवामी लीग की वर्तमान सरकार का यथार्थबोध इस मामले मे अन्य सरकारों से बेहतर है कि भारत से तनाव उसके हितों की दृष्टि से फायदेमन्द नहीं हो सकते । इसलिए दोनों देशों से अच्छे सम्बन्धों पर बल दिया जा रहा है ।

भारत विरोध के आधार पर गोलबंदी की प्रवृत्ति कम हो रही है ।

o बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के सम्बन्धों के निर्धारण में आपकी दृष्टि में भारत की क्या भूमिका रही है एवं क्या इसमें बदलाव आ रहा है ?

पाकिस्तान का निर्माण ही इस्लाम को `राष्ट्रीयता` मानकर किया गया । इससे उपजे `पहचान के संकट` का समाधान उसने `भारत-विरोध` में पाया । लेकिन पूर्वी बंगाल पर किये गये अत्याचारों एवं बांग्लादेश के निर्माण से `धार्मिक-राष्ट्रीयता` का यह मिथक टूट गया । मुजीब के शासन काल में बांग्लादेश में भारत-समर्थक वर्ग काफी बड़ा था किन्तु बांग्लादेश की भारत पर ज्यादा निर्भरता की आशंकाओं एवं सैनिक विद्रोह ने भारत विरोधी तत्वों को बढ़ावा दिया ।

इस प्रकार दोनों ही देशों की आंतरिक राजनीति में `इंडिया-फैक्टर` महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । दोनों देशों में सैनिक सरकारें `भारत विरोध` आधार पर सत्ता में आईं तथा अपने अस्तित्व के लिए इस नीति को जारी रखा । कुछ हद तक यह `छोटे राज्य की असुरक्षाजन्य मनोवृत्ति` का भी सूचक है जिसे अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता । 1980 के दशक में तो दोनों देशों के कुछ वर्गों ने बांग्लादेश एवं पाकिस्तान का परिसंघ बनाने की मांग की । स्वाभाविक है कि इस तरह के किसी भी परिसंघ का स्वरूप कथित इस्लामी एकता या भारत के विरोध में ही होता । यद्यपि भारत में भी लोहियावादी भारत-पाकिस्तान-बांग्लादेश का परिसंघ बनाने की मांग करते रहे हैं किन्तु यह किसी सुरक्षात्मक आशंका की बजाय उपमहाद्वीप की एकता एवं भ्रातृत्व भावना से प्रेरित है ।

भारत की भूमिका सम्बन्धी सकारात्मक पक्ष यह हो सकता है कि इस क्षेत्र की गरीबी, बेरोजगारी एवं पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ये दोनों देश भारत के साथ मिल कर कार्य करें, उसके व्यापक अनुभव एवं तकनीकों का लाभ उठायें ।

o वर्तमान में बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के बीच सहयोग के कौन-कौन से प्रमुख क्षेत्र हो सकते हैं ?

सहयोग के लिए सर्वाधिक महत्व आर्थिक क्षेत्र का है । दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश में वृद्धि हेतु सार्क के मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं । बांग्लादेश अपने यहां से जूट, गारमेंट्स, मछली आदि उत्पादों का मध्य एशियाई गणराज्यों को निर्यात करने के लिए पाकिस्तान के रास्ते का लाभ उठा सकता है । मध्य एशियाई गणराज्यों में रेडीमेड गारमेंट्स की बहुत मांग है एवं बांग्लादेश वहां अपना स्थायी बाजार बना सकता है । समुद्री मार्ग बहुत लम्बा होने की वजह से वहां भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका उभर कर आती है । बेहतर यह होगा कि सार्क के देश व्यापार एवं वस्तुओं के प्रवाह को तटकरों एवं अन्य अवरोधों से मुक्त करें ताकि इस तरह की समस्याएं न आयें ।

'मानव-तस्करी' एवं मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए भी संयुक्त प्रयासों की जरूरत है । बांग्लादेश से बच्चे एवं महिलाएं नेपाल तथा पंजाब में अमृतसर होते हुए तथा बम्बई के रास्ते पाकिस्तान भेजे जाते हैं । वहां से इन बच्चों को अरब देशों में भेज दिया जाता है जहां ऊंट दौड़ों में 'जॉकी' के रूप में इनका इस्तेमाल होता है । महिलाओं से वेश्यावृत्ति करवायी जाती है।

० ऐसे कौन से विवाद या मुद्दे हैं जो बांग्लादेश-पाकिस्तान के घनिष्ठ सम्बन्धों में बाधक है ?

एक प्रकार से सब से बड़ी बाधा `इतिहास की विरासतें ` हैं । `बिहारियों`तथा ` परिसम्पत्तियों ` सम्बन्धी विवादों का प्रभाव मूलत: सरकारी स्तर पर अधिक पड़ता है किन्तु 1970 से पूर्व पाकिस्तान द्वारा किये गये शोषण एवं 1970-71 के अत्याचारों की जो कटु स्मृतियां बांग्लादेशी अवाम के मनस् में हैं, वे दोनों देशों में विश्वास-निर्माण में प्रमुख बाधाएं हैं । बिहारियों का सिंध में अभाव पी.पी.पी. समर्थकों के हित में नहीं है)

इसी से जुड़ा मुद्दा उन पूर्व फौजी अफसरों पर मुकदमा चलाने का है जो शेख मुजीब की हत्या के षड्यन्त्र में शामिल थे, फिर उन्होंने सत्तासुख भोगा किन्तु शेख हसीना की सरकार बनते ही `अभियोग` के डर से देश छोड़ कर पश्चिमी देशों एवं कुछ पाकिस्तान भाग गये । बांग्लादेशी सरकार इनके प्रत्यावर्तन की मांग कर रही है, जबकि पाकिस्तान सरकार ने ऐसे किसी पूर्व सैनिक अफसर की पाकिस्तान में उपस्थिति से इन्कार किया है ।

-

संदर्भ-ग्रन्थ सूची

अयूब, मोहम्मद एण्ड सुब्रह्मण्यम : लिबरेशन वार,
न्यू देहली, एस. चाँद एंड कं० (प्रा.) लि०, 1972

अयूब मोहम्मद के. : दि फ्रेन्ड्स नाट मास्टर्स,
लाहौर, आक्सफोर्ड युनि० प्रेस, 1967

अहमद, बोहरानुद्दीन : दि जनरल्स आफ पाकिस्तान एण्ड बांग्लादेश,
नई दिल्ली, विकास पब्लिशिंग हाउस, 1993

अहमद, मुजफ्फर एंड कलाम, अबुल(संपा.) : बांग्लादेश फारेन रिलेशन्स,
ढाका: युनिवर्सिटी प्रेस लि०, 1989

अहमद, एमाजुद्दीन (संपा.) : फॉरेन पॉलिसी ऑफ बांग्लादेश : अ स्मॉल स्टेट इम्पीरेटिव,
ढाका : यूनि. प्रेस लि., 1984

अहमद, मौदूद : बांग्लादेश : कॉन्स्टीट्यूशनल क्वेस्ट फार ऑटोनामी - 1950-1960
ढाका : यूनि. प्रेस लि., 1979

आजाद, मौलाना अबुल कलाम : इण्डिया विन्स फ्रीडम : एन आटो-बायोग्राफिकल नैरेटिव
बाम्बे ।

इफ्तेखारुज्जमन एंड अहमद, इम्तियाज (संपा.) : बांग्लादेश एण्ड सार्क इश्युज, पर्सपेक्टिव्स एण्ड आउटलुक
ढाका : एकेडमिक पब्लिशर्स, 1992

ओ` डोनेल, पीटर सी. : बांग्लादेश : बायोग्राफी ऑव अ मुस्लिम नेशन, बाउल्डर, कालोराडो, वेस्ट व्यू प्रेस, 1982

कबीर, एम. जी. एंड शोकत हसन (संपा.) : इश्यूज एण्ड चैलेन्जेस फेसिंग बांग्लादेश फॉरेन पॉलिसी, ढाका, बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑव डेवलेपमेंट स्टडीज, 1989

कोचनेक, स्टेनली ए. : पैट्रन-क्लाइंट पॉलिटिक्स एण्ड बिज़नेस इन बांग्लादेश, नई दिल्ली, सेज पब्लिकेशन्स, 1993

खान, असगर अली : डिस्कवरी ऑफ् बांग्लादेश, ढाका, युनि. प्रेस लि., 1996

चक्रवर्ती, एस. आर. एंड वीरेन्द्र नरायण (संपा.) : बांग्लादेश : वॉल्यूम टू, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, दिल्ली,साउथ एशियन पब्लिशर्स, 1986

,, ,, : बांग्लादेश : वाल्यूम थ्री, ग्लोबल पॉलिटिक्स 1988

चक्रवर्ती, एस. आर. : बांग्लादेश अण्डर मुजीब , जिया एण्ड इरशाद, नई दिल्ली, हर आनन्द पब्लिकेशन्स, 1995

,, ,, (संपा.) : फॉरेन पालिसी ऑव बांग्लादेश नई दिल्ली,हर आनन्द पब्लिकेशन्स, 1994

,, ,, (संपा.) : सोसाइटी, पॉलिटी एण्ड इकॉनोमी ऑफ बांग्लादेश नई दिल्ली, हर आनन्द पब्लिकेशन्स, 1994

चौधरी, गुलाम डब्ल्यु. : पाकिस्तान ट्रान्जिशन फ्रॉम मिलिट्री टू सिविलीजेशन रूल, इक्सेक्स, 1984

चौधरी, जी. डब्ल्यु. : इंडिया, पाकिस्तान एण्ड मेजर पावर्स: पॉलिटिक्स ऑव ए डिवाइडेड सबकॉन्टिनेंट, न्यूयॉर्क, फ्री प्रेस, 1975

,, ,, : दि लास्ट डेज ऑव युनाइटेड पाकिस्तान, लन्दन, सी. हर्स्ट एण्ड कं0, 1974

चौधरी, दिलारा : बांग्लादेश एण्ड साउथ एशियन इंटरनेशनल सिस्टम, ढाका, एकेडमिक पब्लिशर्स, 1992

जलाल, आयशा : डेमोक्रेसी एण्ड ऑथोरीटेरीयनिज्म इन साउथ एशिया, कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रेस, 1995

,, ,, : दि स्टेट ऑफ मार्शल रूल : दि ओरिजन ऑफ पाकिस्तान्स पॉलीटिकल इकॉनोमी ऑफ डिफेन्स, कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रेस, 1992

जहां, रौनक : पाकिस्तान : द फेल्योर ऑव नेशनल इन्टीग्रेशन न्यूयॉर्क, कोलम्बिया युनि. प्रेस, 1972

,, ,, : बांग्लादेश पॉलिटिक्स, प्रॉब्लम्स एण्ड इश्यूज, ढाका, युनि. प्रेस, लि. 1986

जिरिंग, लारेन्स : बांग्लादेश फ्रॉम मुजीब टू इरशाद : एन इन्टरप्रेटेटीव स्टडी, कराची, आक्सफोर्ड युनि. प्रेस, 1992

जिरिंग लारेन्स (संपा.) : दि सब कान्टिमेन्ट वर्ल्ड पॉलिटिक्स: इंडियाज़ नेबर्स एण्ड दि ग्रेट पावर्स, न्यूयॉर्क, फ्रेजर, 1982

जैकसन, राबर्ट : साउथ एशियन क्राइसिस..., लन्दन, चेट्टो एण्ड विन्डस, 1975

जैन, जे. पी. : चाइना, पाकिस्तान एण्ड बांग्लादेश, नई दिल्ली, 1974

,, ,, : सोवियत पॉलिसी टवर्ड्स पाकिस्तान एण्ड बांग्लादेश, नई दिल्ली, रैडियन्ट पब्लिशर्स, 1981

तालुकदार, मुनिरुज्जमां : दि बांग्लादेश रिवोल्यूशन एण्ड इट्स आफ्टरमाथ, ढाका, यूनि. प्रेस लि. 1980

नारायण, वीरेन्द्र : फॉरेन पॉलिसी ऑव बांग्लादेश : द कान्टेक्स्ट ऑव नेशनल लिबरेशन मूवमेंट, जयपुर आलेख पब्लिशर्स, 1987

नियाजी, जमीर : जुल्फिकार अली भुट्टो एण्ड पाकिस्तान, न्यूयार्क युनि. प्रेस, 1986

पामर, नार्मन डी. : साउथ एशिया एण्ड यूनाइटेड स्टेट्स पॉलिसी, न्यूयॉर्क, हाटन मिफिन, 1966

प्रसाद, बिशेश्वर : दि फाउण्डेशन ऑव इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, 1960-1982 नई दिल्ली, रणजीत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स, 1978

फर्नान्डा, मार्कस : बांग्लादेश : दि फर्स्ट डेकेड, न्यू देहली, साउथ एशियन पब्लिशर्स, 1982

बर्की, एस. एम. : मैनरिफ्रंग ऑव इण्डियन एण्ड पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसीज़, मीनियोपालीस, युनिवर्सिटी आवॅ. प्रेस, 1974

बानू यू. ए. बी. रजिया अख्तर : इस्लाम इन बांग्लादेश, लीडेन, इ. जे. ब्रिल, 1992

बाक्सट्र, क्रेग : गवर्नमेंट एण्ड पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया कोलोराडो, वेस्ट व्यू प्रेस, 1987

ब्राउन नार्मन : दि युनाइटेड स्टेट्स एण्ड इंडिया, पाकिस्तान एण्ड बांग्लादेश, कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स, हार्वर्ड युनि. प्रेस, 1972

बाक्सट्र क्रेग : बांग्लादेश : अ न्यू नेशन इन एन ओल्ड सेटिंग, बोल्डर, कोलोराडो, वेस्ट व्यू प्रेस, 1984

बिस्वास, सुकुमार और हिरोशी सातो : रीलिजन एण्ड पॉलिटिक्स इन बांग्लादेश एण्ड वेस्ट बंगाल : अ स्टडी ऑव कम्यूनल रीलेशन्स टोकियो, इंस्टीट्यूट ऑव डेवलपिंग इकॉनोमिक्स प्रेस.

भुट्टो, जेड. ए. : मिथ ऑव इंडिपेंडेन्स, लन्दन, आक्सफोर्ड युनि. प्रेस, 1969

मॉडेलस्की, जार्ज : दि नेचर ऑव फॉरेन पॉलिसी,
न्यू पार्क, प्रेजर, 1962

मानसिंह, सुरजीत : इण्डियाज सर्च फॉर पावर : इंदिरा गांधीज फॉरेन पॉलिसी 1966-1982,
कैलिफोर्निया, सेज, 1984

मिर्डल, गुन्नार : एशियन ड्रामा : एन इन्क्वायरी इन टू दि पॉवर्टी ऑव नेशन्स,
न्यू यॉर्क, पैन्थन, 1968

मिश्रा, पी. के. : इण्डिया, पाकिस्तान, नेपाल एण्ड बांग्लादेश,
नई दिल्ली, सन्दीप प्रकाशन, 1970

मुनी, एस. डी. : रेफ्युजीज एण्ड रीज़नल सिक्योरिटी इन साउथ एशिया
न्यू देहली, कोणार्क पब्लिशर्स प्रा. लि., 1996

मोमेन, नूरुल : बांग्लादेश इन दि युनाइटेड नेशन्स : अ स्टडी इन डिप्लोमेसी,
ढाका युनिवर्सिटी प्रेस, लि. 1984

राइट, डेनिस : बांग्लादेश : ओरिजीन्स एण्ड इन्डियन ओशियन्स रिलेशन्स,
(1971 - 1975)
ढाका एकेडेमिक पब्लिशर्स, 1988

रहमान, तारिक : लैंग्वेज एण्ड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान
कराची, ओ. यू. पी. 1997

राजन, एम. एस. : रीसेन्ट एस्पेक्ट ऑन इंडियाज फॉरेन पालिसी,
नई दिल्ली : कलिंगा पब्लिशर्स, 1997

रूडोल्फ, लॉयड एण्ड रूडोल्फ, सुजान एच. : दि रीज़नल इम्पेरेटिव : यू.एस. फॉरेन पॉलिसी टूवर्ड्स साउथ एशियन स्टेट्स, नई दिल्ली, कान्सेप्ट, 1980

रोसेनाउ, जेम्स, एन. : दि साइंटिफिक स्टडी ऑव फॉरेन पॉलिसी, न्यू यार्क, निकोल्स पब्लिशिंग कम्पनी ।

वुल्पर्ट, स्टैनली : स्ट्रस ऑव कन्फ्रन्टेशन इन साउथ एशिया : अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया एण्ड दि सुपर पावर्स, न्यूयार्क, ऑक्सफोर्ड युनि. प्रेस, 1984

शर्मा, श्री राम : बांग्लादेश क्राइसिस एण्ड इंडियन फॉरेन पॉलिसी, नई दिल्ली, यंग एशिया पब्लिकेशन्स 1972

सिमान, रिचर्ड एण्ड रोज, लियो : वार एण्ड सक्सेशन : पाकिस्तान इंडिया एण्ड दि क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, बर्कले, युनि. ऑफ कोलम्बिया प्रेस, 1990

सेनगुप्ता, भवानी : दि यू.एस.एस.आर. इन एशिया : एन इन्टरनेशनल स्टडी ऑव सोवियत एशिया रिलेशन्स विद अ क्रिटीक ऑव सोवियत रोल इन अफगानिस्तान, नई दिल्ली, यंग एशिया पब्लिकेशन्स, 1980

सैन, रंगलाल : पॉलिटिकल स्लीट्स इन बांग्लादेश ढाका युनि. प्रेस लि., 1986

सैय्यद, खालिद बी. : पाकिस्तान : दि फॉरमेटिव फेज़,
कराची, पाकिस्तान पब्लिशिंग हाउस,
1960

सोभन, रहमान : दि क्राइसिस ऑव एक्सटर्नल डिपेन्डेन्स :
दि पॉलिटिकल इकॉनोमी ऑव फॉरेन
ऐड टू बांग्लादेश,
ढाका, युनि. प्रेस, लि. 1982

,, ,, : बांग्लादेश : प्रॉबलम्स ऑव गवर्नेन्स,
न्यू देहली, कोणार्क पब्लिशर्स, 1993

हक, एम. शमसुल : बांग्लादेश इन इन्टरनेशनल पॉलिटिक्स -
दि डाइलेमास ऑव द वीक स्टेट्स,
ढाका, यूनि. प्रेस लि. 1993

हसनुज्मां एण्ड जे. के. रे : एन अनसर्टेन बिगिनिंग : पर्सपेक्टिव्ज़
ऑन पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी इन
बांग्लादेश,
कलकत्ता, नया प्रकाश, 1992

लेख

अब्दुस, सबर (ए. के. एम.) : 'फॉरेन पॉलिसी ऑफ बांग्लादेश : चेलन्जेज इन द नाइन्टीज,' बांग्लादेश इंस्टीट्यूट आफ इंटरनेशनल एण्ड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, 12(4), 1991, पृ0 246-291

अधिकारी, प्रकाशचन्द्र एवं बिस्वास, सिराजुद्दीन : 'पोटेंशियल गेम्स टू बांग्लादेश फॉर इम्पोर्ट ऑफ सलेक्टेड कमोडिटीज़ फ्रॉम इंडिया एण्ड पाकिस्तान : एन एनालिटिकल इन्वेस्टिगेशन' इंडिया क्वार्टरली. 47 (4) अक्तूबर-दिसम्बर 91, पृ0 63-82.

अहमद, ए. एफ. सलाउद्दीन : 'हिस्टॉरिकल एण्ड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द इमरजेन्स ऑफ बांग्लादेश 1971,' इंडो-ब्रिटिश रिव्यू, 17 (1-2) सितम्बर-दिसम्बर 1989, पृ0 159-68

अहमद, फखरुद्दीन, : 'फॉरेन पॉलिसी ऑफ बांग्लादेश ए रिव्यू ऑफ पोस्ट टू डेकेड्स' बी. आई. आई. एस. एस. जर्नल. 14 (2) 1993, पेज 171-183

एम. अब्दुल हफीज : 'बांग्लादेश-पाकिस्तान रिलेशन्स स्टिल डवलपिंग' बी.आई. आई. एस. एस. जर्नल, वाल्यूम 6, नं0 3, जुलाई 1985, पृ0 341-378

कमल, सुल्ताना : "मूव ट्वार्ड्स स्टेट रिस्पोन्सड इस्लामाइजेशन इन बांग्लादेश", साउथ एशिया बुलेटिन, 10 (2), 1990, पृ0 73-75

कोचेनेक, स्टेनली ए. : 'बांग्लादेश इन 1996' एशियन सर्वे, फरवरी 1997

चौधरी, दिलारा एवं अन्य : 'बांग्लादेश एक्सटरनल रिलेशन्स : इन ओवरव्यू," रीजनल स्टडीज, 14(4) : आटम 1996, पेज 58-79

नंदी, सुकुमार एण्ड बसु, संजीव : 'इंस्टीट्यूशन्स एण्ड इकॉनोमिक डेवलपमेंट ए कम्पेरेटेव स्टडी ऑफ पाकिस्तान एण्ड बांग्लादेश', इंडियन इकॉनोमिक जर्नल 41(2), अक्टूबर-दिसम्बर 1993 पृ0 119-127

बनर्जी, सुव्रत : 'सार्क एण्ड बांग्लादेश', वर्ल्ड फोकस, 14(7), जुलाई 1993, पृ0 18-27

रविन्द्र कुमार : 'इंडिया-पाकिस्तान एण्ड बांग्लादेश : एन आवरव्यू' 1947-1990 मैनस्ट्रीम 29(14), 26 जनवरी 91, पेज 15-24

वेद महेन्द्र : '20 ईयर्स आफ्टर मुजीब', स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, अगस्त, 1995

शेख, युनुस अली : 'फॉरेन पॉलिसी एण्ड इट्स रिफलेक्शन्स इन दि मीडिया : बांग्लादेश ड्यूरिंग दि गल्फ वॉर 1990-91'
बी. आई. आई. एस. एस जर्नल,
17(4), 1996, पृ0 663-92

सामी, सी. एम. शफी : 'पाकिस्तान-बांग्लादेश रिलेशन्स इन दि चेंजिंग इंटरनेशनल स्नदायरमेंट,'
पाकिस्तान होराइजन्स,
44(4) अक्तूबर 1991, पेज 23-30

हक, अहमद शफीकुल : 'इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म थॉट्स ऑन पॉलिटिक्स एण्ड गवर्नेंस इन बांग्लादेश,'
एशियन अफेयर्स,
28(1) फरवरी 1997, पृ 0 15-27

,, ,, : 'स्ट्रेण्डेड पाकिस्तानीज एण्ड बर्मीज मुस्लिम इन बांग्लादेश,'
जर्नल: इंस्टीट्यूट आफ मुस्लिम माइनारिटी अफेयर्स,
11 (2) जुलाई 1990, पेज 15-27

हुसैन कमाल : 'बांग्लादेश एण्ड साउथ एशिया : प्रायॉरटीज फॉर दि नाइन्टीज,
: मैन एण्ड डवलपमेंट
14(3) सितम्बर, 1992, पेज 46-48

समाचार-पत्र

खलीज़ टाइम्स, यू. ए. ई

जनसत्ता, नई दिल्ली

दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली

दि हिन्दू, नई दिल्ली

दि बांग्लादेश टाइम्स, ढाका

दि बांग्लादेश ऑब्जर्वर, ढाका

दि डेली स्टार, ढाका

दि डेली इत्तेफाक, ढाका

दि न्यू नेशन, ढाका

दि नेशन, इस्लामाबाद

दि फ्रंटियर पोस्ट, पेशावर

दि डॉन, करांची

दि न्यूज, लाहौर

पाकिस्तान टाइम्स, लाहौर

पाकिस्तान ऑब्जर्वर, कराची

फ्राइडे टाइम्स, लाहौर

दि टाइम्स आफ इंडिया, नई दिल्ली